RNI Reference No. 1328500

द रीव टाइम्स

The RIEV Times

01-15 दिसम्बर, 2018

हिमाचल,
वर्ष 1/ अंक 10/ पृष्ठ: 16
मूल्य: ₹ 25/-

www.therievtimes.com

मृदा जांच से बेहतर होगी खेती, होगा हर किसान खुशहाल : डॉ॰ एल.सी. शर्मा

आवश्यक पोषक तत्वों की कमी से मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित

रासायनिक खादों से हो रहा है नुकसान

मृदा जांच में आए सामने तथ्य

द रीव टाइम्स (हेम राज चौहान)

कृषि प्रधान देश में किसान भगवान से कम नहीं होता। किसान के पसीने से खेतों में सोना निकलता है और उससे न केवल देशवासी अपनी भूख मिटाते हैं बल्कि राष्ट्र की उन्नति और खुशहाली भी संभव हो पाती है । ऐसे में किसान जो उगाते हैं उसकी निर्भरता शत प्रतिशत उनके खेतों पर रहती है । खेतों की पैदावार हमारी आर्थिकी को तय करती है । यानि खेतों की मिट्टी यदि पोषक तत्वों से भरपूर हो तो खेतों से हम मनचाही फसलें उगा सकते हैं । यहां दीगर बात ये है कि किसानों को अभी भी खेतों की मिट्टी में पोषक तत्वों के बारे में जितनी जानकारी होनी चाहिए वो नहीं है ।

मिशन रीव के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के गांव–गांव और खेत–खेत में मृदा जांच करवाने के लक्ष्य के अंतर्गत शिमला ज़िले के विभिन्न गांवो में मृदा जांच शिविर आयोजित किए जा रहे हैं । इन शिविरों में किसानों को अपने खेतों की मिट्टी की जांच की सुविधा और अन्य जानकारियां प्रदान की जा रही है । इसी के तहत शिमला ज़िले के जुब्बल में विभिन्न गांवो में किसानों के खेतों से मृदा जांच हेतु शिविर आयोजित किये गए ।

मृदा जांच में सामने आई हक़ीकत

किसानों ने अपने खेतों एवं बागीचों की मिट्टी को जांच के लिए दिया तो रीव मृदा जांच में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। दरअसल लगातार कीटनाशकों एवं रासायनिक खादों के उपयोग के कारण मिट्टी में बहुत से अतिआवश्यक पोषक तत्वों की कमी अथवा अत्यधिकता पाई गई है। इस असंतुलन के कारण पैदावार प्रभावित हुई हैं और फसलों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । हालांकि आमतौर पर किसान तीन प्रकार के ही मृदा जांच टेस्ट करवाने के लिए कहते है जबकि इनके अलावा भी कुछ अन्य तत्वों की जांच आवश्यक होती है ।

रीव मृदा जांच लैब में ये रहे परिणाम

- **नाईट्रोजन :** नाईट्रोजन की सामान्य रेंज 277 कि.ग्रा. से 544 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर होती है । लेकिन जुब्बल के दोची, मिहाणा और राईका आदि गांवों के किसानों के खेतों एवं बागीचों की मिट्टी में नाईट्रोजन की बहुत कमी पाई गई है । कुछ किसानों के मृदा नमूनो में 119 और इससे भी कम नाईट्रोजन की मात्रा पाई गई है । साथ ही अधिकतर सैंपल में 139, 150, 140 190 आदि मात्रा पाई गई जो निर्धारित मात्रा से काफी कम है । रीव मृदा जांच विशेषज्ञों ने किसानों को इसके लिए नाईट्रोजन की 25 प्रतिशत मात्रा को बढ़ाने का परामर्श दिया है।

नाईट्रोजन क्या है :

- यह एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक छ है । इसकी खोज 1772 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डेनियल रदरफोर्ड ने की थी ।
- यह तत्व अत्यधिक मात्रा में पाया जाने वाला है तथा इसकी कमी अथवा अत्यधिकता मिट्टी की गुणवत्ता को प्रभावित करती है ।
- नाइट्रोजन के असंतुलन से पौधों का विकास प्रभावित होता है । साथ ही फलों की गुणवत्ता में भी अंतर पड़ जाता है ।
- फसलों के गहरे हरे रंग को बनाए रखने में मददगार है ।
- यह दानों के बनने में मदद करता है तथा इससे से ही पौधों या फसलों में प्रोटीन बनती है ।
- **फासफोरस :** फासफोरस की सामान्य रेंज 12.4 किलोग्राम से 22.4 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर होती है। इसमें भी किसानों की मिट्टी जांच में काफी उतार–चढ़ाव पाए गए हैं। जांच में 64–103 किलोग्राम प्रति

शेष पेज 2 पर

SOIL TEST – REPORT CARD FARMERS DETAILS-1			DETAILS-2	DETAILS-3	DETAILS-4	DETAILS-5	DETAILS-6	DETAILS-7	DETAILS-8
SN	Parameters	Results	Results	Results	Results	Results	Results	Results	Results
1	pH	6.67	6.97	5.89	6.37	6.16	6.66	6.93	6.63
2	Electrical Conductivity	0.075	0.082	0.105	0.0125	0.034	0.053	0.093	0.134
3	Organic Carbon (%)	0.6095 %	0.5496 %	0.2751 %	0.1933 %	0.3920 %	0.4670 %	0.5901%	0.6817%
4	Nitrogen	402 Kg/ha	335 Kg/ha	154Kg/ha	108 Kg/ha	219Kg/ha	261Kg/ha	380 Kg/ha	483 Kg/ha
5	Phosphorous	754.2 Kg/ha	64.8 Kg/ha	90.3 Kg/ha	103.6 Kg/ha	75.6 Kg/ha	16.2 Kg/ha	18.7Kg/ha	72.1Kg/ha
6	Potassium	65.8 Kg/ha	92.4 Kg/ha	96.3 Kg/ha	106.7 Kg/ha	107.2 Kg/ha	110.8 Kg/ha	92.7 Kg/ha	92.4 Kg/ha
7	Zinc	3.9 ppm DTPA- 1.8	6.2 ppm DTPA- 2.8	7.7ppm DTPA- 3.5	13.8ppm DTPA- 6.3	7.6ppm DTPA- 3.5	5.6ppm DTPA- 2.6	10.4ppm DTPA- 4.8	18.0PM DTPA- 8.3
8	Boron	0.236 ppm	0.823 ppm	1.334 ppm	1.562 ppm	0.500 ppm	0.02 ppm	10.324ppm	1.352ppm
9	Iron	23.25 ppm DTPA 7.47	12.70 ppm DTPA 4.08	26.17 ppm DTPA 8.41	4.0 ppm DTPA 1.30	8.93ppm DTPA 2.87	1.73 ppm DTPA 0.55	15.45 ppm DTPA 4.96	13.36 ppm DTPA 4.29
10	Manganese	164.19 mg/Kg	170.09 mg/ Kg	170.59 mg/ Kg	171.02 mg/ Kg	170.20 mg/ Kg	170.06 mg/ Kg	171.74 mg/ Kg	170.34 mg/ Kg
11	Copper	4.44ppm DTPA-1.23	13.28ppm DTPA-3.69	10.75ppm DTPA-1.98	5.55ppm DTPA-1.54	5.68ppm DTPA-1.58	13.20ppm DTPA-3.66	8.26ppm DTPA-2.29	33.51ppm DTPA-9.31
12	Sulphur	13Kg / ha	16 Kg / ha	21 Kg / ha	19 Kg / ha	23 Kg / ha	25 Kg / ha	22 Kg / ha	26 Kg / ha

Values ascertained by **Dr I P Sharma**
Ex Professor Soil Science UHF
Solan-Consultant IIRD

Tested by Ms Deepa Negi
Biotechnologist /
Trained Lab Technician IIRD

Action basedadvice by **Dr V K Sharma**
Ex Professor (Apple Science) UHF Solan
Consultant IIRD

सेब उत्पादक एच सी तांटा ने की रीव मृदा जांच की सराहना

कहा जांच के परिणाम के बाद सारी उपजाऊ ज़मीन को लाएँगे जांच हेतु

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

जुब्बल के सेब उत्पादक एच सी तांटा ने रीव जांच शिविर में भाग लिया तथा अपने खेतों की मिट्टी को जांच हेतु दी। शिविर में मिली जानकारी एवं मृदा जांच के तरीके से प्रसन्न सेब उत्पादक ने कहा कि मिशन रीव ने यह सुविधा गांव में पहुंचा कर बहुत बड़ी किसान–बागवान सेवा की है। उन्होंने शिविर में प्राप्त जानकारी को अति महत्वपूर्ण बताया और कहा कि भविष्य के लिए रीव मृदा जांच के लिए वो अपने समस्त बागीचों और खेतों की मिट्टी के सैंपल देंगे। उन्होंने कहा कि यहां बागवानों को मृदा जांच की आवश्यकता है और मृदा जांच की समयसारणी न होने के कारण उत्पादकता में भी अंतर पड़ता है। रीव मृदा जांच से अब यह सुविधा घर पर ही प्राप्त हो रही है जिसके लिए हम बागवान लाभ उठा पा रहे हैं।

मिशन रीव कृषि अधिकारी डॉ0 शशि किरण के अनुसार

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

जुब्बल के विभिन्न गांवों में लोगों से संपर्क एवं बात करने पर बहुत अच्छा अनुभव रहा। विशेषकर किसान एवं बागवान अपने खेतों एवं मृदा के परीक्षण के बारे बेहद जागरुक हैं। उन्होंने अपने खेतों की मिट्टी की जांच को लिए रीव मृदा जांच टीम के प्रयासों को सराहा है। भविष्य में भी अन्य खेतों की मृदा जांच हेतु हामी भरी है। इस प्रयास को आगे भी जारी रखा जाएगा तथा प्रत्येक किसान व बागवान के खेतों की मृदा जांच को प्रोत्साहन दिया जाएगा ।

आईआईआरडी बना अब एनएसडीसी का साझेदार

द रीव टाइम्स (हेम राज चौहान) :

कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर खोल दिए हैं । राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ साझेदारी के बाद आईआईआरडी प्रदेश के युवाओं के लिए विभिन्न स्तरों पर भिन्न–भिन्न ट्रेड में कला–कौशल प्रशिक्षण आयोजित करेगा जिसके लिए एनएसडीसी की ओर से आईआईआरडी युवाओं/ प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र जारी करेगा । पहले यह प्रक्रिया साधारण नहीं थी क्योंकि एनएसडीसी से सीधे प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कई तरह की औपचारिकताओं से होकर गुजरना पड़ता था । आईआईआरडी इसे हिमाचल में अब सरल करने के लिए प्राधिकृत है ।

प्रशिक्षण के लिए प्राधिकरण के बाद प्रदेश में युवाओं को खुलेंगे रोजगार के अवसर

आईआईआरडी ने एक और मुकाम हासिल करते हुए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानि एनएसडीसी के साथ साझेदारी कर हिमाचल प्रदेश में युवाओं के लिए

क्या है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानि एनएसडीसी :

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (National Skill Development Coporation) नितांत एक ही मूल उद्येश्य के साथ कार्य कर रही है जिसका आधार कौशल विकास है । यह एक निजी और सरकारी निकाय में कार्य करने वाली ईकाई है । विशेषकर असंगठित क्षेत्रों में एनएसडीसी का कार्य अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है । एनएसडीसी 21 से भी अधिक क्षेत्रों में सेवाएं दे रही है । एनएसडीसी उन निजी संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सहयोग करती है जो कौशल विकास के लिए समर्पित होकर कार्य कर ही है । इसी के तहत आईआईआरडी के साथ भी साझेदारी हुई है ।

कौशल विकास में आईआईआरडी :

आईआईआरडी एक लंबे समय से कौशल विकास में अपनी सेवाएं प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर देश के अन्य राज्यों में दे रहा है । विभिन्न ट्रेड एवं श्रेणियों में आईआईआरडी ने कला कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर हज़ारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए है । इसी के चलते अब एनएसडीसी ने आईआईआरडी को साझेदारी का प्रमाण पत्र दिया है ।

पेज एक का शेष

हैक्टेयर मात्रा पाई गई हैं , जो सामान्य रेंज से बहुत अधिक है।

फासफोरस क्या है : यह एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक **P** है। फासफोरस की कमी के कारण पौधों और फसलों की ऊंचाई कम होती है। और पौधे अस्वस्थ होते है।

- इसके अभाव में पौधों/फसलों की जड़ों को बहुत नुकसान हो जाता है और कभी–कभी तो ये सूख भी जाती है ।
- फसलों की पत्तियां सूखने लगती है और आकार भी छोटा हो जाता है।

पोटाशियम : पोटाशियम की सामान्य रेंज 133 किलोग्राम से 333 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर है। रीव मृदा जांच में इस तत्व की भी कमी पाई गई है। संबन्धित क्षेत्र के किसानों की मिट्टी में पोटाशियम की कमी पाई गई है। हालांकि कुछ किसानों की मृदा में इसकी पर्याप्त मात्रा है लेकिन औसत में इसकी कमी पाई गई है। जांच में अधिकतर किसानों के सैंपल में 194, 89.66,119, 95 आदि मात्रा पाई गई है जो सामान्य रेंज से कम है। कुछ किसानों के खेत की मिट्टी में पोटाशियम की सही मात्रा भी पाई गई है और कुछ में अधिक भी।

पोटाशियम क्या है : पोटाशियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक **K** है।

- यह पौधों की वृद्धि में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- इसके कारण फलों में गहरा रंग रहता है । पत्तों के वृद्धि और रंग के लिए भी यह लाभकारी है ।
- पौधों/फसलों की कोशिकाओं को मोटा कर कीटों से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है ।
- **ऑर्गेनिक कार्बन** (% में) : इसकी सामान्य रेंज 0.5% से 1% प्रतिशत होती है । रीव मृदा जांच में इसकी मात्रा भी भिन्न ही पाई गई । कुछ सैंपल में 0. 2750: प्रतिशत, 0.675%, 0.0752%, 0.003%, 0. 5901%, और इसके आस–पास के आंकड़ों में परिणाम आया है जो कि मानकों पर बहुत दुरुस्त नहीं है । इसके लिए रीव मृदा विशेषज्ञों ने 100 किलोग्राम गोबर की खाद प्रति पेड़ डालने का परामर्श दिया है ।
- pH : पीएच की सामान्य रेंज 6.5 से 7.5 होती है । जांच में यह मात्रा अधिकतर सैंपल में 5.45, 6.48, 5. 20, 5.78 पाई गई है। यह सामान्य रेंज के आसपास ही है इसके लिए मृदा जांच विशेषज्ञों ने इसमें कुछ भी सम्मिश्रित करने का परामर्श नहीं दिया।
- **जिंक :** इस तत्व की सामान्य रेंज 0.6 से 1.00 ppm होती है । सैंपल में यह 12.2 ppm DTPA-6.2, 1-7 ppm DTPA-0.8, 14.1 ppm DTPA-6.2 आदि आया है।
- **बोरोन :** इस तत्व की सामान्य रेंज 10.0 ppm है। जबकि सैंपल में जांच के दौरान यह भिन्न–भिन्न श्रेणियों में पाया गया। जैसे कि 0-764 ppm, 0.862 ppm, 0.569 ppm आदि। इसके लिए मृदा विशेषज्ञों ने बोरेक्स या बोरिक ऐसिड की 0.4 प्रतिशत से 0.5 प्रतिशत अर्थात् 40 से 50 ग्राम का घोल एक लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करने की सलाह

दी है ।
- **आयरन :** इस तत्व की सामान्य रेंज 4.5 ppm है । सैंपल में यह मात्रा मानकों से बहुत कम आंकी गई । रीव मृदा जांच में यह मात्रा 5-36 ppm DTPA 1-72, 2-30 ppm DTPA 0-73, 9-22 ppm DTPA 2-96, 13-00 ppm DTPA 4-01 आदि पाई गई है ।
- **मैगनीज़ :** इस तत्व की सामान्य रेंज 1.0 ppm होती है । जांच में यह 169-05 mg/Kg, 173-74 mg/Kg, 172.59 mg/Kg, 152.80 mg/Kg आदि पाई गई । क्योंकि पहले से ही अधिक है तो इसमें कुछ विशेष परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है ।
- **कॉपर :** इस तत्व की सामान्य रेंज 0.2 ppm है । इसमें भी जांच के दौरान कुछ भिन्नता पाई गई है । जैसे कि कुछ सैंपल में 8-27 ppm DTPA-2.30, 22.03 ppm DTPA-5.72, 5.56 ppm DTPA-1.53 आदि पाया गया। क्योंकि पहले से ही अधिक है तो इसमें कुछ विशेष परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

- **सल्फर :** इस तत्व सामान्य रेंज 22.4Kg/ha है। जांच में यह 27Kg/ha, 20Kg/ha, 28Kg/ha, 22Kg/ha आदि पाया गया जो कि सामान्य रेंज के आसपास ही है और विशेषज्ञों ने इसमें कुछ बदलाव से इंकार किया ।

ये सभी आंकड़े उन किसानों की मृदा जांच के बाद आए हैं जिन्होंने जुब्बल के विभिन्न गांवों से मृदा जांच शिविर में भाग लिया था और अपने सैंपल दिए थे ।

SOIL TEST – REPORT CARD DETAILS-9

	Parameters	Results	DETAILS-10 Results	DETAILS-11 Results	DETAILS-12 Results
1	PH	6.88	6.92	5.06	6.64
2	Electrical Conductivity	0.032	0.009	1.977	2.660
3	Organic Carbon (%)	0.6014%	0.2496%	0.5035%	0.2341%
4	Nitrogen	393 Kg/ha	139 Kg/ha	283 Kg/ha	131 Kg/ha
5	Phosphorous	13.7Kg/ha	91.2Kg/ha	20.6Kg/ha	43.6Kg/ha
6	Potassium	56.2 Kg/ha	113.1 Kg/ha	210.5 Kg/ha	117.9 Kg/ha
7	Zinc	18.2PM DTPA- 8.4	8.8PM DTPA- 4.0	13.6PM DTPA- 5.6	12.1PM DTPA- 6.6
8	Boron	3.264ppm	0.531ppm	1.609 ppm	1.426 ppm
9	Iron	2.19 ppm DTPA 0.72	26.25ppm DTPA 8.43	14.31ppm DTPA 5.03	9.02ppm DTPA 2.30
10	Manganese	155.83 mg/ Kg	162.83 mg/ Kg	160.23 mg/ Kg	163.55 mg/ Kg
11	Copper	20.58ppm DTPA-5.71	9.08ppm DTPA-2.53	10.75 ppm DTPA-1.95	5.68ppm DTPA-1.58
12	Sulphur	20 Kg / ha	21 Kg / ha	24 Kg / ha	29 Kg / ha

Values ascertained by **Dr I P Sharma** Ex Professor Soil Science UHF Solan-Consultant IIRD

Tested by **Ms Deepa Negi** Biotechnologist / Trained Lab Technician IIRD

Action basedadvice by **Dr V K Sharma** Ex Professor (Apple Science) UHF Solan Consultant IIRD

बागवानी वैज्ञानिक एवं रीव मृदा जांच विशेषज्ञ डॉ0 वी के शर्मा

रीव मृदा जांच विशेषज्ञ एवं बागवानी वैज्ञानिक डॉ0 वी के शर्मा ने कहा कि मृदा जांच में आए परिणामों के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में कमी अथवा अधिकता पाई गई है। यह इसलिए भी हो रहा है कि बागवान अधिकता में रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं जिससे मिट्टी की गुणवत्ता बुरी तरह से प्रभावित हो रही है और इसका उत्पादकता पर गहरा असर पड रहा है।

डाक्टर वीके शर्मा का कहना है कि जिस प्रकार मनुष्य एवं जानवरों को संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार फसलों के लिये भी संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। अत्यधिक एवं असंतुलित उर्वरकों तथा कृषि रसायनों के प्रयोग से खेत की मिट्टी कृषि अयोग्य हो रही है तथा उसकी उत्पादन क्षमता में परिवर्तन आ रहा है। जिन क्षेत्रों में अधिक उपज वाली उन्नत, प्रगतिशील एवं संकर किस्में उगाई जाती है वहां मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी बहुत तेजी से होती है। इसलिए भरपूर उत्पादन लेने के लिए खेत की मिट्टी में उपलब्ध तत्वों की मात्रा एवं मिट्टी का स्वास्थ्य जानने के लिए मिट्टी परीक्षण (जॉच) करना आवश्यक हो जाता है। इसी के आधार पर उर्वरको का प्रयोग करना चाहिए।

क्या कहती हैं लैब तकनीकि अधिकारी दीपा पायलॉस

मृदा जांच के लिए दूर–दराज के किसानों ने शिविर में बढ़चढ़ कर भाग लिया और उनके खेतों से जो सैंपल लैब में जांचे गए हैं उनमें जिन आवश्यक तत्वों की कमी अथवा अत्यधिकता पाई गई है, उससे किसानों को रिपोर्ट के साथ अवगत करवाया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न सीनों पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को रीव जैविक खाद के सम्मिश्रण से पूरा किया जाएगा।

मृदा परीक्षण आवश्यक क्यों ?

(1) फसलों से अधिक उपज लेने के लिये यह जानना जरूरी हो जाता है कि मिट्टी में कौन–कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं ?

(2) फसल के अनुरूप जैविक खाद, उर्वरकों की मात्रा का प्रयोग।

(3) खेत की मिट्टी कौन–कौन सी फसल के लिये उपयुक्त है।

(4) मिट्टी की अम्लीयता, क्षारीयता (पी.एच.) विद्युत चालकता का स्तर जानने के लिए।

(5) लक्षित उत्पादन प्राप्त करने एवं उर्वरकों की उपयोगिता क्षमता में वृद्धि के लिये।

(6) समस्याग्रस्त, अम्लीय, क्षारीय, ऊसर मिट्टी के सुधार हेतु।

मिट्टी का नमूना कैसे लें

1. जिस खेत में मिट्टी का नमूना लेना हो उसमें अलग– अलग से बारह बिंदुओं/जगहों का चुनाव करें।
2. चुने गये बिंदुओं/स्थानों की उपरी एक–दो सेमी. सतह साफ करके घास, पत्थर, कचरा आदि हटा दें।
3. खुरपी की सहायता से चुने गये स्थानों में V आकार का 6–8 इंच गहरा काट लगाकर मिट्टी को तसला या बाल्टी में रखते जायें।
4. खेत से लायी गई मिट्टी को साफ फर्श के ऊपर अखबार पर बिछाकर छाया में सुखा लें।
5. मिट्टी से घास, गोबर, पत्थर के टुकड़े फसल अवशेष निकालकर फेंक दें व मिट्टी को भुरभुरी बना लें।
6. मिट्टी के ढेर को लगभग 3 इंच की ऊचांई में गोलाकार रूप देकर चार बराबर भागों में बॉटकर आमने– सामने की दो भाग मिट्टी हटा दें। शेष दो भाग को मिलाकर इसे भी चार भागों में बॉटकर दो आमने– सामने के भाग अलग करें। ऐसा तब तक करें जब तक शेष दो भाग की मिट्टी (500 ग्राम) आधा किलोग्राम के लगभग हो जाये।
7. साफ थैली में शेष आधा किलोग्राम मिट्टी भरकर धागा से बांध दें।
8. दूसरी नई थैली में मिट्टी वाली थैली, जानकारी सहित नमूना पत्रक रखकर धागे से थैली को बॉध दें। अब आपका यह मिट्टी नमूना जांच के लिए तैयार है।

मिट्टी का नमूना कब लें ?

- गर्मियों में रबी फसल की कटाई के बाद से लेकर खरीफ की बुवाई के पहले तक।
- जहां लगातार पूरे वर्ष फसलें ली जाती है वहां कटाई के तुरंत बाद।
- बहुवर्षीय/खड़ी फसल में पौधों की कतार के बीच से मिट्टी का नमूना लें।

मिट्टी नमूना लेने के लिए सामग्री

खुरपी या आगर, तसला या प्लास्टिक की साफ बाल्टी, एक किग्रा. की दो साफ थैली, धागा, सादा कागज, साफ पुराना अखबार।

सावधानियां –

मिट्टी नमूना लेने के पहले निम्नलिखित सुझावों पर अवश्य ध्यान दें–

- वृक्ष और देसी खाद के ढेर के नीचे की मिट्टी न ले।
- खेत के कोनों एवं मेड़ से एक मीटर अंदर के ओर की मिट्टी न लें।
- अधिकतर समय पानी भरे रहने वाले एवं नाली के पास के स्थान से मिट्टी न लें।
- खेत की मिट्टी यदि अलग–अलग है तो नमूना की मिट्टी अलग–अलग लें।

- उर्वरक, खाद, नमक की बोरी के ऊपर मिट्टी नमूना न सुखाएं।
- खेत की मिट्टी में स्वाभाविक रूप से पाये जाने वाले कंकड़ आदि अलग न करें।
- यदि खेत की ढलान अधिक हैं और फसल अलग–अलग हैं तो मिट्टी का नमूना भी अलग–अलग लें।
- एच्छिक जानकारी नमूना पत्रक में भरकर मिट्टी के साथ अवश्य भेजें।
- अधिकतम एक हेक्टेयर क्षेत्रफल तक के खेत से एक नमूना लें।

मिशन रीव के अंतर्गत पूरे हिमाचल में रीव जैविक खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करवाई गई है। इसके प्राप्त करने लिए इन दूरभाष नंबरों पर संपर्क करें .... 9459584566 और 8219175636, साथ ही आप हमारी वेबसाइट : missionriev.in/www.iirdshimla.org पर लॉगइन कर अधिक जानकारी ले सकते हैं

पूर्ण जैविक हिमाचल की ओर बढ़ते क़दम.....रीव जैविक खाद

मृदा जांच के लिए रोहड़ू और कोटखाई में हो रहा है सर्वेक्षण

सैकड़ो लोगों तक सुविधा पहुंचाने का है लक्ष्य

द रीव टाइम्स ब्यूरो

शिमला ज़िले में किसानों को मिशन रीव की मृदा जांच खूब भा रही है और इसका लाभ लेने के लिए किसान अपने खेतों की मिट्टी की जांच हेतु आगे आ रहे हैं। अभी हाल ही में जुब्बल में किसानों ने भारी तादात में अपने खेतों की मृदा जांच के लिए मृदा जांच शिविर में भाग लिया जिसमें कई प्रकार के मृदा संबन्धि परिणाम सामने आए हैं । इसका ज़िक्र इसी अंक के प्रथम पृष्ठ पर उल्लेखित हैं। मिशन रीव अब मृदा जांच के लिए कोटखाई और रोहड़ू में किसानों के लिए एक भव्य स्तर पर मृदा जांच शिविर आयोजित करने जा रहा है । इसके लिए मिशन रीव

रीव टीम ने किसानों से की बात... घर-गांव में ही मिलेगी जांच सुविधा

टीम रोहड़ू और कोटखाई में किसानों से गांव-गांव में संपर्क कर रही है । किसानों ने इस प्रयास की सराहना की है और मृदा जांच के लिए अपना पंजीकरण करवाना शुरु कर दिया है ।

रीव क्लिनिक में अब ई सी जी की सुविधा उपलब्ध

द रीव टाइम्स ब्यूरो

आईआईआरडी स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश में बेहतरीन कार्य कर रही है। इसी के तहत शनान में रीव क्लिनिक में अब ईसीजी की सुविधा भी उपलब्ध हो गई है। रीव क्लिनिक में मरीज़ों की बढ़ती तादात को देखते हुए रीव क्लिनिक में धीरे-धीरे नए और आधुनिक उपकरणों के साथ लोगों को सुविधाऐं प्राप्त हो रही है। ईसीजी सुविधा उपलब्ध होने के बाद न केवल शनान बल्कि दूर-दूर से मरीज़ों को लाभ हो रहा है और इस टैस्ट के लिए अब इधर-उधर नहीं भटकना पड़ रहा है। अधिकतर टैस्ट अब रीव क्लिनिक में ही संभव हो गए हैं

मरीज़ों की बढ़ रही है तादात

जिससे यहां पर आने वाले मरीज़ों को एक ही जगह पर अधिकतर टेस्ट करवाने और चेकअप के बाद जनऔषधि केन्द्र से सस्ती दवाईयों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है। रीव क्लिनिक में पहुंच रहे मरीज ईसीजी की सुविधा से बहुत खुश है और इसके लिए अब कहीं अन्य अस्पतालों या लैब में धक्के नहीं खाने पड़ रहे हैं ।

क्षमता संवर्द्धन के लिए मिशन प्रतिनिधियों को दिया प्रशिक्षण

आईआईआरडी शिमला में मिशन रीव संस्करण-दो पर मंथन

द रीव टाइम्स ब्यूरो

आईआईआरडी मिशन रीव के पहले संस्करण की सफलता के बाद मिशन रीव संस्करण-2 को लोगों के सामने ला रहा है। पहले संस्करण के अनुभवों के आधार पर दूसरे संस्करण को और बेहतर ढंग से कार्यान्वित करने के लिए कई नई योजनाओं और सुविधाओं के साथ लोगों तक पहुंचने का प्रयास है। मिशन रीव संस्करण दो के तहत मिशन प्रतिनिधि गांव में लोगों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं दे सके, इसके लिए उन्हें आईआईआरडी शिमला में विशेष प्रशिक्षण दिया गया। तीन दिन तक चले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से मिशन रीव के जिला समन्वयक और सहायक जिला समन्वयकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान मिशन प्रतिनिधियों ने संस्करण एक के दौरान गांवों में सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर पेश आई चुनौतियों पर चर्चा की तो वहीं संस्करण दो में इन चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीति भी तैयार की गई। प्रशिक्षण के दौरान आईआईआरडी के प्रबंध निदेशक डाक्टर एलसी शर्मा ने मिशन प्रतिनिधियों को मिशन रीव संस्करण दो पर प्रेजेंटेशन दी और संस्करण के कार्यान्वयन के बारे में विस्तार से बताया। प्रशिक्षण तीन चरणों में आयोजित किया गया। पहले चरण में संस्करण दो की जानकारी दी गई। दूसरे चरण में मिशन प्रतिनिधियों के लिए समूह चर्चा का आयोजन किया गया ताकि मिशन को आगे ले जाने के लिए सभी अपने-अपने अनुभवों के आधार पर अपने विचार प्रस्तुत कर सके। तीसरे चरण में आवश्यकता आकलन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी दी गई तथा साथ ही मिशन रीव के सदस्यों की ओर से फील्ड में किए जा रहे कार्यों की मॉनीटरिंग के लिए तैयार विशेष सॉफटवेयर और विभिन्न प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। इस प्रशिक्षण के बाद यही मिशन प्रतिनिधि फील्ड में तैनात लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

इसके अलावा मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद नायर ने भी प्रशिक्षण के दौरान मिशन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर प्रतिनिधियों से चर्चा की तो वहीं उद्यमिता विकास कार्यक्रम अधिकारी आईआईआरडी प्रवीण मिश्रा ने कौशल विकास के बारे में जानकारी दी।

रीव जैविक खाद से पोषित हो रही किन्नौर की मिट्टी

बागवानों को मिल रहे बेहतर परिणाम

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मिशन रीव के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद किसानों द्वारा खाद को उन क्षेत्रों में भेजा जा रहा है जहां पर किन्ही कारणों से खाद की कमी रहती है या किसान-बागवान जैविक खाद का इस्तेमाल कर अधिक पैदावार करने के इच्छुक रहते हैं। हाल ही में किन्नौर के बागवानों को भी मिशन रीव के तहत जैविक खाद की आपूर्ति की गई, जिसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। दरअसल किन्नौर के अधिकतर क्षेत्र खराब मौसम के कारण प्रदेश के बाकि हिस्सों से कटे रहते हैं। किन्नौर में बगीचे तो खूब होते हैं लेकिन अधिक बर्फबारी के कारण पशुधन कम होता है और बागीचों के लिए जरूरी गोबर खाद की अक्सर कमी रहती है। मजबूरन बागवानों को रासायनिक खादों का उपयोग करना पड़ता है जिससे मृदा उपजाऊ शक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। बागवानों की इसी समस्या को दूर करने के लिए मिशन रीव के तहत किन्नौर के बागवानों को रीव जैविक खाद की आपूर्ति प्रदेश के दूसरे जिलों से की जा रही है। ये वही जैविक खाद है जो मिशन प्रतिनिधिओं से प्रशिक्षण लेने के बाद किसानों द्वारा तैयार की गई है। किन्नौर के राजमन नेगी, विवेक नेगी, जितेंद्र नेगी व अन्य बागवानों ने बताया कि किन्नौर में जैविक खाद की खपत काफी अधिक है। यहां पर व्यापक स्तर पर बागवान फलों का उत्पादन करते हैं। लेकिन यहां खाद की कमी रहती है। इसके साथ ही बागवानो को बाजार से खाद खरीद कर उसे बागीचों तक पहुंचाना भी किसी चुनौति से कम नहीं है। ऐसे में मिशन रीव किन्नौर के बागवानों को उनके घर पर ही बेहतर और गुणवत्तापूर्ण खाद मुहैया करवा रहा है। इससे यहां के बागवान काफी खुश हैं और खाद के उपयोग के भी अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। इससे किन्नौर की मिट्टी को रासायनिक खादों से भी बचाया जा रहा है। मिशन रीव के जिला समन्वयक विशाल नेगी का कहना है कि भविष्य में किन्नौर में खाद की मांग को देखते हुए बागवानों को और खाद भी मिशन रीव के तहत पहुंचाई जाएगी।

किन्नौर और लाहौल-स्पीति में जल्द होगा मृदा परीक्षण

टीम रीव किन्नौर

जिला शिमला के किसानों और बागवानों को मृदा परीक्षण की सुविधा देने के बाद अब बागवानों की मांग पर किन्नौर और लाहौल स्पीति में भी मिशन रीव के तहत जल्द मृदा परीक्षण की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए जिलों के विभिन्न क्षेत्रो में मिशन रीव की ओर से विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में बागवानों और किसानों से मिट्टी के नमूने लेकर उनकी जांच की जाएगी और उसके बाद उन्हें जांच के आधार पर विशेषज्ञों के द्वारा यह भी बताया जाएगा कि वह अपने खेतों और बागीचों में कैसे सही मात्रा में पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखकर अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में जिला शिमला के रोहड़ू और जुब्ल में भी किसानों और बागवानों के लिए मृदा जांच शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में सौ से

अधिक किसानों ने मृदा परीक्षण करवाने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद जिन बागवानों और किसानों ने मिट्टी के नमूने उपलब्ध करवाए उनकी जांच भी की गई और रिपोर्ट के बाद वह काफी संतुष्ट हुए। अब इसी आधार पर अन्य जिलों में भी यह सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

जांच के लिए मिट्टी के सैम्पल लेते मिशन रीव प्रतिनिधि

लौहाल-स्पीति में लोगों को किया जागरूक

टीम रीव, लौहाल-स्पीति

मिशन रीव लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के साथ ही उन्हें उन योजनाओं के बारे में भी जानकारी दे रहा है जो सरकार की ओर से खास तौर पर उनके

दूर -दराज के लोग भी हो रहे जागरुक

लिए बनाई गई है। इस बात को सरकारी अधिकारी भी मानतें है कि जानकारी के अभाव में अधिकतर योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक नहीं पहुंच पाता। इस खाई को पाटने के लिए लाहौल स्पीति के दूर दराज के गांवों में मिशन रीव के प्रतिनिधियों की ओर से विशेष तौर पर गांवों में जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत काजा ब्लॉक में भी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को मिशन रीव के तहत दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं, मिट्टी जांच परीक्षण व अन्य सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही काजा के लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में भी अवगत कराया गया।

पाठकों से अपील

प्रिय पाठक वर्ग

पाक्षिक विकासात्मक समाचार पत्र 'द रीव टाइम्स' का दसवां अंक आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है । आशा करता हूं कि पिछला अंक आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा होगा। द रीव टाइम्स लोगों को जीवन में प्रगतिशील बनने में कारगर सिद्ध हो, इसी उद्देश्य से आप की प्रतिक्रियाओं, आलोचनाओं, सुझावों तथा परामर्श को सादर आमंत्रित करते हैं ताकि विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने संबन्धि सभी पहलुओं का क्रमबद्ध समावेश किया जा सके ।

आनन्द नायर प्रबन्ध संपादक

पूर्ण जैविक हिमाचल की ओर बढ़ते क़दम...रीव जैविक खाद

Parameter	Percentage
PH	7-8
Organic carbon	7.36 - 9
Nitrogen	1.69 - 2
Phosphorus	0.75 - 1
Potassium	1.17 - 1.50
Sulphur	0.042 - 0.70
Zinc	0.0053 - 0.0075
Iron	0.14 - 0.30
Copper	0.0011
Calcium	2.2 - 3
Magnesium	1.03 - 1.20
Boron	0.0012
Manganese	0.0097
Calorific Value	219.96

हिमाचल को जैविक राज्य बनाने की ओर अग्रसर मिशन रीव

टीम रीव, सोलन

आईआईआरडी हिमाचल प्रदेश को जैविक राज्य बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आईआईआरडी की ओर से मिशन रीव के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में किसानों को उनके गांव–घर में ही जैविक खाद बनाने का निशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जब किसान खाद तैयार कर लेते हैं तो आईआईआरडी उसके लिए बाजार भी उपलब्ध करा रहा है। इसके चलते गांव में किसानों को अच्छी–खासी आय बिना किसी परेशानी के प्राप्त हो रही है और किसान खुशहाल हो रहे हैं। इसके साथ ही हिमाचल को जैविक खेती की ओर ले जाने में भी मदद मिल रही है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में ऐसे कई उदाहरण है जहां आईआईआरडी की ओर से मिशन रीव के तहत जैविक खाद से किसानों की आर्थिकी मजबूत हो रही है। हाल ही में जिला सोलन में अनेक किसानों का मिशन रीव के तहत जैविक खाद के तहत खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। किसानो ने खाद तैयार की और इसके बाद इस खाद की पैकिंग और खरीददारों तक इसे पहुंचाने का सारा कार्य मिशन रीव के प्रतिनिधियों द्वारा ही किया गया। इससे किसानों को परेशानी भी नहीं उठानी पड़ी और उन्हें घर बैठे आय भी प्राप्त हो गई। सोलन के किसानों से जैविक खाद खरीद कर किन्नौर और जुब्बल भेजी गई जिससे किन्नौर और जुब्बल के बागवानों और किसानों को भी खाद प्राप्त करने में आसानी हो गई।

केस स्टडी

मेरा नाम नमन ठाकुर है। मैं जिला सोलन गांव डमरोग का निवासी हूं। हमारा परिवार कृषि और पशुपालन से जुड़ा है। जैविक खेती को लेकर काफी बार सुना और पढ़ा था लेकिन जैविक खाद सही तरीके से कैसे तैयार की जाती है इसकी जानकारी नहीं थी। कुछ समय पहले मिशन रीव की ओर से गांव में जैविक खाद बनाने का निशुल्क प्रशिक्षण दिया गया। अन्य लोगों के साथ मैंने भी जैविक खाद बनाने की विधि इस कैंप में सीखी। इसके बाद जब खाद बनाने की शुरूआत की तो मिशन रीव प्रतिनिधियों की ओर से समय–समय पर उचित मार्गदर्शन किया गया। इसके बाद जब खाद बनकर तैयार हो गई तो हमने रीव प्रतिनिधियों को इसकी जानकारी दी। मिशन रीव सचिवालय से मिशन प्रतिनिधियों ने आकर खाद की पैकिंग की और यहीं से खाद उठा ली। करीब 10 हजार की अतिरिक्त आय घर बैठे प्राप्त हो गई। न तो खाद के लिए ग्राहक ढूंढने का झंझट हुआ और न खाद को बाजार तक पहुंचाने का। आईआईआरडी जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण देकर न केवल गांव के लोगों की आर्थिकी मजबूत कर रहा है बल्कि प्रदेश की मिट्टी को रासायनिक खाद के दुष्प्रभाव से बचाने के अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

योजनाओं को लोगों तक पहुंचा रहा मिशन रीव

कृषि और स्वास्थ्य के साथ अन्य सेवाएं लेना भी हुआ आसान

टीम रीव, सिरमौर

सरकार की ओर से जनकल्याण को लेकर कई योजनाएं चलाई जा रही है लेकिन जानकारी के अभाव में अक्सर योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक नहीं पहुंच पाता। जनसमाज कल्याण की राह में रोड़ा बन रही इस समस्या का निवारण करने में आईआईआरडी का मिशन रीव अहम भूमिका निभा रहा है।

प्रदेश के विभिन्न जिलों में रीव सरकार और आम जनता के बीच एक मजबूत कड़ी बनता जा रहा है। जिला सिरमौर में मिशन रीव के तहत ऐसे कई उदाहरण है। मिशन रीव सरकार और आम जनता के बीच खाई को पाटने में अहम भूमिका निभा रहा है। सरकारी योजनाओं को गांव के लोगों तक पहुंचाने में मिशन प्रतिनिधि महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। शिलाई निवासी मोती राम का कहना है कि मिशन रीव से कई सेवाएं ले चुके हैं और मिशन रीव गांवों के विकास को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

रीव घर तक पहुंचा रहा जरूरत का सामान

लोगों को दी मिशन रीव की जानकारी

टीम रीव, सिरमौर

मिशन रीव के तहत सिरमौर के पच्छाद ब्लॉक के सराहा पंचायत में लोगों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए शिविर का आयोजन किया। इसमें रोहन, नरेश, मोहन सिंह, कृपाराम, गीताराम दीपक, रंजन सिंह, मोहि राम आदि किसानों ने भाग लिया इन सभी किसानों को मिशन रीव के सदस्यों ने जैविक खाद और जैविक खेती के बारे में विस्तार से बताया। साथ में मिशन रीव सदस्यों ने मिशन रीव द्वारा दी जा रही सभी सर्विसेस के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान लोगों ने मिशन रीव को लेकर कई सवाल भी पूछे। गीताराम ने पूछा कि मिशन रीव के तहत किस तरह की सेवाएं दी जा रही है। इसके बाद सभी लोगों को मिशन के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि मिशन रीव के सदस्यों को सभी सेवाएं कम दाम पर या निशुल्क दी जाती है। इसके साथ ही गांव के किसानों को विस्तार पूर्वक जैविक खाद बनाने के तरीके के बारे में भी बताया। इसके लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इसमें सभी किसानों ने उत्सुकता पूर्वक भाग लिया। जैविक खाद तैयार होने के बाद इसको कहां बेच सकते हैं इस बारे में भी जानकारी दी गई।

मिशन रीव ने खोले रोज़गार के द्वार

अपनी ही पंचायत में काम करने का मिला मौका

टीम रीव, सिरमौर

सिरमौर ज़िले में मिशन रीव के तहत जन कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर सेवाऐं प्रदान की जा रही है। सेवाओं के साथ ही मिशन रीव ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को रोजगार देने के सबसे बड़े मिशन की ओर अग्रसर है। ज़िले के अभी तक करीब सैकड़ों ग्रामीण युवा बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ा जा चुका है तथा वे सभी ग्रामीण स्तर, खण्ड स्तर एवं ज़िला स्तर पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अभी भी यह प्रक्रिया जारी है। जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ज़िला में विभिन्न पंचायतों में जैविक खाद निर्माण का प्रशिक्षण दिया गया । इससे किसानों में रासायनिक खाद को छोड़कर जैविक खाद बनाने व उपयोग करने की प्रक्रिया को अपनाने के लिए आत्मनिर्भरता बढ़ी है। पंचायतों में फेसिलिटेटर पंचायत से संपर्क कर गांव–गांव जाकर लोगों से सीधा संपर्क साध रहे हैं और उनकी समस्याओं को जानकर उनका निवारण भी कर रहे हैं। लोगों की मांग पर कम कीमत में फूलों का बीज, मटर तथा मक्की का बीज लोगों को उनके घर पर ही प्रदान किया गया। ऑनलाइन सेवाओं के बारे में आम ग्रामीणों को निरंतर जागरुक किया जा रहा है तथा किस प्रकार ऑनलाइन बिजली के बिल, टेलि फोन एवं अन्य बिलों का भुगतान अपने मोबाइल से ही घर बैठे कर सकते हैं, इसकी जानकारी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को दी जा रही है ।

ऑनलाइन सिस्टम भी जान रहे ग्रामीण

पंचायत में ही रोजगार से खुशी

मिशन रीव से गांव में लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा जा रहा है । लोगों को उनके घरों में ही टेस्ट सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा अगर कोई बाजार से दवाईयां लाना चाहता है तो वह भी मिशन रीव के प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही है। इस सुविधा के मिलने से ग्रामीण काफी खुश है।

मिशन रीव से घर-घर पहुंच रहा जरूरत का सामान

टीम रीव, ऊना

मिशन रीव के माध्यम से लोगों को उनके घरों पर ही जरूरत का सामान उपलब्ध करवाया जा रहा है। इससे लोगों के समय और पैसे, दोनों की ही बचत हो रही है। लोगों की समस्याओं को जानने और उनका निवारण करने के लिए मिशन रीव के तहत पंचायत में तैनात प्रतिनिधियों द्वारा विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में ऊना की कुछ पंचायतों में इसी तरह के शिविर का आयोजन किया और लोगों को मिशन रीव के तहत उपलब्ध कराए जा रहे एनीमल फीड सप्लीमेंट की जानकारी दी गई। इसके साथ ही लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न तरह का सामान उनके घरों तक मिशन रीव के प्रतिनिधियों द्वारा पहुंचाया गया। इस दौरान लोगों ने पशुधन के माध्यम से आर्थिकी मजबूत करने पर चर्चा की और मिशन रीव के तहत एनीमल फीड सप्लीमेंट उपलब्ध कराने की मांग की। इसके बाद उन्हें फीड सप्लीमेंट भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिसके काफी बेहतर परिणाम सामने आ रहे है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में रोजमर्रा की जरूरत का सामान जैसे साबुन, क्रॉकरी, शैंपू आदि भी लोगों के घरों तक पहुचांया जा रहा है।

किसानों को दी जैविक खेती के लाभ की जानकारी

टीम रीव, ऊना

गांव के किसानों को पशुधन से अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके, इसके लिए मिशन रीव के तहत कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो उनके लिए काफी लाभदायक साबित हो रहा है। इसी तरह के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कुछ समय पूर्व मिशन रीव के तहत बल्ह पंचायत के गांव में परनॉलियाँ सनहाल में दिया गया था। इस दौरान मिशन प्रतिनिधियों ने किसानों को जानकारी दी कि कैसे जैविक खाद लोग खुद तैयार कर सकते हैं और कैसे रासायनिक खाद के दुष्प्रभावों से खेतों को बचाया जा सकता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रशिक्षण के बाद वह अब स्वंय जैविक खाद बना रहे हैं और अपने खेतों में इसका प्रयोग करने के साथ–साथ बिक्री करने के लिए भी खाद बना रहे हैं। स्थानीय लोगों ने मिशन रीव के इस कार्य की सराहना की

बिलासपुर में गांव-गांव तक पहुंचा मिशन रीव

टीम रीव, बिलासपुर

प्रदेश के दूसरे जिलों की तरह बिलासपुर में भी मिशन रीव ग्रामीणों के बीच अपनी अलग पहचान बना चुका है। बात खेती की हो, पशुपालन की हो या रोजमर्रा से जुड़ी अन्य जरूरतों को पूरा करने की, मिशन रीव हर क्षेत्र में एक साथी के तौर लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका है।

अक्सर सरकारी योजनाओं का लाभ उन लोगों को नहीं मिल पाता जिन लोगों के लिए ये योजनाएं बनाई जाती है। ऐसे में न तो सरकार अपने लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त कर पाती है और न ही लोगों को योजनाओं का लाभ मिल पाता है। समाज कल्याण की राह में रोड़ा बन रही इन समस्याओं का निवारण करने में आईआईआरडी का मिशन रीव अहम भूमिका निभा रहा है। दरअसल रीव सरकार और आम जनता के बीच खाई को पाटने में एक मजबूत कड़ी बनता जा रहा है। जिला बिलासपुर में मिशन रीव के तहत ऐसे कई उदाहरण है।

मिशन रीव बिलासपुर के लोगों के लिए ग्रामीण विकास का पर्याय बनता जा रहा है। मिशन रीव के तहत उन क्षेत्रों में भी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है। मिशन रीव के तहत किसानों को खेती से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही खेती करने के लिए जरूरी उपकरण और उन्नत किस्म के बीज और टब आदि भी मुहैया करवाए जा रहे हैं। सबसे पहले मिशन प्रतिनिधियों के माध्यम से गांव के लोगों का आवश्यकता आकलन किया जाता है और उसके बाद उस आंकलन के आधार पर लोगों की मांग के अनुसार उनकी जरूरतों को पूरा किया जाता है।

लोगों का कहना है कि वैसे तो बाजार में सभी सामान मिल जाता है लेकिन इसके लिए पहले बाजार जाना पड़ता है और फिर सामान घर तक पहुंचाने की परेशानी अलग से रहती है। लेकिन मिशन रीव के तहत इन जरूरतों को घर पर ही पूरा किया जा रहा है जिससे गांव में लोगों का जीवन आसान हो गया है।

लोगों को निशुल्क स्वास्थ्य जांच, जीएसटी नंबर, जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण, राशन कार्ड में नाम जोड़ने, कार लेने, बीएसएनएल का क्नेक्शन दिलाने, बाइक, कार और घर का इशोरेंस करने और उनके व्यवसाय को आगे ले जाने में मिशन रीव काफी मददगार साबित हो रहा है।

लोगों को दी मिशन रीव की जानकारी

टीम रीव, हमीरपुर

जिला हमीरपुर में गांवों में लोगों को मिशन रीव के बारे में जानकारी देने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। इसके तहत मिशन के प्रतिनिधि लोगों के घर जाकर उनकी जरूरतों के बारे में पूछ रहे हैं और प्राथमिकता के आधार पर उन जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित बैठकों के दौरान लोगों की जरूरतों को जानने के साथ ही 'द रीव टाइम समाचार पत्र' भी लोगों को बांटा गया ताकि वह देश – दुनिया में होने वाली घटनाओं के बारे में अपडेट रह सके। इसके बाद मिशन रीव के तहत गांवों में दी जा रही विभिन्न सेवाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर मिशन रीव के प्रतिनिधियों ने बताया कि मिशन रीव लोगों को उनके घर पर ही स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा प्रदान कर रहा है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को चिकित्सकों के परामर्श के बाद कोई दवा की जरूरत पड़ती है तो वह भी मिशन रीव के प्रतिनिधि लोगों को बाजार से लाकर दे रहे हैं। स्वास्थ्य के अलावा कृषि, पशुपालन व ग्रामीण विकास से जुड़ी कई योजनाओं पर भी मिशन रीव कार्य कर रहा है। गांव के पशुपालकों के लिए रीव जैविक खाद का प्रशिक्षण वरदान साबित हो रहा है। गोबर से जैविक खाद बनाकर जहां वह अपने खेतों में इस्तेमाल कर रहे हैं वहीं इसकी बिक्री कर अतिरिक्त आय भी घर बैठे ही प्राप्त कर रहे हैं।

कांगड़ा में भी दिया जाएगा जैविक खाद का प्रशिक्षण

हिमाचल को जैविक राज्य बनाने की दिशा में बड़ी उपलब्धि

टीम रीव, कांगड़ा

हिमाचल को जैविक राज्य बनाने की दिशा में आईआईआरडी ने मिशन रीव के तहत एक बड़ी उपलब्धि हासिल की हैं। सोलन में जैविक खाद का सबसे बड़ा भंडार तैयार करवाने के बाद अब कांगड़ा में भी किसानों को जल्द जैविक खाद का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि इस खाद को तैयार करने के लिए जैविक खेती अभियान के तहत आईआईआरडी के प्रतिनिधियों की ओर से गांव गांव जाकर किसानों और बागवानों को निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके तहत आईआईआरडी के प्रतिनिधियों की निगरानी में गांव वालों से खाद तैयार करवाई गई और उनसे खरीदकर मिशन रीव के तहत उन्हें खाद की बिक्री के लिए बाजार भी उपलब्ध कराया गया है।

यह पहली बार है कि कोई संस्था गांव के लोगों को उन्हीं के घरद्वार पर रोजगार के साथ साथ व्यवसाय शुरू करने का भी अवसर प्रदान कर रही है। इन प्रतिनिधियों को आईआईआरडी शिमला में विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। संस्था के इस प्रयास की ग्रामीण क्षेत्रों में काफी सराहना हो रही है। लोगों का कहना है कि खाद बनाना तो आसान है पर उसकी बिक्री अभी तक मुश्किल थी लेकिन आईआईआरडी ने इसे आसान बना दिया है। जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण देकर गांव के लोगों को व्यवसाय का भी अवसर दिया जा रहा है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

निशुल्क प्रशिक्षण और बाजार उपलब्ध कराने से मजबूत होगी किसानों की आर्थिकी

आईआईआरडी कृषि प्रभाग की अधिकारी शशी किरण का कहना है कि हिमाचल में खेती की अपार संभावनाएं हैं। यहां पर जैविक खेती को बढ़ावा देकर प्रदेश की आर्थिक को मजबूत किया जा सकता है। इन्होनें कहा कि जब गांव में जाकर लोगों से बात की गई तो वह जैविक खेती को लेकर काफी उत्साहित थे। जब उन्हें रासायनिक खादों से भूमि के साथ–साथ स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में भी अवगत कराया गया तो सौ फीसदी जैविक खेती को ही अपनाने के पक्ष में थे।

जैविक खेती के लाभ

कृषकों की दृष्टि से लाभ

- भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो जाती है।
- सिचाई अंतराल में वृद्धि होती है।
- रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है।
- फसलों की उत्पादकता में वृद्धि।

मिट्टी की दृष्टि से

- जैविक खाद के उपयोग करने से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है।
- भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती हैं।
- भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम होगा।

पर्यावरण की दृष्टि से

- भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है।
- मिट्टी, खाद्य पदार्थ और जमीन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण मे कमी आती है।
- कचरे का उपयोग, खाद बनाने में, होने से बीमारियों में कमी आती है।
- फसल उत्पादन की लागत में कमी एवं आय में वृद्धि।
- अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पाद की गुणवत्ता का खरा उतरना।

जाहू में लोगों को मिल रही सस्ती दवाईयां

जनऔषधि केंद्र खुलने से इलाज हुआ सस्ता

टीम रीव, हमीरपुर

एकीकृत ग्रामीण विकास संस्थान, आईआईआरडी शिमला की एक नई पहल के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में लोगों को सस्ते दामों पर दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तीन सौ जनऔषधि केंद्र खोले जा रहे हैं। इसी के तहत हमीरपुर के जाहू में जनऔषधि केंद्र खोला गया है। जाहू में यह पहला जनऔषधि केंद्र है। इसके खुलने से जाहू के लोगों को अब सस्ती दवाईयों के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता।

जाहू निवासी भगतराम का कहना है कि अभी तक उन्हें बाजार से मंहगे दामों पर दवाईयां खरीदनी पड़ती थी। कई बार तो ये दवाईयां जेब पर इतनी भारी पड़ जाती थी कि घर का पूरा बजट ही बिगड़ जाता था। लेकिन अब आईआईआरडी की ओर से प्रधानमंत्री जनऔषधि योजना के तहत जाहू में सस्ती दवाईयां उपलब्ध करवाई जा रही है। इससे स्थानीय लोगों को काफी राहत है। जाहू में ही जनऔषधि केंद्र खुलने से इलाज सस्ता हो गया और लोगों के समय की भी बचत हो रही है।

उल्लेखनीय है प्रदेश के लोगों को सस्ती दवाईयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पांच जनऔषधि केन्द्रों का मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने रीव सचिवालय शिमला से किया था। उन्होंने इस दौरान कहा था कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। और लोगों को इसकी रक्षा के लिए मंहगी

प्रदेश में खुलेगें 300 जनऔषधि केंद्र

दवाईयों के लिए अब नहीं तड़पना पड़ेगा तथा जनाऔषधि केन्द्रों से अब सभी को सस्ते दामों पर दवाईयों की उपलब्धता होगी । जाहू में भी इसी दौरान जनऔषधि केंद्र की शुरूआत की गई थी जिससे आज सैंकड़ो लोग सस्ती दवाईयों का लाभ उठा रहे हैं।

आईआईआरडी की ओर से खोले गए जनऔषधि केंद्रो पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सस्ते दामों पर बेहतर क्वालिटी की दवाईयां उपलब्ध है। इससे पहले लोगों को सस्ती दवाओं के लिए शहरों में भटकना पड़ता था।

मंडी में ऑयस्टर मशरुम बदलेगा किसानों की आर्थिकी

मिशन रीव के तहत ग्रामीणों को दिया जाएगा उत्पादन का प्रशिक्षण

टीम रीव, मण्डी

हिमाचल प्रदेश में मौसम की बेरूखी और जंगली जानवरों की समस्या ने किसानों की कमर तोड़ दी हैं। हालात ये है कि किसान अपनी जमीन बंजर छोड़ने को मजबूर है। बागवानी में भी स्थिति काफी अच्छी नहीं है। ऐसे में किसानों और बागवानों की आर्थिकी लगातर कमजोर हो रही है। एकीकृत ग्रामीण विकास संस्थान शिमला ने मिशन रीव के माध्यम से कमजोर होती आर्थिकी को मजबूत करने की मुहिम शुरू की हैं व इसके तहत गांवों में जाकर लोगों को उच्च गुणवत्ता वाले मशरूम उगाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और अगर कोई मशरूम लगाना चाहता है तो उसके लिए निशुल्क प्रशिक्षण देकर बाजार उपलब्ध कराने की सुविधा भी मिशन रीव के तहत गांवों में दी जा रही है। इस योजना को सिरे चढ़ाने के लिए आईआईआरडी शिमला कार्यालय में जुलाई माह के पहले सप्ताह में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मशरूम प्लांट स्थापित किया गया था। सीमित संसाधनों के साथ शुरू किया गया यह प्रोजेक्ट पूरी तरह सफल रहा। इसके बाद जिला मंडी में भी पायलट आधार पर लगाया गया प्लांट सफल रहा है। अब इस आधार पर जल्द ही मंडी की विभिन्न पंचायतों में ऑयस्टर मशरूम की खेती करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद जैविक खाद की तर्ज पर ही किसानों को मशरूम की बिक्री के लिए किसानों को बाजार भी उपलब्ध करवाया जाएगा।

मंडी के रामपाल का कहना है कि वह ऑयस्टर मशरूम लगाना चाहते हैं लेकिन इसे कैसे लगाना इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। इसके बाद फिर सवाल यह भी है कि मशरूम उगाने के बाद उसे बेचना कहां है ताकि अच्छे दाम मिल सके। रामपाल की तरह ही अन्य लोग भी मशरूम खेती को व्यवसाय के तौर पर अपनाना चाहते हैं। इसे देखते हुए मिशन रीव के तहत गांव में किसानों को ऑयस्टर मशरूम की खेती करने के गुर सिखाए जाएंगे।

आईआईआरडी के प्रबंध निदेशक डाक्टर एलसी शर्मा का कहना है कि मिशन रीव के तहत पंचायतों के लोगों को सशक्त बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। इसी कड़ी में अब ऑयस्टर मशरूम की खेती से जोड़कर गांवों की आर्थिकी मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।

मंडी जिला समन्वयक ने बताया की मशरुम की ऑयस्टर प्रजाति के उत्पादन का प्रयोग मंडी में भी सफल रहा है। मिशन रीव के तहत मंडी के बल्ह में पहले ही प्रयास में ऑयस्टर मशरुम की बंपर फसल मिली है। इस प्रयोग के बाद स्थानीय लोगों में काफी उत्साह है और अधिकतर लोगों ने मिशन रीव से इस मशरूम को उगाने का प्रशिक्षण प्राप्त करने की इच्छा जताई है।

ऑयस्टर, बटन मशरुम के मुकाबले में बहुत ही आसानी से उगाया जा सकता है। उन्होंने बताया की जल्द ही लोगों को इस की खेती करने की पूरी जानकारी दी जाएगी और मशरूम की अन्य प्रजातियों के बारे में भी बताया जाएगा।

ग्रामीणों तक पहुंचाया उन्नत किस्म का बीज

मिशन रीव के कार्यो से लोग खुश

टीम रीव, चंबा

मिशन रीव ब्लॉक चम्बा के नितेश ठाकुर अतिरिक्त जिला समन्वयक ने बताया कि मिशन रीव के तहत ग्रामीणों की विभिन्न जरूरतों को कम समय में बेहतर तरीके से पूरे करने का प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में ग्राम पंचायत चंडी में लोगो को गेंदा फूल के फायदे व आजीविका कमाने के साधन के बारे में जानकारी दी गई। नितेश ने बताया कि जब बीज बोने का समय था तो ग्रामीणों को मिशन रीव के तहत लोगो को उन्नत किस्म के गेंदे के फूल का बीज भी उपलब्ध करवाया। इसके परिणाम स्वरुप ग्राम पंचायत चंडी के लोग गेंदा फूल बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहे है। इसके साथ ही गेंदा फूल का इस्तेमाल लोग अपने खेतों के चारो तरफ भी कर रहें है।

मिशन रीव से आसान हुआ दूरदराज के गांवों में जीवन

कुल्लू में घर–घर मिल रही सेवा

टीम रीव, कुल्लू

हिमाचल में आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां लोगों को बाजार तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ता है। अधिकतर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी भी नहीं मिल पाती।

इसी समस्या को दूर करने के लिए मिशन रीव के तहत लोगों की जरूरतों को पहचाना गया और उनकी जरूरतों को पूरा भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में मिशन रीव के तहत पंचायत में तैनात आईआईआरडी के प्रतिनिधि विशेष शिविरों का आयोजन कर रहे हैं। हाल ही में कुल्लू की विभिन्न पंचायतो में इसी तरह के शिविर का आयोजन किया और लोगों को मिशन रीव के तहत उपलब्ध कराए जा एनीमल फीड सप्लीमेंट की जानकारी दी गई। इसके साथ ही लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न तरह का सामान उनके घरों तक मिशन रीव के प्रतिनिधियों द्वारा पहुंचाया गया। इस मौके पर लोगों ने पशुधन के माध्यम से आर्थिकी मजबूत करने पर चर्चा की और मिशन रीव के तहत एनीमल फीड सप्लीमेंट उपलब्ध कराने की मांग की। इसके बाद उन्हें

कृषि और पशुधन में हुआ सुधार

सप्लीमेंट भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिसके काफी बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। पशुपालकों का कहना है कि मिशन रीव के तहत एनीमल फीड सप्लीमेंट से पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और दूध की गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में रोजमर्रा की जरूरत का सामान भी लोगों को घरों तक पहुचांया जा रहा है।

महिलाओं को दी मिशन रीव की जानकारी

टीम रीव, चंबा

किसी भी क्षेत्र के विकास में महिलाओं का विशेष योगदान रहता है। ऐसे में जरूरी है कि विकास को लेकर नई योजनाओं के बारे में ग्रामीण महिलाओं को जागरूक किया जाए। इसी उद्देश्य से मिशन रीव की ओर से चंबा की पुखरी पंचायत में महिला मंडल के साथ एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान एनआरएलएम पीआरपी नीशा एवं रेनू ने वीओ फांउडेशन करते हुए एनआरएलएम के तहत जय श्रीराम महिला ग्राम संगठन बनाया।

इस बैठक में महिलाओं को मिशन रीव के तहत ग्रामीण विकास के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। महिलाओं को बताया कि वह कैसे घर का कामकाज करने के साथ स्वरोजगार से जुड़ सकती हैं और कैसे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकती है। महिला मंडल की सदस्यों की ओर से मिशन रीव की भरसक प्रशंसा की गई। महिलाओं ने कहा कि योजनाओं के बारे में बात तो सब करते हैं लेकिन इन योजनाओं का लाभ कैसे प्राप्त करना है यह कोई नहीं बताता। लेकिन अब मिशन रीव के तहत यह जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। इससे उन महिलाओं को भी लाभ मिल रहा है जो घरेलु काम काज के कारण कहीं बाहर नहीं जा पाती। मिशन रीव के तहत पंचायत में, यहां तक की घर में ही सभी जानकारी प्रदान की जा रही है।

किसान भी मान रहे मिशन रीव के प्रयास बेहतरीन

टीम रीव, चंबा

यदि इंसान में मेहनत करने का जज्बा हो तो मंजिल हासिल हो ही जाती है। ग्राम पंचायत जतरुन के तहत जंगला गांव के किसान कांशीराम ने बताया कि जिला चंबा के रठियार के लाहडू गांव में 2 बीघा भूमि पर आलू ,गाजर ,बीन ,शलगम, मूली आदि की खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें खेती–बाड़ी करने का शौक बचपन से ही था। कांशी राम ने बताया कि उनके गांव में एक कृषि जागरूकता शिविर में जाने के बाद कृषि के प्रति रूझान और बढ़ गया। मिशन रीव के प्रतिनिधि ने जब कांशीराम को मिशन रीव जैविक खाद के बारे में बताया तो वह काफी खुश हुए और उन्होंने कहा कि वह भी जैविक खाद का ही प्रयोग करते हैं और इसी की बदौलत उन्होंने अपने खेत में पांच किलो की मूली उगाने में सफलता हासिल की।

कांशीराम का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों, बागवानो, किसानों को आर्थिक सहायता के अलावा अनुदान पर बीज औजार और कृषि कार्य के लिए पावर ट्रेलर, थ्रेशर व अन्य सामान उपलब्ध करवाया जाता है जिससे किसान और बागवान भरपूर फायदा उठा अपनी आर्थिकी मे सुधार ला सकते हैं लेकिन जानकारी के अभाव में किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाता। इन्होनें कहा कि मिशन रीव के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल रही है और प्रदेश को जैविक राज्य बनाने के लिए भी मिशन का योगदान प्रशंसनीय है।

मिशन रीव के तहज चंबा पहला कैशलैस जिला

कैश रखने का झंझट नहीं, पीओएस से हो रहा भुगतान

टीम रीव, चंबा

मिशन रीव की ओर से चंबा में एक बेहतरीन पहल की जा रही है। बीते माह मिशन रीव के तहत सभी प्रतिनिधियों को पीओएस मशीनें दी गई थी। इन मशीनों को देने का मुख्य उद्देश्य गांव के लोगों को सेवा प्राप्ती के लिए कैश रखने की परेशानी से मुक्त करना है। चंबा की तर्ज पर मिशन रीव के तहत अन्य जिलों में भी जल्द ही पीओएस मशीनों से ही सभी भुगतान किया जाएगा और सभी मिशन प्रतिनिधियों को पीओएस मशीने दी जाएंगी। चंबा के जिला समन्वयक राकेश शर्मा का कहना है कि मिशन रीव चंबा को कैशलैस करने की ओर से तेजी से अग्रसर है। अधिकतर प्रतिनिधियों को पीओएस मशीनें दी जा चुकी है और जहां किन्हीं कारणों से मशीनें नहीं पहुंच पाई वहां भी जल्द ही पीओएस से भुतगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। राकेश का कहना है कि अब किसी को भी सेवा प्राप्ति के लिए भुगतान कैश में करने की जरूरत नहीं रही यानी अगर आप मिशन रीव के तहत किसी भी सेवा का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी जेब में कैश रखने की अनिवार्यता नहीं है। आप पीओएस में एटीएम कार्ड स्वाइप कर सेवा का लाभ कभी भी कहीं भी ले सकते हैं। चंबा में पीओएस मशीने काफी कारगर साबित हो रही है। क्योंकि अधिकतर पंचायतों से बैंक शाखा अथवा एटीएम काफी दूर है। लोगों को कैश निकालने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पीओएस मशीनों से यह परेशानी पूरी तरह दूर हो जाएगी। आईआईआरडी की प्रबंध निदेशक डाक्टर एल.सी. शर्मा ने बताया कि पहले चरण में चम्बा में मिशन रीव के सभी प्रतिनिधियों को मशीनें दी जा रही है। इसके बाद प्रदेश के अन्य जिलों में भी पीओएस मशीनें भेजी जाएंगी ताकि गांव के लोगों को कैश ट्रांसफर करने में परेशानी न हो।

IIRD हम जानते हैं गाँव को बेहतर
MISSION RIEV
Ruralising India- Empowering Villages
कि दुनिया देखती रह जाए
सबका साथ ही
मिशन की सफलता है क्योंकि
हम जानते हैं गाँव को बेहतर

आओ कानून को जानें

मानहानि कानून क्या है ? मानहानि के नियम क्या है ? मानहानि का मामला ? मानहानि का केस क्या है ? मानहानि की सजा क्या होती है ? मानहानि केस प्रोसीजर क्या है ? मानहानि केस पनिशमेंट क्या है ?

एक गरीब व्यक्ति से लेकर एक बड़े से बड़े व्यक्ति तक उसकी इज्जत उसके लिए बहुत माईने रखती है। कहा भी गया है कि व्यक्ति को अपनी इज्जत बनाने में वर्षो लग जाते है और इज्जत गंवाने में एक मिनट ही काफी है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपने प्रतिस्ठा, इज्जत, ख्याति और सामाजिक सम्मान को किसी भी तरह से ठेस पहुंचने से बचा सके और साथ ही अगर कोई व्यक्ति उसकी इज्जत और सम्मान के साथ खिलवाड़ करता है तो वह उसके खिलाफ न्यायालय (कोर्ट) में जा सकता है। हमारे कानूनी सलाहकार आपको इस अंक में इसी विषय पर जानकारी दे रहे हैं :

- किसी भी व्यक्ति की बेइज्जती करना, समाज में उसको निचा दिखाने की कोशिश करना, उस पर कोई झूठा आरोप लगाना, झूठा बेईमान कहना, उसे गाली देना इत्यादि मानहानि केस के अन्दर आते है और उसके लिए आरोप लगाने वाला व्यक्ति अपराधी की श्रेणी में आता है।

मानहानि कानून क्या है ?

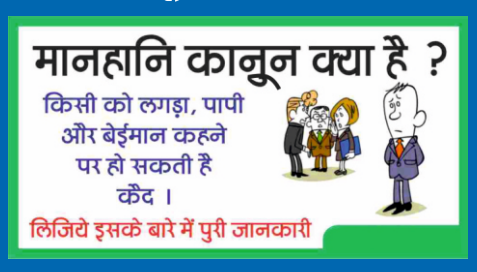

बहुत बार हम किसी व्यक्ति को बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कह देते है लेकिन हमारे द्वारा बिना सोचे समझे कहा गया एक वाक्य और शब्द हमारे लिए मुसीबत बन सकता है । किन–किन बातों से , तथ्यों से, इशारों से किसी व्यक्ति की मानहानि होती है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए ताकि हम सोच समझ कर ही किसी को कुछ कहे तथा हमें भी अपने अधिकारों के बारे में पता चल सके।

जाति व समुदाय से सम्बंधित : किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने के उद्देश्य से उसकी जाति, समुदाय और उसके धर्म के बारे में अपशब्द कहना मानहानि के अन्दर आते है। लड़ाई झगडे के दौरान किसी को जातिसूचक शब्द कहने से व्यक्ति पर मानहानि का मुकदमा चल सकता है। इसमें अगर कोई व्यक्ति किसी के व्यवसाय को लेकर भी उसका अपमान करता है, इस स्थिति में भी व्यक्ति पर मुकदमा चल सकता है ।

योग्यता और साख को गिरना : अगर कोई व्यक्ति किसी के काम करने की योग्यता, अनुभव, ज्ञान और तुजुर्बे को झूठा साबित करने की कोशिश करता है और लोगों में उसका दुष्प्रचार करता है, मानहानि के अन्दर आते है । इस तरह की मानहानि व्यक्तिगत, सामुहिक और संस्थागत किसी भी रूप में हो सकती है।

किसी व्यक्ति को कानूनी रूप से चोर, बे–ईमान, अपराधी, डिफाल्टर इत्यादि की संज्ञा मिलने से पहले ही उसको इन नामों से पुकारना व संबोधित करना भी मानहानि के दायरे में आता है।

किसी की शारीरिक स्थिति को देख कर उसे अपमानजनक शब्दों से सूचित करना जिसका उदेश्य उसके सम्मान को ठेस पहुंचाना हो..... किसी व्यक्ति की अच्छी छवि को उसकी मृत्यु के बाद गलत ठहराना व उसके परिजनों को दुःख पहुंचाना.....ये सभी भी इसी दायरे में आता है।

उपरोक्त बताई हुई बातों में अगर कोई सम्मलित पाया जाता है तो उसे मानहानि केस में दोषी ठहराया जा सकता है।

साइबर मानहानि कानून क्या है ? :

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66–ए के तहत कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर, इन्टरनेट या मोबाइल की मदद से फेसबुक, ट्वीटर, यू ट्यूब तथा अन्य सामाजिक वेबसाइट और उपकरणों से किसी की मानहानि करता है तो कानून के तहत कैद या जुर्माना या फिर ये दोनों सजा हो सकती है ।

वो तथ्य जो मानहानि केस के अन्दर नहीं आते है

किसी भी व्यक्ति पर मानहानि का मुकदमा तब तक नही चलाया जायेगा जब तक ये साबित नही हो जाये की इसका उद्देश्य दुसरे व्यक्ति के मान सम्मान को ठेस को पहुंचाना, उसकी साख गिराना, उसको समाज में नीचा दिखाना और उस पर कोई झूठा आरोप लगाना साबित नही हो जाता । इसके लिए पीड़ित व्यक्ति के पास मानहानि से संबंधित सभी सबुत होना जरुरी है ।

किसी व्यक्ति को अभद्र, चिड़चिडा, पिछड़ा, अनाड़ी जैसे शब्दों से संबोधित करना मानहानि में नही आता।

अगर किसी पर कोई आरोप समाजहित व लोगो की भलाई के लिए लगाया गया हो तो व्यक्ति मानहानि के मुकदमे से बच सकता है लेकिन इसके लिए व्यक्ति को यह साबित करना होगा की उसका उदेश्य लोगों की भलाई करना था ।

किसी व्यक्ति और समाज को अपराधी, चोर व बेईमान लोगों से आगाह करना मानहानि नही है ।

किसी पुस्तक, फिल्म, नाटक, व्यक्ति और आदेश की आलोचनात्क समीक्षा करना जिसमें निजी हित शामिल ना हो ।

मानहानि केस का दोषी पाये जाने पर मिलने वाली सजा : मानहानि की सजा

भारतीय दंड संहिता की मानहानि की धारा 499 (defamation ipc 499) के अनुसार भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अपने मान–सम्मान, शौहरत, यश इत्यादि को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति धारा 499 के अंतर्गत दोषी पाया जाता है तो उसको निम्न धाराओ के तहत दंड दिया जा सकता है.....

धारा 500 : Defamation ipc 500 :अगर कोई व्यक्ति किसी दुसरे व्यक्ति की मानहानि करता है तो उसको धारा 500 के तहत 2 साल तक की कैद या आर्थिक जुर्माना या फिर ये दोनों सजा हो सकती है।

धारा 501 : Defamation ipc 501: जान बुझ कर किसी की मानहानि करने पर उसको धारा 501 के तहत 2 साल तक की कैद या आर्थिक जुर्माना या फिर ये दोनों सजा हो सकती है ।

धारा 502 : Defamation ipc 502 :अपने आर्थिक उदेश्य के लिए किसी की मानहानि करने पर धारा 502 के तहत 2 साल तक की कैद या आर्थिक जुर्माना या फिर ये दोनों सजा हो सकती है ।

आदि.....

मानहानि होने पर मिलने वाला मुआवजा या हर्जाना :

अगर किसी व्यक्ति की मानहानि होने से उसे आर्थिक नुकसान भी हुआ है तो वह कोर्ट में इसके लिए मानहानि करने वाले व्यक्ति से मुआवजे की अपील कर सकता है । इसमे पीड़ित व्यक्ति को हर्जाने की रकम बतानी होगी और व्यक्ति द्वारा मानहानि करने का ठोस सबुत भी देना होगा ।

एडवोकेट प्रदीप वर्मा
कानूनी सलाहकार आईआईआरडी

पाठकों के प्रश्न एवं कानूनी समस्याऐं सादर आमंत्रित है । आपके प्रश्नों के उत्तर हमारे कानून विशेषज्ञ ऐडवोकेट प्रदीप वर्मा अगले अंक में देंगे। प्रश्न हमारी मेल आई डी पर डालें therievtime@iirdshimla.org hem.raj@iirdshimla.org

समय प्रबंधन कितना आवश्यक और इसके कुछ टिप्स

जीवन में यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वो समय है। जीवन का आरंभ और अंत इसी के पराधीन है। इसलिए यह अति आवश्यक हो जाता है कि हम समय के प्रबन्धन को जीवन का मुख्य हिस्सा बनाकर सफलता की ओर क़दम बढ़ाऐं। लेकिन यह अक्सर मुश्किल सा लगता है कि हमारे दैनिक कार्य इस प्रकार उलझे होते हैं कि समय का उचित बंटवार कैसे हो ? आईए द रीव टाइम्स के साथ इसे कुछ आसान करते हैं .....

- एक दैनिक योजना बनायें । यह योजना आप रात में सोने से पहले या फिर सुबह में बना लें । इससे यह होगा कि कल पूरे दिन आप क्या करने वाले हैं इसका पता चल जायेगा । अब आप अपने प्लान के मुताबिक अपने कम को करते रहेंगे ।
- प्रत्येक कार्य के लिए एक समय निर्धारित करें । यह स्पष्ट रखें कि पहला काम 10 बजे तक दूसरा काम 2 बजे तक और तीसरा काम 5 बजे तक कर लेना है । इससे आपका काम न सिर्फ समय पर होता है बल्कि एक काम का समय दूसरे काम में नहीं देना पड़ता है ।
- एक कैलेंडर का प्रयोग करें । कैलेंडर का उपयोग आपके दैनिक गतिविधियों के प्रबंधन के लिए सबसे मौलिक कदम है । यदि आप outlook या lotus notes का उपयोग करते हैं तो कैलेंडर अपने मेलिंग सॉफ्टवेयर के हिस्से के रूप में आते हैं । Google कैलेंडर का प्रयोग कर सकते हैं । यह और भी बेहतर होगा अगर आप इसे अपने मोबाइल फोन और अन्य हार्डवेयर में उपयोग करते हैं । किसी काम के बारें में नोट आप अपने मोबाइल में अलार्म के साथ set कर सकते हैं ।
- एक ऑरगेनाईज़र का प्रयोग करें। ऑरगेनाईज़र आपको आपके जीवन में हर चीज में आगे रहने में मदद करता है। यह आपकी जानकारी को व्यवस्थित रखने में, सूची बनाने में, केंद्रीय उपकरण की तरह काम करता है।
- अपने डेडलाइन का ध्यान रखें। आप अपने काम को कब समाप्त करना चाहते हैं उसका एक deadline अपने कैलेंडर पर अंकित कर लें अब अपने आप को इस तरह से व्यवस्थित करें कि आपका काम समय पर पूरा हो जाये।
- नहीं – कहना भी सीखें। यह जान लें कि आप अपनी क्षमता से ज्यादा काम नहीं कर सकते और उससे ज्यादा काम मत लें। अगर बीच में कोई काम आता है जिससे आपका चल रहा काम बाधित हो रहा हो तो न कहें या उसके लिए कोई अन्य समय आवंटित करें ।
- लक्ष्य को थोड़ा पहले रखें. जब लक्ष्य उसके निश्चित समय पर रहेगा तो या तो वह समय पर पूरा होगा या देर हो जायेगा लेकिन जब लक्ष्य थोड़ा पहले होगा तो वह हमेशा समय पर ही पूरा होगा। किसी से मिलने समय से थोड़ा पहले ही जाना चाहिए।
- हमेशा वक्त का ध्यान रखो। अपने पास एक घड़ी रखो। कभी कभी काम की व्यस्तता में समय का अहसास नहीं रहता। गांधी जी अपने पास हमेशा एक घड़ी रखते थे और अपना हर काम समय पर करते थे । अतः अच्छे समय प्रबंधक अपने पास एक घड़ी जरूर रखते हैं।
- यदि आपको कोई काम करना है और आप उसका अलार्म लगाते हैं तो अलार्म 15 मिनट पहले का लगायें।
- एक शब्द है – Multitasking अर्थात एक साथ कई काम करना। इसमें कभी–कभी कोई भी काम समय पर पूरा नहीं होता है, ऐसे में सिर्फ एक मुख्य काम पर ध्यान केन्द्रित करें। इससे आपका काम शीघ्र और पूर्ण रूप से होगा।
- अपना ध्यान भंग करने वाले सभी काम को ब्लॉक कर दें.... बंद कर दें। Facebook पर मेसेज आ रहा है, Google chat पर message आ रहा है जिससे आपका प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो रहा है ऐसे में Facebook और Google is sign out होकर अपना काम करें नहीं तो आपका प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाएगा – इसलिए इस प्रकार की गतिविधियों पर कुछ हद तक अकुंश लगाऐं।
- अपने बिताये हुए समय का ध्यान रखें। इससे अभी आप अपने प्रोजेक्ट पर कितना समय लगा चुके हैं इसका पता चलेगा और आपके पास कितना समय बच गया है यह भी ध्यान में रहेगा। परीक्षा के दौरान एक घंटे पर एक bell, दो घंटे पर दो bell इसलिए बजाये जाते हैं कि छात्रों को यह ध्यान रहे कि कितना समय शेष बचा है।
- महत्वहीन विवरण में मत फसें। आप कभी भी कार्यों को उस तरीके से नहीं कर सकते जैसा कि आपने सोच रखा है, ऐसा करना अप्रभावी होगा।
- कार्य को प्राथमिकता के अनुसार करें। चूँकि आप सभी काम को अकेले नहीं कर सकते अतः जरुरी काम पहले कर लें, बाकी रहने दें। प्राथमिकता क्रम के लिए 80/20 का सिद्धांत का प्रयोग करें।
- दूसरों को भी काम करने दें अर्थात delegate your work- कोई काम यदि ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है और उसे दूसरे भी कर सकते हैं तो वैसे काम दूसरों को करने दें। इससे आप और महत्वपूर्ण काम में अपना ध्यान लगा सकेंगे।
- अगर एक ही तरह का काम हो तो उसे बैच में भी किया जा सकता है। इससे काम को अलग–अलग श्रेणी में बांटकर किया जा सकता है। फोन करने के लिए 3–4 बजे का समय book writing के लिए सुबह का दो घंटा आदि।
- आपका समय जिस भी काम करने से नष्ट होता है या इससे आप अपने काम से दूर होते जाते हैं time wasters कहलाते हैं। अधिकतर सोशल मीडिया पर बने रहना भी परेशानी का सबब बन जाता है और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं।
- जरुरत पड़ने पर अपने आपको cut off रखें। आप पर काम का बोझ बढता जायेगा। डरें नहीं..... यह ज़रुरी होता है अन्यथा काम कभी समाप्त नहीं होगा एक के बाद दूसरा आता रहेगा।
- एक काम और दूसरे काम के बीच थोड़ा 5–10 मिनट का अवकाश रखें इससे पहले काम को समेटने में भी थोड़ा समय मिल जायेगा।
- प्रोजेक्ट पूरा होने पर उसके समय प्रबंधन से जुड़े steps के बारे में विचार करें इससे आगे के प्रोजेक्ट्स में समय प्रबंधन और भी अच्छे तरीके से हो सकेगा।

आपका स्वास्थ्य हमारा परामर्श

त्वचा की एलर्जी क्या और उसका उपचार

कई बार कुछ शरीरिक समस्याएं बीमारी तो नहीं होती पर परेशान बीमारियों से भी ज्यादा कर देती हैं। स्किन एलर्जी सुनने में साधारण लगती जरूरी है पर कई बार

इतना हैरान कर देती है कि व्यक्ति हरारत भरे बुखार तक के चपेट में आ जाता है।

कैसा होता है एलर्जी का असर

एलर्जी से कई लोग अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं इसलिए उन्हें खुजली के प्रत्यक्ष लक्षणों की जगह छाले, दर्द, छोटी–मोटी फुंसियाँ इत्यादि होती हैं और इसे हल्के में ले लिया जाता है जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं । अगर सही समय पर इस पर ध्यान न दिया जाए तो त्वचा रोग भी बन सकते हैं। इसके अलावा कई बार प्लास्टिक की चीजों जैसे नकली आभूषण, बिंदी, परफ्यूम, चश्मे के फ्रेम, साबुन आदि से भी एलर्जी हो जाती है । इस तरह की एलर्जी को कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस कहा जाता है ।

एलर्जी होने की कुछ खास वजह

- मौसम में बदलाव से नाक की एलर्जी हो सकती है
- वायु प्रदूषण
- टैटू का त्वचा पर बुरा प्रभाव
- ऐसा खाना खाना जो हमारे शरीर को सूट न करे
- आस पास सफाई न होना
- किसी तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट जैसे की हेयर कलर इस्तेमाल करना
- किसी दवा का साइड इफेक्ट
- ड्राई स्किन से त्वचा के एलर्जी होती है
- किसी कीड़े–मकोड़े / मच्छर का काटना

एलर्जी के लक्षण

- त्वचा का रंग बदलना, जैसे लाल धब्बे पड़ना
- खुजली होना
- फुंसी जैसे दाने हो जाना
- रैशेज या क्रैक पड़ना
- जलन होना
- त्वचा में खिंचाव पैदा होना
- छाले पड़ना

एलर्जी से बचने के उपाय

- घर से बाहर निकलें तो चेहरे और बाजुओं को ढकें । सन्सक्रीन का भी उपयोग कर सकते हैं ।
- चेहरे को दिन में कई बार पानी से धोएं । इससे चेहरे पर लगी धूल–मिट्टी हट जाएगी ।
- ऐलोवेरा जेल या ऐलोवेरा से बनी क्रीम आदि का ही प्रयोग करें।
- अगर कामकाजी हैं तो शाम को भी स्नान करें। इससे धूल आदि से होने वाली एलर्जी नहीं होगी।
- फिल्टर्ड पानी का ही प्रयोग करें।

स्किन एलर्जी के आसान घरेलू उपचार जिससे आपको तुरंत मिलेगा आराम।

1. कपूर और नारियल तेल
2. फिटकरी
3. एलोवेरा
4. नीम
6. सुपाच्य एवं सब्जी फल

एलर्जी होने पर ये सावधानियां बरतें

- त्वचा में खुजली न करें
- जिस साबुन का आप नियमित रूप से इस्तेमाल कर रही हैं, उसका इस्तेमाल करना बंद कर दें
- शरीर को खुली हवा लगने दें
- सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपको पता चल गया है कि किस चीज से आपको एलर्जी होती है तो उससे दूर रहें, किसी भी उपचार हेतु अपने डॉक्टर से संपर्क करें और चिकित्सक के परामर्श से ही दवाई का सेवन करें। इस समस्या में कई बार ठीक होने के लिए महीनों भी लग जाते हैं क्योंकि दवाईयों का उपयोग कोर्स के आधार पर ही पूरा होता है ।

डॉ0 के आर शांडिल
आईआईआरडी, शिमला
अधिक जानकारी के लिए लिखें: therievtime@iirdshimla.org

शासन व न्यायिक व्यवस्था की आड़ में.....भाग एक

कहा जाता है कि लंका में रावण के राज्य में विभीषण, दमोदरी आदि को छोड़ बाकि सभी दंभी, अभिमानी व दानवी प्रवृत्तियों से युक्त थे। वैसे ही राम राज्य में अधिकांश अयोध्यावासी ईमानदार, सत्यवादी, परोपकारी व धर्म परायण कहे जाते हैं। अर्थात् जिस प्रकार जैसा राजा का आचरण रहा है वैसी ही प्रवृति प्रजा में पाई गई जिससे 'यथा राजा तथा प्रजा' की उक्ति सटीक साबित होती है ।

वर्तमान परिदृश्य में राजा का स्थान सरकारों ने ले लिया तथा सरकारी तंत्र में मुख्य ओहदों पर विराजमान वे सभी व्यक्ति राज की श्रेणी में आते हैं जिनके मात्र एक छोटे से निर्णय से जनता पर दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं। अतः वर्तमान में राजा की भूमिका निभाने वाले समस्त व्यक्तियों पर अपने निर्णय व पहल के दूरगामी प्रभाव आकलन करने का दबाव सदैव बना रहता है।

हिमाचल के संदर्भ में यहां दो अहम विषयों पर विवेचना करने का प्रयास हो रहा है। इसमें पहला है लोगों के कब्ज़े वाली सरकारी ज़मीन को कब्ज़ामुक्त करने बारे। पिछले लगभग पांच दशकों से सरकारी तंत्र में बैठे प्रभावशाली व्यक्तियों के इशारों से दूर–दराज के क्षेत्रों में वनों को काटकर बगीचे लगाने की परम्परा आरम्भ हुई। सरकारें आती रहीं, जाती रहीं, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली कि प्रदेश की अमूल्य वन संपदा संकट में है। वन विभाग जो कि प्रदेश का एकमात्र विभाग ऐसा है जहां भारतीय सेवा स्तर के अधिकारियों की सबसे बड़ी फौज है, मूक दर्शक बना रहा। पारिवारिक विभाजन के होते–होते जो लोग भूमिहीनता की ओर बढ़ते गये, उनकी सुध लेना किसी भी सरकार ने आवश्यक नहीं समझा तथा उनकी ओर से अधिग्रहण की गई सरकारी भूमि को कुछ हद तक रोटी के सवाल से जोड़कर देखा जा सकता है । लेकिन उनका क्या जो मात्र अपनी संपन्नता और प्रभाव को बढ़ाने के उद्देश्य से जंगलों का सफाया कर बगीचे लगाने लगे। दशकों मूक दर्शक रहे सरकारी तंत्र से जनता को लगने लगा कि कब्ज़े वाली भूमि शायद सरकार कब्ज़ाधारी के नाम ही कर लेगी। इस बारे कुछ प्रक्रिया शुरु भी हुई। सब कब्ज़ाधारियों की सूची बनाई गई जो कई वर्षों से सरकारी फाईलों में धूल का शिकार बनी हुई है ।

लगभग दो वर्ष पूर्व किसी की याचिका पर हि0प्र0 उच्च न्यायालय ने सरकार को बगीचों को काट कब्जा छुड़वाने का आदेश दिया लेकिन इसका प्रभाव कुछ कम प्रभाव वाले व्यक्तियों पर ही दिखा। बड़े रसूखदार बागवानों की ओर देखने की किसी कर्मचारी की हिम्मत नहीं हुई। जिन्होंने आंख उठाई उन्हें मुंह की खानी पड़ी। न्यायालय स्तर पर कई बार समीक्षा करने के बाद भी स्थिति जस की तस है। इस पर कुछ प्रश्न अनायास ही परंतु यक्ष प्रश्न बन कर खड़े हो जाते हैं :

- उच्च न्यायालय के आदेशानुसार हुई कार्यवाही में कुछ लोगों के बगीचे काटे गए जबकि दूसरे लोग अभी भी मनमाने तरीके से फसलों का व्यावसायीकरण करने में लगे हैं। जबकि न्यायालय के आदेशों का अनुपालन समस्त कब्ज़ाधारियों पर समान रुप से लागू होना चाहिए था। जिनके पेड़ काटे गए व कब्ज़ा छुड़वाया गया, क्या उनकी मात्र यह ग़लती थी कि वे कम प्रभावशाली थे ?

- दूसरा, जब तक सभी के पेड़ काटकर सरकार अपने कब्ज़े में ज़मीन को नहीं करती, क्या तब तक उन लोगों, जिनका कब्ज़ा छूट गया है, को सरकार या न्यायालय फसल की भरपाई का अनुदान देगी, जो वे लोग कमा सकते थे यदि पेड़ न कटे होते ?
- वस्तुतः सेब के एक पेड़ को बड़ा करने में 10 से 15 वर्षों का समय लग जाता है तथा पेड़ों की देखरेख बच्चों जैसी ही करनी पड़ती है। काटने की अपेक्षा क्या यह न्यायसंगत न होता कि कब्ज़े वाली ज़मीन को बगीचों सहित 'बागवानी विभाग' को या फिर 'वन विभाग' को ही देख–रेख के लिए दिया जाता, कब्ज़ाधारियों से छुड़वाकर।
- पेड़ काटना अपने आप में एक बड़ा अपराध है, आज के चुनौतीपूर्ण पर्यावरण के दौर में। एक ओर हम पेड़ों को लगाने की कवायद शुरु किए हुए हैं और दूसरी ओर पेड़ काटने की न्यायिक व्यवस्था बना रहे हैं।
- हिमाचल प्रदेश जो आज लगभग 52,000 / करोड़ रुपये के ऋण के बोझ में दबा है, वहीं इन बगीचों से 100–500 करोड़ रुपये की वार्षिक आमदन सरकारी ख़जाने के लिए व्यवस्थित की जा सकती है। सरकारी लचर व्यवस्था से यह स्थिति आज 'किंकर्त्वय' की ओर व्यवस्था को ले जा रही है।

भाग दो

दूसरा प्रश्न शिमला शहर में बने कुछ भवनों के नियमितिकरण का है तथा आजकल भवनों के स्वीकृति न लिए हुए भाग को तोड़ने की बात चल रही है। यदि इसकी गहराई में जाया जाए तो हमें पता चलता है कि यह समस्या भी कम पुरानी नहीं है। कई दशकों से लोग ऐसा करते आ रहे हैं और उनको किसी ने पूछा तक नहीं। अर्थात् पहले से हमारी शासन व्यवस्था लोगों को ग़लत करते हुए देखती रही, जिसकी देखा–देखी में दूसरों को भी बिना नक्शे की स्वीकृति के अपने भवनों में जोड़–घटाव करने का वातावरण बना। अब उसके तोड़ने की बात हो रही है, तो इस व्यवस्था को नियंत्रण करने के लिए जो निकाय बने हैं जो अधिकारी रहे, जो नेतृत्व प्रदान करते रहे उनकी जिम्मेवारी तय किए बिना जो भी क़दम ले वो अधूरा ही होगा। बीच–बीच में सरकारें 'जहां है–जैसा हैं' स्थिति पर नियमितीकरण का शगूफा छोड़ती रही जो कभी सिरे नहीं चढ़ा लेकिन जनमानस की भावनाओं को उजाग्र किए रखा। अब जिन्होंने ग़लती वाले वातावरण में, जो कि शासकीय व्यवस्था की देन हैं, ग़लतियां की हैं, उनकी आर्थिकी व उस कार्य में प्रयुक्त सामान व मानव श्रम के आकलन को नज़रंदाज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि यह राष्ट्रीय उत्पादकता से भी जुड़ा पहलु है। देश की आर्थिकी सकारात्मक कार्यों पर व्यय करने से सुदृढ़ होती है जबकि स्वीकृति बिना जोड़े गए भवनों के भाग को गिराने में भी खर्चा होना है तथा गिराने से बचे हुए भवन में कमजोरी आ सकती है।

यहां यह देखना आवश्यक होगा कि ऐसे भवन भौगोलिक दृष्टि से तथा भूकंप की दृष्टि से कच्चे न हो जिसका प्रमाण पत्र संबन्धित

अभियंता दे सकते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर भूकंपरोधी इमारत बनाने की पहल भी की जा सकती है। सरकार इन सभी ऐसी इमारतों व इमारतों के भागों पर एकमुश्त कर लगाने का प्रयास कर सकती है।

गिराने की बात मात्र वहीं होनी चाहिए जहां पहले भी किसी प्रकार की स्वीकृति नहीं ली गई हो या बिना स्वीकृति से बना भवन नियमावली से बिल्कुल मेल न खाता हो या अनाधिकृत ज़मीन पर कब्ज़ा कर इमारत बनाई हो या पानी, बिजली, सड़क, रास्ता आदि की सुविधा के लिए जनहित में गिरानी आवश्यक समझी जाए बशर्ते अनुदान की उचित प्रक्रिया अपनाई जाए आदि।

यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ईमारतों की ऊंचाई या मंज़िलों से है। प्राथमिकतः तौर पर यह संज्ञान लेना यहां आवश्यक होगा कि ईश्वर ने धरती को बनाना और अधिक विस्तार देना बंद कर दिया है जबकि जनसंख्या बढ़नी बंद नहीं हुई है। अतः हमारे पास आज विकल्प मात्र ऊंचाई की ओर है क्योंकि दांऐ–बांऐ बढ़ने के लिए जगह कम पड़ती जाएगी। समय की मांग है कि हम वैज्ञानिक तकनीकों की सहायता से अधिक से अधिक जनसंख्या को कम से कम भू–भाग में व्यवस्थित करें, नहीं तो आने वाले समय में क़दम रखने को भी जगह नहीं मिलेगी। अतः तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखकर 5 से 7 मंज़िलों तक का प्रावधान होना चाहिए, ज़मीन को बचाए रखने का इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं होगा।

अगली बात यहां भवनों के नक्शों की स्वीकृति को लेकर है यह प्रशासनिक कम दार्शिनिक अधिक लगता है। एक ही समय में एक जैसे मामलों में किसी को 5 मंजिलें बनाने की स्वीकृति मिलती है तो किसी को अढाई मंजिलों तक की, जैसा कि नियमावली में है । आज समस्त नियमों के होते हुए भी ऐच्छिक शक्तियों का प्रयोग होता है । सरकारी हस्ताक्षर कहीं ग़लत को भी ठीक बना लेते हैं तो कहीं ठीक को भी ठीक नहीं मानते। यह एक विडंबना है। जिस प्रकार विवाह से पूर्व पुरुष व स्त्री साथ रहने को चारित्रिक संदेह की दृष्टि से देखा जाता है , उसी प्रकार विवाह के बाद एक साथ न रहने से भी इसी श्रेणी में आते हैं। भेद मात्र विवाह की मुहर का है। जबकि व्यवहारिक पक्ष में स्थिति एक जैसी होती है। वही व्याख्या यहां सरकारी मुहर की है। नक्शे पास करने के लिए जो जोड़–तोड़ किए जाते हैं उनकी तो बात ही यहां नहीं हो रही है। शासन आधारभूत नियमावली बनाऐं तथा नागरिक स्वयं की भूमि में नियमावली के अनुरुप घर बनाए तथा पूरी जिम्मेवारी वास्तुकार की निश्चित की जाए।

ऐसी व्यवस्था हो तो डेविएशन पर भारी कर सहित कारावास तक की सजा का प्रावधान हो जिसे सख़्ती से लागु किया जाए तो स्थिति में स्वतः ही सुधार आ सकता है। अभी तक जो भी घर बने हैं उन्हें नियमित करने की व्यवस्था की जाए तथा भविष्य के लिए नागरिकों को स्वयं ही जिम्मेवार बनाने की योजना पर विचार करना होगा। ताकि हर समय लोग व्यवस्था को दोषी न ठहराते रहे अपितु स्वयं ही व्यवस्था का अभिन्न अंग बन कर आगे बढ़े। यहीं से आम नागरिकों को जिम्मेवार नागरिक बनने की पहल हो सकती है। बनी हुई चीज को गिराना किसी भी प्रकार से न्यायसंगत नहीं हो सकता।

डॉ0 एल सी शर्मा
प्रधान संपादक
md@iirdshimla.org

हज़ारों पेड़ चढ़ चुके हैं फोरलेन की बलि

पेड़ लगाने के नाम पर अभी ज़मीन तक का चयन नहीं

पहाड़ों को चीर कर बन रहा तरक्की का फोरलेन

टीम रीव, शिमला (हेम राज चौहान)

तरक्की की राह सड़कों से होकर गुजरती है .....यह बात आज के संदर्भ में बिल्कुल सटीक एवं सत्य है। लेकिन पहाड़ों में सड़क की आधारभूत आवश्यकता के बाद फोरलेन के लिए सारी भौगोलिक स्थिति को ही आकलन के दायरे में लाया जाना ज़रुरी है। ये सड़कें हालांकि हमारे समाज की वर्तमान में जीवन रेखा है फिर भी सड़कों का बड़ा स्वरुप यानि फोरलेन कहीं न कंही भविष्य के लिए ख़तरे से कम नहीं हैं । हमारी पड़ताल इसी संदर्भ में की गई जिसमें कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। पर्यावरणविदों एवं प्रकृति के शुभचिंतक अक्सर अपनी चिंता कंकरीट के बनते जंगलों और कटते पेड़ों के अलावा अंधाधुंध खनन पर जताते रहे हैं। और यह उचित भी है। पहाड़ बिना पेड़ों और जंगलों के पहाड़ नहीं हो सकते। यहां का जीवन भी जल–जंगल–जलवायु पर ही निर्भर है। ऐसे में खड़े पहाड़ों पर फोरलेन के विभत्स मशीनी पंजों ने इन पहाड़ों को अंदर से खोखला कर दिया है। सबसे अधिक नुकसान तो वर्षों से हमारे जीवन को ऑक्सीजन और हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर रहे मूक पेड़ झेल रहे हैं जिन्हें एक झटके से गिरा कर जेसीबी रौंद रही है। ऐसा नहीं कि बिना नुकसान के तरक्की का इतिहास लिखा जा सकता हो.....तरक्की के लिए कुछ न कुछ कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है किंतु उसका विकल्प जब तक सामने न हो तब तक इस प्रकार का नुकसान प्रकृति को असंतुलित कर देगा।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से सूचना के अधिकार में प्राप्त सूचना की माने तो प्रदेश सरकार के साथ हुए समझौता ज्ञापन में जिन शर्तों पर सहमति बनी है उसमें सबसे पहले यदि कोई कार्य हुआ और हो रहा है तो वो हैं पेड़ों का अंधाधुंध कटान। तीनों ज़ोन में ही यानि परमाणु से सोलन, सोलन से कैथलीघाट और कैथलीघाट से ढली के बीच पेड़ों का व्यापक स्तर पर कटान हो चुका है तथा अभी कितने ही इस फोरलेन की भेंट चढ़ने बाकि है ।

सूचना में एनएचएआई ने बताया कि

- **एनएचडीपी–111 (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) ईपीसी मोड़ के आधार पर परमाणु से सोलन अनुभाग एनएच 22 में 67.00 किलोमीटर से 106.139 किलामीटर का निर्माण हो रहा है।**
- **एनएचडीपी–111 (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) ईपीसी मोड़ के आधार पर ही सोलन से कैथलीघाट अनुभाग एनएच 22 में 106.139 किलामीटर से 129.05 किलोमीटर का निर्माण हो रहा है।**
- **एनएचडीपी–111 (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) एन्यूटी (वार्षिकी) हाईब्रिड मोड़ के आधार पर ही कैथलीघाट से ढली अनुभाग एनएच 22 में 129.05 किलामीटर से 156.507 किलोमीटर का निर्माण हो रहा है।**

परियोजना निदेशक सनवर मल स्वामी ने बताया कि समझौता ज्ञापन के तहत इन तीन अनुभागों में प्रदेश सरकार के साथ ऑथोरिटी द्वारा सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है। पेड़ो को काटने का कार्य प्रगति पर है तथा नए पेड़ लगाने का कार्य प्रदेश वन विभाग के डिविजनल फोरेस्ट ऑफिसर (डीएफओ) के अधीन है क्योंकि सरकार को पेड़ों का उचित मुआवज़ा दिया जा चुका है तथा इतना ही नहीं..... पेड़ों के लगाने से उसके दस वर्षों तक के संरक्षण तक के लिए पैसा जमा किया गया है । प्राधिकरण फोरलेन के निर्माण से संबन्धित ही कार्य देख रहा है तथा पेड़ों के लगाने के लिए हिमाचल सरकार के पास नियमानुसार धनराशि जमा करवाई जा चुकी है ।

फोरलेन की भेंट अब तक हुए इतने पेड़ शहीद

4 सितंबर 2018 तक फोरलेन में परमाणु से ढली शिमला तक तीनों अनुभागों में कुल 40 हज़ार से अधिक पेड़ काटे जा चुके हैं । यह आंकड़ा अगस्त के आख़िर तक का है जिसमें अभी के आंकड़े शामिल नहीं है । यानि यह आंकड़ा अब कहीं अधिक हो चुका है ।

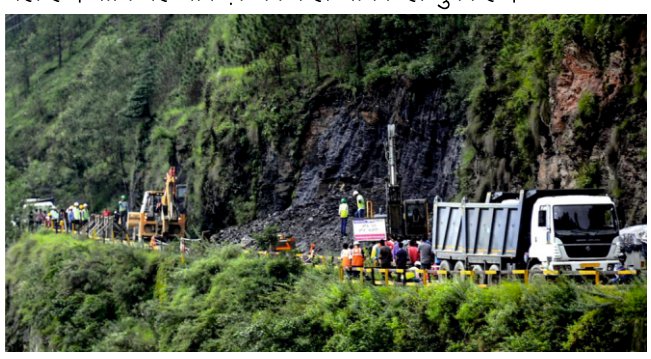

- **परमाणु से सोलन में वन विभाग की ज़मीन पर 12 हज़ार 508 पेड़ काटे गए हैं जबकि डिफेंस भूमि पर 1 हज़ार 882 तथा निजी भूमि पर 7 हज़ार 807 पेड़ काटे गए हैं। जिनका कुल योग 22 हज़ार 197 बनता है।**
- **सोलन से कैथलीघाट के बीच वन विभाग की ज़मीन पर 1 हज़ार 150 पेड़ काटे गए हैं।**
- **कैथली घाट से ढली के बीच वन विभाग की ज़मीन पर 9 हज़ार 576 पेड़ काटे गए और निजी भूमि पर 7 हज़ार 173 पेड़ों को कटना पड़ा है। जिसका कुल योग 16 हज़ार 749 है। यानि सितंबर प्रथम सप्ताह तक 40 हज़ार से अधिक पेड़ ज़मींजोद हो चुके हैं।**

यह आंकड़ा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से प्राप्त हुआ जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकारी इससे भी अधिक के पेड़ काटे जाने की बात कर रहे हैं ।

यहां प्रश्न यह है कि जब समझौता ज्ञापन में पेड़ काटे जाने के एवज में पेड़ लगाने की शर्तें हैं और उसके लिए प्राधिकरण ने बाकायदा सरकार को पर्याप्त राशि जमा भी करवा दी है तो कितने पेड़ लगाए गए हैं तथा कितने अभी नहीं लगे ....इसका स्पष्टीकरण होना भी आवश्यक है । इन तीनो अनुभागों के लिए पेड़ लगाने आदि के लिए संबन्धित डिवीजनल फोरेस्ट अधिकारी यानि डीएफओ की जिम्मेवारी को सुनिश्चित की गई है।

क्या कहते हैं शिमला डीएफओ सुशील राणा

इस बाबत जब डीएफओ शिमला सुशील राणा से बात की तो उन्होंने बताया कि एनएचएआई द्वारा पैसे जमा करवा दिए गए हैं तथा पेड़ों को काटा भी जा रहा है। लेकिन अभी तक एक भी पेड़ नहीं लगाया गया है । पेड़ को लगाने की दस्तावेज़ी औपचारिकताऐं अधिक है तथा अभी लैंड बैंक भी नहीं बन पाया है। ज़मीन की तलाश जारी है तथा ज़ल्द ही इस पर गंभीरता से कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा। यह पूछे जाने पर कि जहां फोरलेनिंग का कार्य हो चुका है और उसके मलबे आदि मे भी पेड़ लगाने का कार्य है तो उन्होंने बताया कि अभी कोई भी पेड़ नहीं लगाया गया है। डीएफओ ने बताया कि अभी शिमला ज़ोन में ही लगभग 24 हज़ार पेड़ और कटने है। 10 हज़ार 740 पेड़ काटे जा चुके हैं तथा 39 ऐसे पेड़ हैं जो किसी न किसी विवाद के कारण नहीं काटे जा सके हैं। साथ ही 494 ऐसे पेड़ हैं जिन्हें टनल आदि बनने के कारण कटने से बचाया गया है। शिमला ग्रामीण एवं शहरी अलग–अलग क्षेत्रों में लैंड बैंक की समस्या बनी हुई है।

लेकिन यहां प्रश्न यह है कि टनल बनने से उसके उपर बने मकान और पेड़ दोनों ही असुरक्षित हो जाऐंगे। ब्लास्टिंग से मकानों को खतरा तो रहेगा ही साथ ही पेड़ों की जड़ें जब कट जाएगी तो उपर खड़ा पेड़ स्वतः ही सूख जाऐगा। यानि पेड़ कटने के बजाए सूखेगा और इससे यह संख्या और अधिक बढ़ जाएगी। हालांकि सुशीन राणा कहते हैं कि टनल के उपर पेड़ सुरक्षित नहीं रखे जा सकते क्योंकि उनकी जड़ें कट जाऐंगी। इसलिए उन सूखे पेड़ों को वाइल्ड लाईफ सेक्चरी आदि में उपयोग लाया जा सकेगा।

क्या कर रही है सरकार जमा पैसों का

सरकार के पास करोड़ों रुपया पेड़ लगाने का जमा है जिसकी ब्याज सरकार के खाते में आ रही है और पेड़ अभी एक भी नहीं लगाया गया है। यदि लैंड बैंक नहीं है अथवा कोई अन्य दस्तावेज़ी गतिविधियां भी पूरी नहीं की गई है तो पेड़ काटा जाना भी कहां तक वाज़िब कहा जा सकता है।

हिमाचल प्रदेश में बंजर वन भूमि की कमी नहीं हैं तथा पौधारोपण कार्यक्रम करवाने संस्थाओं की भी भरमार है। सरकार को सबसे पहले बंजर वन भूमि को ही लैंड बैंक बनाकर उस पर पौधारोपण कर संतुलन बनाने की आरंभिक पहल करने की प्रबल आवश्यकता है। क्योंकि एक पेड़ को बड़ा होने तथा गुणों के विकास में बहुत वर्ष का सफर तय करना होता है। ऐसे में इतना अंधाधुंध कटान हिमाचल प्रदेश की भूमि को नग्न कर देगा। इसके दूरगामी दुष्परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा।

पर्यावरणविद की पीड़ा

वयोवृद्ध, सेवानिवृत एवं पर्यावरणविद प्रो0 आर के गुप्ता ने हमसे अपनी पीड़ा ज़ाहिर करते हुए साझा किया कि पहाड़ टूट रहे हैं. ....नदियां सूखती जा रही है.....प्राकृतिक स्रोत सूखे पड़े हैं.....पहाड़ों के नीचे सुरंगे बना कर उपर बने मकान कभी भी ज़मींजोद हो सकते हैं। यह सब अब देखा नहीं जाता। उन्होंने कहा कि एक ज़माना था कि पहाड़ हरे–भरे और पेड़ों से लदे होते थे। इसके कारण कभी पानी और नमी की भी कमी नहीं रही। आज वही पहाड़ नंगे और जर्ज़र है, उन्हें कुरेदा जा रहा है, मशीनी पंजो से खरोंचा जा रहा है। पहाड़ नहीं बचे तो मानव जीवन भी सुरक्षित नहीं हो सकता। उनके अनुसार जल–जंगल–ज़मीन को बचाना आज की चुनौती है।

सरकार से लेकर आम आदमी तक की जिम्मेवारी

विकास हमेशा नुकसान की सान पर ही चलता है, लेकिन उसके विकल्पों पर समय रहते विचार न किया गया तो भविष्य के लिए जो मुश्किलें होंगी उनका निदान अगली पीढ़ी के लिए बहुत मुश्किल होगा। पेड़ों का संरक्षण और उसके कटने के बाद प्राकृतिक जलस्रोतों को बचाने के लिए हम सभी की सामुहिक जिम्मेवारी है। सरकार को योजनाबद्ध तरीके से इसके लिए क़दम उठाने की आवश्यकता है और आम आदमी को भी विकास के लाभ लेने से पहले अपने कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि यहां पहाड़ नहीं दरक रहे.....दरक रहा है भविष्य के गर्भ में प्रलय का भूचाल.....

हेम राज चौहान
सहायक संपादक, द रीव टाइम्स
Chauhan.hemraj09@gmail.com,94184 04334

हिमाचल में योजना विभाग ही चलेगा

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

हिमाचल प्रदेश में फिलहाल योजना विभाग पहले की तरह ही काम करता रहेगा। प्रदेश में योजना विभाग को खत्म करके वित्त विभाग में समायोजित करने का प्रोपोजल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। प्रदेश सरकार फिलहाल इसे पूर्व की तरह ही चलने देना चाहती है, जैसा कि पिछली सरकार ने भी किया था। सूत्रों के अनुसार वित्त विभाग की ओर से योजना विभाग को खत्म करके वित्त विभाग में समायोजित करने का एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भेजा गया था। पिछले दिनों इस पर चर्चा भी की गई, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय से यह फाइल वापस भेज दी गई है। मुख्यमंत्री ने खुद इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिए जाने को कहा है। मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद केंद्र में योजना आयोग को बंद कर दिया। इसकी जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया और पिछले चार–पांच साल से नीति आयोग ही काम कर रहा है। योजना आयोग की जगह पूरा दारोमदार नीति आयोग को सौंपा गया और उनकी सिफारिशों पर ही राज्यों को आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। चूंकि केंद्र में योजना आयोग ही खत्म हो गया है तो राज्यों को योजना विभाग को वित्त विभाग में समायोजित करना था। कुछ राज्यों ने ऐसा कदम उठाया भी है, लेकिन यहां पूर्व की वीरभद्र सरकार ने इस विभाग को चालू रखा। बाकायदा प्रदेश सरकार बजट के लिए वार्षिक योजना भी बनाती है, जिसका पूरा काम यही विभाग देखता है। इसके अलावा विधायक प्राथमिकता योजनाओं से जुड़े सभी कार्य यही विभाग करता है। सरकार को इस विभाग के माध्यम से महत्त्वपूर्ण सिफारिशें दी जाती हैं, जिनको यहां पर अमल में भी लाया जाता है। ऐसे में प्रदेश के मामलों में योजना विभाग अहम है, जिसको अब खत्म किए जाने का मुद्दा एक दफा फिर से उठा है। योजना विभाग में योजना सलाहकार से लेकर नीचे तक पूरा प्रशासनिक ढांचा है। वैसे यह विभाग वित्त विभाग के अधीन ही काम करता है, जिसका अलग से सचिव स्तर का जिम्मा भी आला प्रशासनिक अधिकारी के पास रहता है। मुख्यमंत्री द्वारा फाइल को वापस लौटा दिए जाने से फिलहाल इस विभाग को खत्म किए जाने की चर्चाओं पर विराम लग चुका है। सरकार इस मुद्दे पर आगे कोई निर्णय लेगी, यह कहना मुश्किल है।

हिमाचल प्रदेशः आउटसोर्स पर ही होगी 325 पदों पर ये भर्ती, कंपनियों से मांगीं निविदाएं

द रीव टाइम्स ब्यूरा

हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) में आउटसोर्स पर कंडक्टरों की भर्ती करने के फैसले पर प्रदेश सरकार अडिग है। कर्मचारियों के भारी विरोध के बाद भी निगम प्रबंधन ने 325 कंडक्टरों की भर्ती करने का फैसला लिया है। इसके लिए कंपनियों से निविदाएं मांग ली गई हैं।

6 दिसंबर को 3 बजे निगम प्रबंधन कार्यालय में इसकी फाइनेंशियल बिड खुलेगी। वर्तमान में एचआरटीसी में 1000 से अधिक कंडक्टरों के पद खाली चल रहे हैं। नियमित भर्ती के बजाय इन्हें आउटसोर्स पर भरा जाना है। इन कंडक्टरों को कितना वेतन दिया जाना है, यह तय नहीं किया गया है।

फाइनेंशियल बिड खुलने के बाद इस पर स्थिति साफ होगी। हालांकि, निगम प्रबंधन का मानना है कि इन कंडक्टरों को तनख्वाह और अन्य वित्तीय लाभ कंपनी की ओर से तय होने हैं। लेकिन बसों में टिकट की चेकिंग का काम एचआरटीसी प्रबंधन का रहेगा। अगर यह कंडक्टर टिकट में हेराफेरी करते हैं तो निगम प्रबंधन कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करेगा। कंपनी को प्रशिक्षण प्राप्त कंडक्टरों को ही बसों में चढ़ाना होगा। इसके लिए कंपनी की ओर से निगम प्रबंधन को इन कंडक्टरों का एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र देना होगा। एचआरटीसी सीजीएम ने बताया कि आउटसोर्स पर कंडक्टरों की भर्ती के लिए कंपनियों से निविदाएं मांग ली गई हैं।

छतों से दस मीटर ऊपर रोप-वे की शर्त हटेगी, एक्ट में हुआ संशोधन

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

राज्य सरकार ने दुर्गम क्षेत्रों में बनने वाले रोपवे की घरों की छतों से दस मीटर ऊपर की शर्त हटाने की तैयारी कर ली है। सरकार हिमाचल प्रदेश रोपवे एक्ट 1968 में संशोधन कर यह व्यवस्था कर रही है। एक्ट का उल्लंघन करने पर रोपवे संचालक के खिलाफ सरकार सिविल कोर्ट में जा सकेगी। राज्य की अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नंदा के इस संबंध में जारी नोटिस को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है। दरअसल दुर्गम क्षेत्रों में रोपवे निर्माण को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। अभी तक एक्ट के अनुसार रोप–वे बनाने के लिए घरों की छतों के ऊपर 10 मीटर की दूरी की शर्त लागू है। नए संशोधन में सरकार व्यवस्था कर रही है कि रोप वे निर्माण करने के लिए प्रमोटर को समय अवधि बढ़ाने के लिए विस्तृत कारण के साथ राज्य सरकार के पास साधारण पत्र देकर आवेदन करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त रोप–वे प्रमोटर ही समय–समय पर यात्रियों, पशुओं और सामान को ढोने के लिए दरें भी तय कर सकेगा। इससे पहले सरकार ने शर्त रखी थी कि पीपीपी मोड और बीओटी आधार पर बनने वाले रोपवे की दरें तय करने से पहले विशेषज्ञ कमेटी की सिफारिश करेगी। इसके अलावा प्रत्येक नब्बे दिन के बाद दरें तय की जाएंगी। इस शर्त को भी हटाने की तैयारी है। एक्ट में व्यवस्था की जा रही है कि अगर रोपवे संचालक नियमों की उल्लंघन करता है तो जुर्माना किया जा सकेगा।

हिमाचल में पाइपलाइन से घर-द्वार मिलेगी रसोई गैस

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

हिमाचल के तीन शहर ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर जल्द ही गैस पाइपलाइन से जुड़ेंगे। ऊना पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) से जुड़ने वाला प्रदेश का पहला शहर होगा, जहां लोगों को घर–द्वार पर पाइपलाइन के जरिए गैस उपलब्ध होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर संयुक्त रूप से 22 नवंबर को इंदिरा स्टेडियम से दोपहर 2:00 बजे इस योजना के काम का शुभारंभ करेंगे। सोमवार को प्रेस वार्ता में सत्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊना को देश के 65 शहरों में शुमार किया है, जहां एक साथ इस योजना के तहत निर्माण कार्य शुरू होगा । उन्होंने कहा कि नंगल तक पीएनजी पहुंच चुकी है। सबसे पहले इससे ऊना नगर परिषद को जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही हमीरपुर और बिलासपुर शहर में इस योजना का निर्माण कार्य शुरू होगा। यह गैस सिलिंडर से 15 प्रतिशत सस्ती पड़ेगी। इसके अलावा ऊना को सीएनजी से भी जोड़ा जा रहा है, जिसमें भारत पेट्रोलियम, एचपी व इंडियन ऑयल जैसी कंपनियां सहयोग कर रही हैं। उन्होंने इस योजना के लिए सांसद अनुराग ठाकुर का आभार जताते हुए कहा कि सांसद के प्रयासों से ऊना को यह सौगात मिलने जा रही है।

निजी स्कूलों में व्यावसायिक गतिविधियों पर पीएमओ ने मांगा जवाब

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल के निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम का पालन नहीं करने और सोसाइटी की आड़ में व्यावसायिक गतिविधियां चलाने पर प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने कड़ा संज्ञान लिया है। हिमालयन पर्यावरण संरक्षण संगठन कुल्लू की शिकायत पर प्रदेश के मुख्य सचिव और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के प्रोजेक्ट निदेशक को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया गया है। जानकारी के मुताबिक हिमालयन पर्यावरण संरक्षण संगठन ने आरोप लगाए हैं कि प्रदेश के निजी स्कूलों में आरटीई के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित नहीं की जा रही हैं। निजी स्कूल सोसाइटी की आड़ में वर्दियां, कॉपी–किताबें और अन्य खाद्य सामग्री बेच रहे हैं। पीएमओ ने मुख्य सचिव से इसकी जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। एक बयान में संगठन के अध्यक्ष अभिषेक राय ने कहा कि जिला कुल्लू समेत प्रदेश के निजी स्कूलों में आरटीई एक्ट का सरेआम उल्लंघन किया जा रहा है। स्कूलों में किताबें और वर्दियां धड़ल्ले से बेची जा रही हैं। मनमानी न रुकने पर उन्होंने इसकी शिकायत पीएमओ और एचआरडी मंत्रालय से की है।

तीन नहीं अब इतने साल के लिए मिलेगी प्राइवेट स्कूलों को संबद्धता

द रीव टाइम्स ब्यूरो

निजी स्कूलों की संबद्धता को लेकर स्कूल शिक्षा बोर्ड की बैठक में नया फैसला लिया गया है। सूबे के निजी स्कूलों को निकट भविष्य में पांच साल की संबद्धता मिलेगी । इस बीच बोर्ड के अधिकारी निजी स्कूलों का निरीक्षण करके खामियों को जांच सकते हैं।

संबद्धता का समय तीन साल से बढ़ाकर पांच साल करने के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला सभागार में हुई बैठक में चर्चा हुई। बोर्ड सचिव डॉ. हरीश गज्जू की अध्यक्षता में निजी स्कूलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। बैठक में निजी स्कूलों की समस्याओं पर चर्चा हुई।

साथ ही संबद्धता का समय बढ़ाने और इसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया सरल करने की मांग को निजी स्कूलों के प्रतिनिधियों ने प्रमुखता से उठाया। हालांकि, स्कूल शिक्षा बोर्ड तीन साल की संबद्धता निजी स्कूलों को देता है। लेकिन, हर साल संबद्धता नवीकरण के लिए पूरी फाइल फिर से बनाई जाती है।

2277 शिक्षक होंगे भर्ती, बेसहारा पशुओं को बनेगा गौसेवा आयोग

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

मंत्रिमण्डल ने प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों के 2277 रिक्त पदों को अनुबन्ध आधार पर भरने का निर्णय लिया। इन पदों में जेबीटी के 671 पद, टीजीटी के 835, शास्त्री के 375 तथा भाषा अध्यापकों के 396 पद शामिल हैं।

बैठक में राज्य में हिमाचल स्वास्थ्य देखभाल योजना (हैल्थकेयर) को लागू करने का निर्णय लिया गया। योजना के तहत परिवार फलोटर आधार पर प्रति परिवार (अधिक से अधिक पांच सदस्यों के लिए) प्रतिवर्ष प्रति परिवार पांच लाख रुपये की कैशलैस उपचार कवरेज प्रदान की जाएगी। उपचार सूचीबद्ध किए गए अस्पतालों में पूर्व परिभाषित पैकेज के आधार पर प्रदान किया जाएगा। आयुष्मान भारत के तहत सूचीबद्ध अस्पताल स्वतः स्वास्थ्य देखभाल योजना के लिए भी सूचीबद्ध होंगे। योजना में राज्य के वह सभी परिवार शामिल होंगे जो आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल नहीं हैं।

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमण्डल ने राज्य में गौवंश के संरक्षण व कल्याण के लिए हिमाचल प्रदेश गौसेवा आयोग की स्थापना करने को अपनी मंजूरी प्रदान की। आयोग गौवंश के कल्याण में लगे गौसदनों, गौशालाओं, गौ–अभ्यारणयों, गौ विज्ञान केन्द्रों तथा सामुदायिक पशु पालन केन्द्रों इत्यादि संस्थानों को नियंत्रित करेगा। आयोग बे–सहारा गायों से जुड़ी समस्याओं के समाधान में भी मद्दगार होगा।

मंत्रिमण्डल ने पट्टा नियमों के अनुसार पतजंलि योग पीठ को पट्टा राशि की स्वीकृति प्रदान की।

हिमाचल प्रदेश राज्य शहरी ठोस कचरा प्रबन्धन नीति को भी मंजूरी प्रदान की गई। नीति का उददेश्य कचरा प्रबन्धन गतिविधियों का इस ढंग से संचालन करना है जो न केवल पर्यावरण, सामाजिक तथा वित्तीय तौर पर टिकाऊ हो, बल्कि आर्थिक तौर पर भी व्यवहार्य हो। इसके अलावा भी मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।

DO YOU KNOW...?

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

Q1- What is the total geographical area of Himachal Pradesh?
Answer - 55673 Sq- km
Q 2- When was Himachal constituted?
Answer - 15th April, 1948
Q 3- When were Punjab Hills merged with Himachal?
Answer- 1st November, 1971
Q 4- When did Himachal Pradesh achieved full statehood?
Answer - 25 January, 1971
Q 5- What is the Vedic name of river Ravi ?
Answer - Parushani
Q 6- What is the Vedic name of Satluj?
Answer - Satudri
Q 7- What is the Vedic name of river Beas ?
Answer - Arjikya
Q 8- Baspa river is the tributary of which river ?
Answer - Satluj
Q 9- Which is the longest river of Himachal Pradesh ?
Answer - Satluj
Q 10- Bhakhra Dam is loacated on which river ?
Answer - Satluj
Q 11- Which pass separates Kinnaur from Tibet ?
Answer - Chobia Pass
Q 12- Which is the largest glacier in Asia located in Himachal?
Answer - Shigri La (in Lahaul&Spiti)
Q 13- What is the altitude of Kinner Kailash ?
Answer - 6500 mts
Q 14- Which pass separates Mandi from Kullu ?
Answer - Dulachi Pass
Q 15- The highest bridge in Asia at Kandror is located on which river ?
Answer - Satluj
Q 16 - In which district is lake Suraj Tal located ?
Answer - Lahaul Spiti
Q 17 - River Pabbar originated from which lake ?
Answer - Chandra Nahan Lake (Shimla)
Q 18 - In which scripture is the war between Divodas and Shambhar mentioned ?
Answer - Rig Veda
Q 19 - Which river was it on whose banks Alexander erected huge altars as a mark of his invasion of India ?
Answer - Beas
Q 20 - Who was the head of the group of monks whom Ashoka had sent to preach Buddhism in Himachal ?
Answer - Majjihima
Q 21 - Which fortress in Himachal Pradesh was attacked by Mahmud Gaznavi in 1019 A.D.
Answer - Kangra
Q 22 - What was the status of Himachal Pradesh as a state of the Indian Union after the State Re-organization Commission submitted its report in 1956 ?
Answer - Union Territory
Q 23-Which is the largest World Bank financed hydro&electric project in Himachal Pradesh ?
Answer & Nathpa Jhakri (1500 MW, in Kinnaur)
Q 24 - Who built the Gauri Shankar Temple of Chamba ?
Answer - Tribhuvan Rekha Devi
Q 25 - Which is the largest temple of Himachal Pradesh ?

रामायण एक्सप्रेस दिल्ली से शुरु

सफदरजंग स्टेशन से दिखाई हरी झंडी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

दिल्ली स्थित सफदरजंग रेलवे स्टेशन से 14 नवंबर 2018 को पूरे रामायण सर्किट पर दौड़ने वाली विशेष पर्यटक ट्रेन श्री रामायण एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह ट्रेन हिन्दू महाग्रंथ रामायण में वर्णित प्रमुख स्थानों पर जाएगी। यह ट्रेन तमिलनाडु के रामेश्वरम तक की यात्रा 16 दिन में पूरी करेगी। इस दौरान भगवान राम के जीवन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर रूकेगी। श्री रामायण एक्सप्रेस अपनी पहली यात्रा पर 800 यात्रियों के साथ रवाना हुई।

श्री रामायण एक्सप्रेस के प्रमुख स्टेशन

यह ट्रेन दिल्ली से रवाना हुई। यहां से निकलने के बाद इसका पहला पड़ाव अयोध्या था। अयोध्या के बाद यह हनुमान गढ़ी, रामकोट और कनक भवन मंदिर जाएगी। ट्रेन रामायण सर्किट के महत्वपूर्ण स्थलों जैसे नंदीग्राम, सीतामढ़ी, जनकपुर, वाराणसी, प्रयाग, श्रृंगपुर, चित्रकूट, नासिक, हम्पी और रामेश्वरम को कवर करेगी। ट्रेन अपनी यात्रा तमिलनाडु के रामेश्वरम में 16 दिनों में पूरी करेगी। ट्रेन में श्रीलंका के दौरे के लिए अलग से शुल्क चुकाना होगा। यदि यात्री श्रीलंका का सफर भी करना चाहते हैं, तो इसके लिए चेन्नई से कोलंबो तक हवाई सफर से जा सकेंगे। इसके बाद यहां 5 रात और 6 दिन का पैकेज मिलेगा। श्रीलंका के इस पैकेज टूर पैकेज में कैंडी, नुवारा एलिया, कोलंबो और नेगोंबो जैसे गंतव्य शामिल होंगे। आईआरसीटीसी ने हाल ही में 28 अगस्त से 9 सितंबर 2018 तक त्रिवेन्द्रम के रामायण सर्किट से पंचावती, चित्रकूट, श्रिंगवेरपुर, तुलसी मानस मंदिर, दरभंगा, सीतामढ़ी, अयोध्या और रामेश्वरम तक एसी पर्यटक ट्रेन संचालित की है।

अंतरिक्ष से भी नजर आता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी

अमेरिकी सैटेलाइट ने जारी की तस्वीर

द रीव टाइम्स ब्यूरो

गुजरात के अहमदाबाद में नर्मदा नदी के किनारे स्थापित विश्व की सबसे ऊँची सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अंतरिक्ष से भी साफ दिखाई देती है। अमेरिकी कमर्शियल सैटेलाइट नेटवर्क प्लैनेट द्वारा 16 नवम्बर 2018 को 182 मीटर (597 फीट) ऊंची प्रतिमा की अंतरिक्ष से ली गई एक फोटो ट्वीट की गई। यह तस्वीर 15 नवंबर को खींची गई थी। इसी के साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उन कुछ मानव निर्मित संरचनाओं में शामिल हो गया है, जो पृथ्वी के ऊपर से भी दिखाई देते हैं। दुबई के तट पर बना पाम आइलैंड, मिस्र का ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा सहित दो अन्य मानव निर्मित संरचनाएं हैं जो अंतरिक्ष से दिखाई देती हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की फोटो जारी करने वाली अमेरिकी कंपनी स्काईलैब है। वर्ष 2017 में इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करने का कीर्तिमान बनाया था, तब इनमें 88 डव सैटेलाइट स्काईलैब कंपनी के ही थे। सरदार पटेल की यह प्रतिमा गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध पर लगाई गई है, जो सात किलोमीटर दूर से नजर आती है। यह न्यूईयॉर्क के स्टैजच्यू ऑफ लिबर्टी से करीब दोगुना ऊंची प्रतिमा है और इसे बनाने में करीब 2989 करोड़ रुपये का खर्च आया है।

स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी

गुजरात में नर्मदा बांध के किनारे बनी यह मूर्ति न सिर्फ विश्व में सबसे ऊंची है बल्कि सबसे कम टाइम में तैयार भी हुई है। 182 मीटर की इस मूर्ति को बनने में सिर्फ 33 महीने का वक्त लगा है। इसके बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊँची मूर्ति चीन में स्प्रिंग टैम्पल बुद्ध है, जिसकी आधार के साथ कुल ऊंचाई 153 मीटर (502 फीट) हैं। इस अभियान में लगभग 6 लाख ग्रामीणों ने मूर्ति स्थापना के लिए लोहा दान किया। इस दौरान लगभग 5,000 मीट्रिक टन लोहे का संग्रह किया गया। मूर्ति के अंदर एक हाई स्पीड एलिवेटर लगाई गई है। इसके जरिए मूर्ति की छाती तक पहुंचा जा सकता है और नर्मदा डैम को ऊंचाई से देखने का लुत्फ उठाया जा सकता है। मूर्ति को 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली तेज हवाओं के साथ साथ रिक्टर स्केल पर 6.5 की तीव्रता वाले भूकंप को सहने की क्षमता वाला बनाया गया है।

प्रधानमंत्री ने लॉंच किया 'ग्रैंड चैलेंज'

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर 'कारोबार में सुगमता' से जुड़ी सात चिन्हित समस्याओं को सुलझाने के लिए 'ग्रैंड चैलेंज' का शुभारंभ किया है। इस चैलेंज का उद्देश्य युवा भारतीयों, स्टार्टअप और अन्य निजी उद्यमियों की क्षमताओं का दोहन करना है, ताकि वर्तमान अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर जटिल समस्याओं का समाधान निकाला जा सके। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 20 नवम्बर 2018 को नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय और विदेशी कंपनियों के चुनिंदा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत में कारोबारी माहौल को निरंतर बेहतर करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को अवगत कराया।

ईज़ आफ़ डूइंग बिज़नेस ग्रैंड चैलेंज

इस चैलेंज का उद्देश्य युवा भारतीयों, स्टार्टअप्स तथा निजी उद्योगों की संभावित क्षमता का उपयोग करना है। इसके चैलेंज में कुछ एक निश्चित समस्याओं के लिए आधुनिक तकनीक द्वारा समाधान ढूंढें जायेंगे। यह सरकार द्वारा भारत को व्यापार करने के लिए एक सुगम स्थल बनाने की योजना का हिस्सा है। देश में व्यापार करने के लिए माहौल को बेहतर करने के लिए सरकार काफी समय से प्रयास कर रही है। इस चैलेंज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन्टरनेट ऑफ़ थिंग्स, बिग डाटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन जैसी नवीनतम टेक्नोलॉजी के द्वारा सरकारी प्रक्रिया में सुधार किया जायेगा। इस ग्रैंड चैलेंज का प्लेटफार्म स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर होगा।

पृष्ठभूमि : विश्व बैंक द्वारा 31 अक्टूबर, 2018 को जारी 'कारोबार में सुगमता' रिपोर्ट (डीबीआर, 2019) में भारत 23 पायदानों की ऊंची छलांग लगाकर वर्ष 2017 के 100वें पायदान से ऊपर चढ़कर 77वें पायदान पर पहुंच गया है। विश्व बैंक की इस रिपोर्ट में 190 देशों में कारोबारी माहौल का आकलन किया गया है। सरकार द्वारा इस दिशा में किए जा रहे निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत 'कारोबार में सुगमता' सूचकांक में पिछले दो वर्षों में 53 पायदान और पिछले चार वर्षों (2014–2018) में 65 पायदान ऊपर चढ़ चुका है।

बीबीसी द्वारा जारी विश्व की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में 3 भारतीय

द रीव टाइम्स ब्यूरो

बीबीसी ने 19 नवम्बर 2018 को विश्व की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की। इसमें विश्व के अलग–अलग देशों की 100 महिलाओं को स्थान दिया गया है। इस सूची में जहां भारत की तीन महिलाएं हैं, वहीं पाकिस्तान की एक महिला शामिल है जो कि एक हिंदू हैं।

इस सूची में 15 से 60 वर्ष की 100 महिलायें हैं जिन्हें 60 देशों से चयनित किया गया है। इस सूची में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की बेटी चेल्सिया क्लिंटन का भी नाम है। उन्हें क्लिंटन फाउंडेशन के लिए उल्लेखनीय कार्य करने के लिए नामित किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने लाचार सीरियाई छात्रा नुजीन मुस्तफा के जरिये शरणार्थियों की मदद की।

मीना गाएनः

मीना (36 वर्ष) एक व्यापारी हैं तथा उन्होंने अपने क्षेत्र की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर सुंदरबन डेल्टा में अपने गांव तक पक्की सड़क बनाई है ताकि उनका गांव क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों से जुड़ सके। इन्हें सूची में 33वें स्थान पर रखा गया है।

विजी पेनकुद्दूः

विजी (50 वर्ष) केरल की रहने वाली हैं तथा उन्होंने अपने क्षेत्र में महिलाओं के अधिकारों के लिए महिलाओं की यूनियन बनाई है। यह यूनियन महिला कामगारों तथा अन्य महिलाओं के हितों के लिए आवाज़ उठाती है। उनके प्रयासों के फलस्वरूप ही महिला कामगारों को, फैक्ट्री आदि में, काम के वक्त बैठने का अधिकार प्राप्त हो सका है। वे बीबीसी की सूची में 73वें स्थान पर हैं।

रहीबी सोमाः

रहीबी सोमा पोपेरे (55 वर्ष) पश्चिमी भारत में कार्यरत हैं तथा यहां वे बीजों के संरक्षण का कार्य करती हैं. रहीबी स्वयं एक किसान हैं तथा उन्होंने भारत में सीड बैंक (बीज बैंक) तैयार किया है। इन्हें सूची में 76वें स्थान पर रखा गया है।

पाकिस्तान की हिन्दू महिला

भारत के अतिरिक्त पाकिस्तान की हिंदू महिला सांसद कृष्णा कुमारी कोहली को भी बीबीसी ने दुनिया की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में रखा है। कृष्णा (40) पाकिस्तान में मानवाधिकारों के लिए आवाज उठाने के लिए जानी जाती हैं. कृष्णा हिंदुओं के थारी वर्ग से आती हैं। वह सिंध प्रांत के एक दूरदराज के गांव की रहने वाली हैं। वह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर संसद में पहुंची हैं। उन्होंने पाकिस्तान में बंधुआ मजदूरों और महिलाओं की समस्याओं पर वर्षों संघर्ष किया था। कृष्णा और उनके परिवार ने तीन साल तक खुद भी बंधुआ मजदूरी की है।

भारत सरकार और एडीबी के मध्य ऋण समझौते पर हस्ताक्षर

जल एवं स्वच्छता सेवाओं के लिए होगा खर्च

ADB
ASIAN DEVELOPMENT BANK

द रीव टाइम्स ब्यूरो

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और भारत सरकार ने तमिलनाडु राज्य के कम से कम दस शहरों में जलवायु–सुदृढ़ जलापूर्ति, सीवरेज और जल निकासी संबंधी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के विकास से जुड़े 500 मिलियन डॉलर के बहु–किस्त वित्त पोषण की पहली किस्त के रूप में 169 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर 16 नवम्बर 2018 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए। 'तमिलनाडु शहरी प्रमुख निवेश कार्यक्रम' के लिए ऋण समझौते पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अपर सचिव (फंड बैंक एवं एडीबी) समीर कुमार खरे और एडीबी की ओर से एडीबी के भारत निवासी मिशन के कंट्री डायरेक्टर केनिची योकोयामा ने हस्ताक्षर किए।

ऋण समझौते की आवश्यकता

हाल के वर्षों में तमिलनाडु को बार–बार सूखे और अनियमित मानसून का सामना करना पड़ा है, जिस वजह से यहां पर जल की भारी किल्लत होने के साथ–साथ शहरों में बाढ़ की भी नौबत आ गई। एडीबी की ओर से मिलने वाले इस सहयोग से अभिनव एवं जलवायु–सुदृढ़ निवेश के साथ–साथ व्यापक संस्थागत सहयोग के जरिए इन जटिल शहरी चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। एडीबी का कार्यक्रम राज्य के विजन तमिलनाडु 2023 के लिए उसके द्वारा दिए जाने वाले सहयोग का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सभी की पहुंच जल एवं स्वच्छता तक सुनिश्चित करना और उच्च कार्य निष्पादन वाले औद्योगिक गलियारों (कॉरिडोर) में विश्वस्तरीय शहरों का विकास करना है।

केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने एयरसेवा 2.0 वेब पोर्टल लांच किया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

केन्द्रीय नागरिक उड्डयन एवं वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने 19 नवंबर 2018 को नई दिल्ली में एयरसेवा 2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल एप का उन्नत वर्जन लांच किया। इस अवसर पर नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि उपयोगकर्ताओं (यूजर) को बेहतर अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से एयरसेवा के एक उन्नत वर्जन के विकास की जरूरत महसूस की जा रही थी।

वेब पोर्टल से संबंधित मुख्य तथ्य

- इस वेब पोर्टल में कई खूबियां शामिल की गई हैं। सोशल मीडिया के साथ सुरक्षित साइन–अप एवं लॉग–इन, यात्रियों की सुविधा के लिए चैटबॉट, सोशल मीडिया पर शिकायतों सहित बेहतर शिकायत प्रबंधन, वास्तविक समय पर उड़ानों की ताजा स्थिति से अवगत कराना और उड़ान कार्यक्रम से जुड़ा विस्तृत विवरण उपलब्ध कराना इन खूबियों में शामिल हैं।
- एयरसेवा के उन्नत एवं बेहतरीन वर्जन का संचालन संवादात्मक वेब पोर्टल के साथ–साथ एंड्रायड एवं आईओएस दोनों ही तरह के प्लेटफॉर्मों पर प्रभावकारी मोबाइल एप के जरिए किया जाता है। इससे यात्रियों को बाधामुक्त एवं सुविधाजनक हवाई यात्रा करने का आनंद मिलेगा।
- वेब पोर्टल और एप्लीकेशन से हवाई यात्रियों की प्रतिक्रियाओं एवं सुझावों से अवगत होने में मदद मिलेगी जिससे ठोस नीतिगत कदम उठाना आसान हो जाएगा।
- इस अवसर पर सुरेश प्रभु एवं जयंत सिन्हा ने चेन्नई एयरपोर्ट को चैंपियन पुरस्कार प्रदान किया। चेन्नई एयरपोर्ट पर शत–प्रतिशत शिकायतों का निवारण एक साल के अंदर कर दिया गया है।

विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया गया

19 November
WORLD TOILET DAY 2018

विश्व शौचालय दिवस

विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर 2018 को मनाया गया. ।यह दिवस उन लोगों के बारे में जागरूकता लाने के लिए मनाया जा रहा है, जिनके पास शौचालय की सुविधा नहीं है, जबकि यह उनका मूलभूत अधिकार है। इस दिवस का आयोजन बेहतर पोषण और स्वास्थ्य में सुधार के तथ्य पर बल देते हुए शौचालय के महत्व पर पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया गया। यह विभिन्न बीमारियों के प्रसार को रोकने में भी मदद करता है। विश्व शौचालय दिवस वैश्विक स्वच्छता संकट से निपटने के लिए प्रेरित करने वाला एक महत्वपूर्ण दिवस है। वर्ष 2018 के लिए विश्व शौचालय दिवस का विषय "व्हेन नेचर कॉल्स है। विश्व में सभी लोगों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध करवाना संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों का हिस्सा है। शौचालय, एक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बनाने और स्वास्थ्य में वृद्धि करने और लोगों की गरिमा और सुरक्षा के संरक्षण में, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हैं। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यो में सबको शुद्ध पेयजल और स्वच्छता की सुविधा उलब्ध कराने का लक्ष्य भी रखा गया है। लेकिन खराब आधारभूत ढांचे दूषित जल आपूर्ति और गंदगी के कारण प्रत्येक दिन एक हजार बच्चो मौत का शिकार होते हैं।

पिछले चार सालों में ग्रामीण स्वच्छताः

02 अक्टूबर 2014 से आरंभ स्वच्छ भारत मिशन ने पिछले चार सालों में ग्रामीण स्वच्छता की कवरेज ने अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है। पहले स्वच्छता कवरेज जहां केवल 39 फीसद थी, वह बढ़कर अब 96 फीसद पहुंच गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 8.8 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। स्वतंत्र सर्वेक्षण के मुताबिक कुल 92 फीसद से अधिक शौचालय का निरंतर प्रयोग किया जा रहा है।

विश्व शौचालय दिवस

विश्व शौचालय दिवस की घोषणा विश्व शौचालय संगठन द्वारा वर्ष 2001 में की गयी थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2013 में इसे आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र विश्व शौचालय दिवस घोषित किया गया। इसका प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र जल संघ द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

ब्रिटेन की अदालत ने तिहाड़ जेल को बताया सेफ विजय माल्या का प्रत्यर्पण होगा आसान

माल्या के प्रत्यर्पण के मामले को लेकर अहम हो सकता है UK की अदालत का फैसला

भारत की जेलों को खुद के लिए असुरक्षित बताते रहे हैं माल्या, अब खत्म हो सकता है बहाना

इंटरनेशनल क्रिकेट में फिक्सिंग के आरोपी संजीव चावला के केस में कोर्ट ने दिया फैसला

द रीव टाइम्स ब्यूरो

ब्रिटेन की एक अदालत का फैसला विजय माल्या के भारत प्रत्यर्पण के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है । यू के की अदालत ने तिहाड़ जेल को सुरक्षित परिसर करार देते हुए कहा है कि यहां भारतीय भगोड़ों का प्रत्यर्पण किया जा सकता है। क्रिकेट फिक्सिंग के आरोपी संजीव चावला के केस में आया यह फैसला बैंक धोखाधड़ी कर भागे विजय माल्या के प्रत्यर्पण के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। लंदन हाई कोर्ट के जस्टिस लेगाट और जस्टिस डिंगेमैन्स ने शुक्रवार को दिए अपने फैसले में कहा कि तिहाड़ में भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक संजीव चावला के लिए कोई खतरा नहीं है। संजीव चावला पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की फिक्सिंग का आरोप है। यह हैंसी क्रोन्ये मैच फिक्सिंग का मामला है, जिसमें भारतीय क्रिकेटरों अजय जडेजा और मोहम्मद अजहरुद्दीन पर भी आरोप लगा था ।

भारत की ओर से चावला के इलाज का भरोसा दिलाए जाने के बाद लंदन हाई कोर्ट ने यह बात कही है। लंदन उच्च न्यायालय के इस फैसले का असर विजय माल्या के केस पर भी होगा। इसकी वजह यह है कि माल्या अकसर भारत की जेलों को असुरक्षित बताते रहे हैं, ऐसे में अब ब्रिटिश अदालत से उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी मिल सकती है।

अब इस मामले में नए फैसले के लिए केस वेस्टमिन्सटर मजिस्ट्रेट कोर्ट को ट्रांसफर होगा। ब्रिटेन के विदेश मंत्री चावला के प्रत्यर्पण के संबंध में आखिरी फैसला लेंगे, लेकिन इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। यही नहीं इसके बाद लंदन के सुप्रीम कोर्ट में भी फैसले को चेतावनी दी जा सकती है।

द रीव टाइम्स ने पहले भी एक लेख में इस मुद्दे पर ब्रिटेन की भारत की जेलों पर की गई टिप्पणी पर सख़्त प्रतिक्रिया दी थी। ये वही ब्रिटेन है जो भारत पर एक लंबे समय तक राज करता रहा और उसके दमनकारी शासन में भारत में जेलों की स्थिति बद् से

ये 1947 का नहीं.... आज का भारत है

भारत की जेलों पर ब्रिटेन की टिप्पणी उसकी संकुचित सोच को दिखाती है

जब कर्ज लेना था तो देश अच्छा.....अब माल्या को देश बुरा लग रहा

बद्तर थी। इसकी पूरी पड़ताल द रीव टाइम्स ने की थी और उस लेख की एक प्रति दिल्ली में ब्रिटेन के दूतावास को भी प्रेषित किया था। अब यदि चावला के मुकद्दमें में ब्रिटेन को भारत की तिहाड़ जेल उपयुक्त और सुरक्षित लगती है तो यह कहना ग़लत न होगा कि भगौड़ा विजय माल्या भी इस टिप्पणी के दायरे में ही आता ।

बदल गया है किलोग्राम मापने का तरीका, जानें- आप पर कितना फर्क

द रीव टाइम्स ब्यूरो

(वॉशिंगटन) किलोग्राम मापने का तरीका बदल गया है। अभी तक इसे प्लैटिनम–इरिडियम के अलॉय से बने जिस सिलिंडर से मापा जाता था, उसे रिटायर कर दिया गया है। साल 1889 से इसी को माप माना जाता था । हालांकि अब वैज्ञानिक माप के जरिए किलोग्राम तय होगा। इस बारे में पैरिस में हुई दुनिया भर के वैज्ञानिकों की मीटिंग में एकमत से फैसला किया गया है। हालांकि माप का तरीका बदलने से मार्केट में होने वाले माप में फर्क नहीं पड़ेगा। 20 मई से नई परिभाषा लागू हो जाएगी। किलोग्राम को एक बेहद छोटे मगर अचल भार के जरिए परिभाषित किया जाएगा। इसके लिए 'प्लैंक कॉन्स्टेंट' का इस्तेमाल किया जाएगा। नई परिभाषा के लिए वजन मापने का काम किब्बल नाम का एक तराजू करेगा। अब इसका आधार प्लेटिनम इरीडियम का सिलिंडर नहीं होगा। इसकी जगह यह 'प्लैंक कॉन्स्टेंट' के आधार पर तय किया जाएगा। क्वांटम फिजिक्स में प्लैंक कॉन्स्टेंट को ऊर्जा और फोटॉन जैसे कणों की आवृत्ति के बीच संबंध से तैयार किया जाता है।

जानें, क्या था पुराना सिस्टम

किलोग्राम को मापने के पुराने सिस्टम में किलो का वजन गोल्फ की गेंद के आकार की प्लेटिनिम इरिडियम की गेंद के सटीक वजन के समान होता है। यह गेंद कांच के जार में पेरिस के पास वर्साय की ऑर्नेट बिल्डिंग की सेफ में रखी हुई है।

इस सेफ तक पहुंचने के लिए उन तीन लोगों की ज़रूरत होती है, जिनके पास तीन अलग अलग चाबियां हैं। ये तीनों लोग तीन अलग–अलग देशों में रहते हैं। इन चाबियों की मदद से ही इस सेफ को खोला जा सकता है। इसकी निगरानी इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स करती है ।

नासा ने मंगल 2020 रोवर के उतरने वाले स्थान के तौर पर प्राचीन गढ्ढे को चुना

द रीव टाइम्स ब्यूरो

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सोमवार को कहा कि उसने 3.6 अरब साल पुराने एक गढ्ढे (क्रेटर) को मानवरहित मंगल 2020 रोवर मिशन के उतरने वाले स्थान के तौर पर चुना है। इस मिशन का लक्ष्य, लाल ग्रह पर पूर्व में अगर कोई जीवन रहा है तो उसके संकेतों का पता लगाना है । नासा ने पांच साल की खोज के बाद जेजेरो क्रेटर का चयन किया है । इन पांच सालों के दौरान मंगल पर करीब 60 स्थानों के संबंध में उपलब्ध प्रत्येक ब्यौरे को मिशन टीम और ग्रह विज्ञान से जुड़े समूहों ने बारीकी से देखा और उस पर चर्चा की । अंतरिक्ष एजेंसी ने एक बयान में कहा कि लाल ग्रह की खोज के नासा के अगले कदम के तहत रोवर मिशन जुलाई 2020 में वहां भेजा जाएगा । बयान में बताया गया कि यह मिशन न सिर्फ रहने योग्य पुरानी स्थितियों और सूक्ष्मजीवों के पूर्व के जीवन के संकेतों का पता लगाएगा बल्कि रोवर पत्थरों एवं मिट्टी के नमूने भी इकठ्ठे करेगा और ग्रह की सतह पर एक भंडार में जमा करेगा । नासा के विज्ञान मिशन निदेशालय के सहायक प्रशासक थॉमस जुरबुचेन ने कहा, 'जेजेरो कार्टर में मिशन के उतरने वाली जगह भौगोलिक रूप से समृद्ध इलाका है जहां जमीन 3.6 अरब साल से भी पुराने समय से अपने प्राकृतिक रूप में मौजूद है जो ग्रह की उत्पत्ति एवं खगोल जीव विज्ञान से जुड़े अहम सवालों का संभवतः उत्तर दे सकती हैं।'

मालदीव में भारत को बड़ी बढ़त, नई सरकार ने कहा चीन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को करेंगे खत्म

बीते साल सत्ता से बेदखल हुए अब्दुल्ला यामीन ने चीन से किया था फ्री ट्रेड अग्रीमेंट

मौजूदा सरकार के मुखिया ने किया करार खत्म करने का ऐलान, द्वीपीय देश में कम होगा ड्रैगन का प्रभाव

मालदीव सरकार ने करार को बताया वन वे, कहा-चीन हमसे कोई सामान नहीं खरीदता

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मालदीव में नई सरकार के गठन के साथ ही चीन का दखल वहां कम होने लगा है और कूटनीतिक पलड़ा भारत की ओर से झुकता दिख रहा है। नई बनी गठबंधन सरकार में शामिल सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया ने ऐलान किया है कि मालदीव चीन के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से बाहर निकलेगा। उन्होंने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी के साथ किए गए करार को द्वीपीय देश की एक गलती करार दिया।

इस ऐलान के साथ ही समुद्री किनारों पर शानदार रिजॉर्ट्स के लिए चर्चित देश में भारत कूटनीतिक और रणनीतिक रूप से मजबूत पकड़ बनाता दिख रहा है। सत्ताधारी गठबंधन का नेतृत्व करने वाले मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के चीफ मोहम्मद नशीद ने कहा, 'चीन और मालदीव के बीच व्यापारिक असंतुलन बहुत ज्यादा है और कोई भी ऐसी स्थिति में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बारे में सोच नहीं सकता।'

उन्होंने इस समझौते को वन–वे करार देते हुए कहा कि चीन हमसे कुछ नहीं खरीदता है। बता दें कि शनिवार को अपना कार्यभार संभालने पर प्रेजिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सालेह ने कहा था कि देश के खजाने को लूटा गया है। पिछली सरकार पर बरसते हुए उन्होंने कहा था कि देश चीन से भारी कर्ज लेने के चलते संकट के दौर से गुजर रहा है।

सूर्य के निकटतम एकल तारे का चक्कर लगा रहा 'सुपर अर्थ'

द रीव टाइम्स ब्यूरो

खगोल विज्ञानियों ने सूर्य के निकटतम एकल तारे का चक्कर लगा रहे जमे हुए एक 'सुपर अर्थ' का पता लगाया है जिससे पृथ्वी के निकटतम पड़ोसी ग्रहों के बारे में जानकारियां सामने आ सकती हैं। ब्रिटेन के क्वीन मैरी लंदन यूनिवर्सिटी के अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार संभवतः चट्टानों वाला यह ग्रह धरती से भी बड़ा है और उसे 'बर्नार्ड्स स्टार बी' के नाम से जाना जाता है।

वैज्ञानिकों के मुताबिक, यह सुपर अर्थ अपने मेजबान तारे का 233 दिनों में चक्कर लगाता है। विज्ञान पत्रिका जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन के अनुसार यह ग्रह अपने मेजबान तारे से इतना दूर है जिसे 'स्नो लाइन' कहा जाता है। यानी इस दूरी पर पानी, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी चीजें ठंड की वजह से जम जाती हैं।

अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार, इस ग्रह की दशाएं पर्यावास क्षेत्र से परे हैं। पर्यावास क्षेत्र में द्रव पानी और संभवतः जीवन का अस्तित्व होता है। उन्होंने कहा कि इस ग्रह की सतह का तापमान शून्य से करीब 170 डिग्री सेल्सियस नीचे है। इसका मतलब है कि यह ऐसी जमी हुई दुनिया है जहां धरती जैसे जीवन के अनुकूल दशाएं नहीं हैं।

द रीव टाइम्स संस्थापकः डॉ. एल.सी. शर्मा, द रीव टाइम्स पब्लिकेशन के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक श्री प्रदीप कुमार जरेट द्वारा एपोसिएट प्रैस सायबू निवास समीप सेक्टर -2, बस स्टैंड मिडल मार्केट न्यू शिमला-9, हि.प्र. से प्रकाशित एवं मुद्रित
प्रधान सम्पादकः डा. एल.सी. शर्मा, प्रबन्ध सम्पादकः आनन्द नायर
फोन न. 0177 2640761, मेलः editor@themissionriev.com
RNI Reference No. 1328500

द रीव टाइम्स
आपकी आवाज़ ही है
हमारी आवाज़

सामान्य ज्ञान

क्या आप जानते हैं .....

1 पृथ्वी का एक मात्र प्राकृतिक उपग्रह है ।
उत्तर दृ चन्द्रमा

2 'गाँधी' फिल्म में गाँधी की भूमिका किसने निभाई ?
उत्तर : बेन किंग्सले

3 शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है?
उत्तर : 5 सितंबर

4 जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था?
उत्तर : 1945 में

5 भांखड़ा नंगल बाँध किस नदी पर है?
उत्तर : सतलुज

6 भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है?
उत्तर : कमल

7 धनराज पिल्लै किस खेल से सम्बंधित है?
उत्तर : हॉकी

8 सयुंक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् में कितने स्थाई सदस्य है ?
उत्तर : 5

9 कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है ?
उत्तर : हड़प्पा

10 चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था?
उत्तर : मराठो द्वारा

11 मुगल बादशाहो का सही क्रम है ।
उत्तर : बाबर, हुमायूँ, शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, हुमायूँ, अकबर–ए–आजम, जहांगीर, शाह–जहाँ–ए–आजम, अलामगीर, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुख्शियार, रफी उल–दर्जत, शाहजहां द्वितीय, मुहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय

12 'भूदान आंदोलन' किसने शुरू किया किया था?
उत्तर : विनोभा भावे

13 भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू की थी?
उत्तर : लार्ड मैकाले

14 'फ्लाइंग सिख' के नाम से किसे जाना जाता है?
उत्तर : मिल्खा सिंह

15 नींबू और सन्तरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है?
उत्तर : विटामिन 'सी'

16 उदय शंकर किससे सम्बंधित है?
उत्तर : नृत्य

17 संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे?
उत्तर : डॉ. भीम रॉव अम्बेडकर

18 त्रि–स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है?
उत्तर : जिला परिषद

19 लक्षदीप की राजधानी है।
उत्तर : करवती

20 श्री लंका की मुद्रा का नाम है।
उत्तर : रुपया

21 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' नामक पुस्तक किसने लिखी थी?
उत्तर : जवाहर लाल नेहरू

22 'गुरुत्वाकर्षण' की खोज किसने की थी?
उत्तर : न्यूटन

23 नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है।
उत्तर : रविन्द्र नाथ टेगोर

24 द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे सम्बंधित है?
उत्तर : श्रेष्ठ गुरु / प्रशिक्षक

25 खजुराहो स्थित है–
उत्तर : मध्य प्रदेश

26 राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है।
उत्तर : देहरादून

27 रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी?
उत्तर : स्वामी विवेकानंद

28 भारतीय मानक समय आधारित है।
उत्तर : 82' 30' पूर्व देशान्तर पर

29 कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है?
उत्तर : अरुणाचल प्रदेश

30 कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है?
उत्तर : चीन

31 पृथ्वी के नजदीक वायुमण्डल की सबसे निचली परत है–
उत्तर : क्षोभ मण्डल

32 भारतीय सेना में 'विजयंत' नाम है–
उत्तर : एक टैंक का

33 चीनी यात्री फाह्यान किसके काल में भारत आया था?
उत्तर : विक्रमादित्य

34 प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राजकपूर में सम्बन्ध है।
उत्तर : बाप–बेटे का

35 भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है।
उत्तर : असम

36 भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है
उत्तर : पश्चिम बंगाल

37 भारत के किस शहर में जंतर–मंतर स्थित है?
उत्तर : दिल्ली

38 भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है?
उत्तर : पश्चिम बंगाल

39 तेलगु किस राज्य की राजभाषा है?
उत्तर : आंध्रप्रदेश

40 हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते है–
उत्तर : 11

41 बांग्लादेश की मुद्रा है
उत्तर : टका

42 नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था?
उत्तर : मिश्र सभ्यता

43 किस स्थान पर महात्मा बुध ने ज्ञान प्राप्त किया था?
उत्तर : गया

44 प्रसिद्ध नाटक 'शकुंतला' किसने लिखी थी?
उत्तर : महाकवि कालिदास

45 ज्वार सबसे ऊँचा कब होता है–
उत्तर : जब सूर्य और चन्द्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते है

46 कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नही है?
उत्तर : मध्य प्रदेश

47 खैबर दर्रा स्थित है–
उत्तर दृ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच

48 कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नही निकलती है
उत्तर : यमुना

49 कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है
उत्तर : कानपुर

50 भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है–
उत्तर : भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नही है

51 राष्ट्रीय राजमार्ग (नेशनल हाइवे) जोड़ते हैं
उत्तर : व्यापार केन्द्रो और राज्य की राजधानियों को

52 कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है?
उत्तर : नासिक

मैरी कॉम ने छठा विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीतकर बनाया विश्व रिकॉर्ड बनाया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारत की दिग्गज महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी एम. सी. मैरी कॉम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अगर इरादे बुलंद हो तो सफलता के रास्ते न तो उम्र और न ही मजबूरियां रोड़ा बन सकती हैं। मैरी ने 24 नवंबर 2018 को आईबा महिला विश्व मुक्केबाजी चैम्पियनशिप के 10वें संस्करण में 48 किलोग्राम भार वर्ग का खिताब अपने नाम कर फिर अपना लोहा मनवाया है। मैरी कॉम ने फाइनल में यूक्रेन की हना ओखोटा को 5–0 से हराया। इसी के साथ मैरीकॉम छह वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं।

मैरी कॉम के रिकॉर्ड

- मैरी कॉम ने 2002, 2005, 2006, 2008 और साल 2010 में विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपनी झोली में डाला था।
- मैरी कॉम ने एक खिताब 45 किग्रा, तीन वर्ल्ड खिताब 46 किग्रा भार वर्ग और आखिरी दो खिताब 48 किग्रा वजन वर्ग मे जीते हैं।
- इसके अलावा वर्ष 2001 में मैरी कॉम इसी भार वर्ग में उपविजेता रही थीं और उन्होंने सिल्वर पदक जीता था.
- मैरी कॉम विश्व चैंपियनशिप (महिला एवं पुरुष) में सबसे अधिक पदक भी जीतने वाली खिलाड़ी बन गई हैं।
- मैरी कॉम छह स्वर्ण और एक रजत जीत कर क्यूबा के फेलिक्स सेवोन (91 किलोग्राम भारवर्ग) की बराबरी की। फेलिक्स ने 1986 से 1999 के बीच छह स्वर्ण और एक रजत पदक जीता था।

समीर वर्मा ने जीता सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारत के स्टार शटलर समीर वर्मा ने 25 नवम्बर 2018 को चीन के लू ग्वांगझू को हराकर लगातार दूसरी बार सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। उन्होंने खिताबी मुकाबले में चीन के लू ग्वांगझू को 16–21, 21–19, 21–14 से हराया।

समीर वर्मा ने लगातार दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया। उन्होंने पिछले साल बी साई प्रणीत को हराकर यह खिताब अपने नाम किया था।उन्होंने इस साल भी यह खिताब बरकरार रखा है। वहीं, समीर हमवतन शटलर पी. कश्यप के बाद दो बार यह टूर्नामेंट जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष शटलर हैं। समीर से पहले वर्ष 2016 में किदांबी श्रीकांत और वर्ष 2015 में पी कश्यप चैम्पियन बने थे।

हॉकी विश्व कप 2018 का भुवनेश्वर में शुभारंभ

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हॉकी विश्व कप 2018 का भुवनेश्वर में आयोजित किया जा रहा है। मेजबान भारत 14वें हॉकी विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत की। यह मैच भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम पर खेला जा रहा है।

मेजबान भारत का पहला मैच दक्षिण अफ्रीका से हुआ। आठ बार के ओलंपिक चैंपियन भारत ने अब तक सिर्फ एक बार विश्व कप जीता है। हॉकी के इस महाकुंभ में विश्व की कुल 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो 28 नवंबर से 16 दिसंबर 2018 तक चलेगा।

16 टीमों को चार ग्रुपों में बांटा गया

विश्व कप में 16 टीमों को चार ग्रुपों में बांटा गया है। मेजबान भारत को पूल 'सी' में जगह मिली है जबकि पाकिस्तान को पूल 'डी' में रखा गया है।

विश्व कप हॉकी

विश्व कप हॉकी की शुरुआत वर्ष 1971 में हुई थी और अभी तक पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा चार बार खिताब पर कब्ज़ा किया है। ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड्स ने तीन–तीन और जर्मनी ने दो बार विश्व कप पर कब्ज़ा किया है। भारत ने वर्ष 1975 में विश्व कप जीता था। उसके बाद आज तक भारत विश्व कप नहीं जीत पाया है। भारत में तीसरी बार हॉकी विश्व कप का आयोजन हो रहा है। इससे पहले वर्ष 1982 और वर्ष 2010 में भारत हॉकी विश्व कप का आयोजन कर चुका है।

भारत 43 साल से नहीं जीता कोई पदकः

वर्ष 1975 के बाद से एशियाई धुरंधर भारतीय टीम नीदरलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के स्तर तक पहुंचने में नाकाम रही। पिछले चार दशक से यूरोपीय टीमों ने विश्व हॉकी पर दबदबा बनाये रखा है। भारत के नाम केवल एक स्वर्ण पदक (1975), एक रजत पदक (1973) और एक कांस्य पदक(1971) सहित कुल तीन पदक हैं।

बात अगर रैंकिंग की हो तो हॉकी रैंकिंग में इस समय ऑस्ट्रेलिया पहले पायदान पर है। चार बार हॉकी विश्व कप का खिताब अपने नाम कर चुके पाकिस्तान की भूमिका भी इस टूर्नामेंट में काफी अहम मानी जा रही है। पिछली बार हॉकी विश्व कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। वह फाइनल में नीदरलैंड को हराकर वर्ष 2014 में चैंपियन बना था।

भारतीय टीमः

गोलकीपरः– पी.आर.श्रीजेश, कृष्णन बहादुर पाठक

डिफेंडरः– हरमनप्रीत सिंह, गुरिंदर सिंह, वरुण कुमार, कोथाजीत सिंह, सुरेंद्र कुमार, जर्मनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह

मिडफील्डरः– मनप्रीत सिंह (कप्तान), सुमित, नीलकंठ शर्मा, ललित कुमार उपाध्याय, चिंग्लेसाना सिंह

फारवर्डः– आकाशदीप सिंह, गुरजंत सिंह, मनदीप सिंह और दिलप्रीत सिंह

रणजी ट्रॉफी में 11,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने वसीम जाफर

भारतीय टेस्ट टीम के पूर्व ओपनर वसीम जाफर ने रणजी ट्रॉफी में 11,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। जाफर ने विदर्भ की तरफ से बड़ौदा के खिलाफ 153 रन की शानदार खेली और इस बीच 11,000 रन भी पूरे किए. जाफर ने इस बीच फैज फजल (151) के साथ 300 रन की साझेदारी की। जाफर के नाम पर रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक 37 शतक और 81 अर्धशतक भी दर्ज हैं। रणजी ट्रॉफी देश की सबसे प्रतिष्ठित घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी का आरंभ जुलाई 1934 में हुआ था। प्रतियोगिता का पहला मैच 4 नवंबर 1934 को चेपक स्टेडियम में मद्रास और मैसूर के बीच आयोजित किया गया था। इसका नाम भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी रणजीत सिंह के नाम पर पड़ा, जिन्हें प्यार से रणजी कहा जाता था। रणजी ट्रॉफी का प्रारूप दो चरणों में होता है। पहले चरण में राउंड–रॉबिन लीग मैच खेले जाते हैं दूसरे चरण में यह नॉक–आऊट हो जाता है। राउंड रोबिन मैच के लिए चार दिन और नॉकआउट मैच के लिए यह सीमा पांच दिन है। इसमें प्रत्येक टीम को दो बार बल्लेबाज़ी और दो बार गेंदबाज़ी करनी होती है। नॉकआउट चरण में यदि मैच ड्रॉ रहता है तो पहले पारी के आधार पर टीम को जीत मिलती है।

शांतनु नारायण फॉर्च्यून बिजनेस पर्सन ऑफ द इयर सूची में

एडोबी के सीईओ, सूची में 12वां स्थान

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक शांतनु नारायण को 2018 की 'फॉर्च्यून बिजनेस पर्सन ऑफ द इयर' लिस्ट में शामिल किया गया है। नारायण दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी एडोबी के सीईओ हैं। इस लिस्ट में कुल 20 लोगों के नाम हैं, जिसमें नारायण को 12वां स्थान मिला है। इस प्रतिष्ठित लिस्ट में बीमा कंपनी प्रोग्रेसिव की सीईओ ट्रिसिया ग्रिफिथ को पहला स्थान मिला है। इसके अलावा ग्राफिक चिपमेकर एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेनसेन हुआंग, फ्रेंच ग्रुप केरिंग के सीईओ फ्रांकोइस–हेनरी पिनॉल्ट, अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस और पेपाल के सीईओ डैन स्कलमैन भी फॉर्च्यून की इस लिस्ट के हिस्सा हैं।

फिच का अनुमान, इस वित्त वर्ष 7.8 फीसद रहेगी भारत की ग्रोथ रेट

लगातार 12वें साल भी भारत की रेटिंग नहीं बदली

द रीव टाइम्स ब्यूरो

दुनिया की अग्रणी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने चालू वित्त वर्ष (2018–19) के दौरान देश की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) विकास दर 7.8 फीसद के ऊंचे स्तर पर रहने का अनुमान लगाया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट में एजेंसी का मानना है कि मध्यम अवधि में देश की अर्थव्यवस्था स्थिर रहने के मजबूत संकेत हैं। वहीं सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष अक्टूबर में देश की निर्यात विकास दर पिछले वर्ष समान अवधि के मुकाबले 17.86 फीसद ज्यादा रही है। लगातार 12वें साल भी भारत की रेटिंग नहीं बदली बीते वित्त वर्ष यानी 2017–18 में देश की आर्थिक विकास दर 6.7 फीसद रही थी। इस लिहाज से चालू वित्त वर्ष के लिए यह अपेक्षाकृत मजबूत विकास दर है। अगले वित्त वर्ष यानी 2019–20 और उसके अगले वित्त वर्ष यानी 2020–21 के लिए एजेंसी ने देश की विकास दर 7.3 फीसद रहने का अनुमान लगाया है। हालांकि फिच द्वारा देश की अर्थव्यवस्था की रेटिंग लगातार 12वें वर्ष भी नहीं बदलना चौंकाने वाला फैसला है। एजेंसी ने भारत की रेटिंग 'बीबीबी–' पर बनाये रखने का फैसला किया है। स्थिर आउटलुक के साथ निवेश के लिहाज से यह सबसे निचली रेटिंग है। फिच द्वारा रेटिंग नहीं बदलने का फैसला इसलिए भी हैरानी भरा है, क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार इस बात का प्रयास किया जा रहा था कि एजेंसी भारत के लिए अपनी रेटिंग में सुधार करे। खासतौर पर पिछले वर्ष नवंबर में एक अन्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज की तरफ से रेटिंग में सुधार किये जाने के बाद इसकी उम्मीद लगायी जा रही थी कि फिच भी ऐसा कर सकता है।

यूरोपियन यूनियन में इस वजह से बंद हो सकता है गूगल न्यूज

द रीव टाइम्स ब्यूरो

यूरोपियन यूनियन में एक टैक्स की वजह से गूगल न्यूज की सेवाएं बंद हो सकती है। दरअसल, यूरोपियन यूनियन में यदि खबरों के लिए प्रस्तावित "लिंक टैक्स" का नियम लागू होता है तो गूगल यूरोपियन यूनियन में अपनी गूगल न्यूज की सेवाएं बंद कर सकता है। कॉपीराइट के नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, जिसे यूरोपियन पार्लियामेंट की ओर से 12 सितंबर को अपना लिया गया है, तकनीकी क्षेत्र की बड़ी कंपनी को कलाकार एवं पत्रकार के उस काम के लिए भुगतान करना होगा जिसका वो इस्तेमाल कर रही होगी। नियमों को लागू करने के लिए, व्यक्तिगत सदस्य देशों को स्थानीय कानूनों का एक मसौदा तैयार करना होगा। सर्च इंजन के न्यूज सेक्शन के वाइस प्रेसिडेंट रिचर्ड गिंग्रास के मुताबिक गूगल वर्तमान प्रस्तावों के बारे में गहराई से सोच रहा है, जो कि संघर्षशील समाचार प्रकाशकों की उस सूरत में क्षतिपूर्ति के लिए डिजाइन किए गए हैं अगर खोज परिणामों में उनके आर्टिकल्स के स्निपेट दिखाई देते हैं।

उन्होंने कहा कि गूगल समाचार का भविष्य अब इस बात पर निर्भर हो सकता है कि यूरोपीय संघ कानून में बदलाव को इच्छुक है या नहीं। उन्होंने कहा, "हम जब तक इस मामले में आखिरी रुख को नहीं देख लेते हम फैसला नहीं ले सकते हैं।"

द रीव टाइम्स
आपकी आवाज़ ही है हमारी आवाज़

राष्ट्रीय समसामयिक घटनाक्रम

द रीव टाइम्स ब्यूरो

1 . हाल ही में, किस व्यक्ति को वर्ष 2017 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है?
(इ) सचिन तेंदुलकर (ब) मनमोहन सिंह
(क) राहुल द्रविड़
उत्तर– (ब) मनमोहन सिंह

2. हाल ही में, बीबीसी ने विश्व की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची की, जिसमे किन 3 भारतीय महिलाओं को जगह मिली है?
(इ) मीना गाएन, विजी पेनकुट्टू और रहीबी सोमा
(ब) पूजा शर्मा, अंकिता अरोरा और विशाखा सिंह
(क) सना खान, मोनिका चौधरी और पिंकी ओला
उत्तर– (इ) मीना गाएन, विजी पेनकुट्टू और रहीबी सोमा

3. विश्व शौचालय दिवस हर वर्ष मनाया जाता है?
(इ) 19 नवंबर को
(ब) 15 नवंबर को (क) 11 नवंबर को
उत्तर– (इ) 19 नवंबर को

4. हाल ही में, किस व्यक्ति की आत्मकथा '281 एंड बियॉन्ड' लॉन्च हुई है?
(इ) सोनू निगम (ब) अन्ना हजारे
(क) वीवीएस लक्ष्मण
उत्तर– (क) वीवीएस लक्ष्मण

5. कौन प्रवर्तन निदेशालय के पूर्णकालिक निदेशक बनाए गये है?
(इ) संजय कुमार मिश्रा (ब) अतुल परिहार
(क) दिग्विजय देवगन
उत्तर– (इ) संजय कुमार मिश्रा

6. हाल ही में, कौन भारतीय यूनिसेफ इंडिया की युवा एंबेसडर बनाई गईं है?
(इ) साक्षी मलिक (ब) हिमा दास
(क) सानिया मिर्जा
उत्तर– (ब) हिमा दास

7. दिल्ली पुलिस ने कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम है?
(इ) निपुण (ब) ई–ट्रेनिंग
(क) सक्षम
उत्तर– (इ) निपुण

8. हाल ही में, रामायण में वर्णित प्रमुख स्थानों हेतु एक ट्रेन शुरू हुई है, जिसका नाम है?
(इ) रामायण एक्सप्रेस (ब) श्रीराम एक्सप्रेस
(क) अयोध्या एक्सप्रेस
उत्तर– (इ) रामायण एक्सप्रेस

9. हाल ही में, कौन भारतीय 65 किलोग्राम वर्ग में दुनिया के नंबर एक पहलवान बने है?
(इ) बजरंग पूनिया (ब) सुशिल कुमार
(क) उदय चंद
उत्तर– (इ) बजरंग पूनिया

10. हाल ही में, किस शहर में भारत का पहला जलमार्ग बंदरगाह आरंभ हुआ है?
(इ) वाराणसी (ब) जोधपुर (क) भोपाल
उत्तर (इ) वाराणसी

11. हाल ही में, 4 व्यक्तियों ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में शपथ ली है, जिनमे कौन शामिल नही है?
(इ) सुभाष चावला (ब) एमआर शाह
(क) अजय रस्तोगी
उत्तर– (इ) सुभाष चावला

12. हाल ही में, जारी ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट में भारत को कौनसा स्थान मिला है?
(इ) 77वां (ब) 66वां (क) 20वां
उत्तर– (इ) 77वां

13. हाल ही में, कौन एशियन स्नूकर टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने है?
(इ) गीत सेठी (ब) पंकज आडवाणी
(क) मनन चन्द्र
उत्तर– (ब) पंकज आडवाणी

14. भारत ने हाल ही में, किस देश के साथ हाई स्पीड रेल परियोजना और नौसेना सहयोग सहित 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए है?
(इ) जापान (ब) फ्रांस (क) दक्षिणी अफ्रीका
उत्तर– (इ) जापान

15. कौन श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किये गये है?
(इ) नुवान प्रतापा (ब) महिंद्रा राजपक्षे
(क) योगोमो मुकाम्बो
उत्तर– (इ) महिंद्रा राजपक्षे

16. कौन व्यक्ति हाल ही में, ब्राज़ील के नये राष्ट्रपति चुने गये है?
(इ) जेयर बोलसोनारो (ब) ब्लूटो रुआक
(क) जेसन मार्क
उत्तर– (इ) जेयर बोलसोनारो

17. किन 2 टीमों ने एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2018 का ख़िताब संयुक्त रूप से जीता है?
(इ) भारत – पाकिस्तान
(ब) जापान – कोरिया (क) भारत – ओमान
उत्तर– (इ) भारत – पाकिस्तान

18. कौन व्यक्ति हाल ही में, प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किये गये है?
(इ) जयदेव शर्मा
(ब) नवदीप लोखंडवाला
(क) संजय मिश्रा
उत्तर– (क) संजय मिश्रा

19. हाल ही में, 'मदन लाल खुराना' का निधन हुआ है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे?
(इ) दिल्ली (ब) मणिपुर
(क) असम
उत्तर– (इ) दिल्ली

20. उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हाल ही में, किस देश में भारतीय सैनिकों के सम्मान में स्मारक का उद्घाटन किया है?
(इ) फ्रांस (ब) श्रीलंका
(क) चीन
उत्तर– (इ) फ्रांस

हिमाचल : एक रुपये में करवाएं अपना इलाज

365 रुपये में साल भर लें यूनिवर्सल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम का लाभ

योजना के तहत 365 रुपये देकर स्मार्ट कार्ड बनाया जाता है और इसमें परिवार के पांच सदस्य शामिल होते हैं।

द रीव टाइम्स

हिमाचल में स्वास्थ्य क्षेत्र सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। प्रदेश में हर वर्ग को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से कोई न कोई योजना है। अगस्त 2017 में हिमाचल में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम (एचपीयूएचपीएस) लॉच की गई और इसके साथ ही लॉच किया गया ई–हैल्थ कार्ड। इस लॉचिंग के साथ ही यह सुविधा देने वाला हिमाचल पहला राज्य बना था। दरअसल एचपीयूएचपीएस उन लोगों के लिए लॉच की गई है जो किसी अन्य स्वास्थ्य योजना के तहत कवर नहीं होते। प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रह–रहे बीपीएल परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाइ), मुख्यमंत्री स्टेट हेल्थ कार्ड स्कीम और मेडिकल रिइंबर्समेंट स्कीम के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा प्राप्त होती है, लेकिन जो लोग इस श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें इलाज के लिए पैसे खर्च करने पड़ते थे। जबकि एचपीयूएचपीएस योजना से सामान्य वर्ग के लोगों को भी बेहद सस्ते इलाज का लाभ सरकारी अस्पतालों में मिलता है।

365 रुपये में साल भर इलाज

योजना का लाभ लेने के लिए मरीज को एक बार 365 रूपये में कार्ड बनाना होता है। इसके बाद कार्ड धारक पूरे साल सरकारी अस्पताल में निशुल्क इलाज करवा सकता है। यानि प्रतिदिन एक रूपये में सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाया जा सकता है। दरअसल यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की तरह काम कर रही है और जिन परिवारों के स्मार्ट हेल्थ कार्ड नहीं बने हैं या किसी अन्य योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ नहीं ले रहे हैं, उन्हें इसमें शामिल किया जाता है। इस योजना के तहत अस्पताल में दाखिल होने पर 30 हजार से 1.75 लाख रुपये मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। योजना के तहत 365 रुपये देकर स्मार्ट कार्ड बनाया जाता है और इसमें परिवार के पांच सदस्य शामिल होते हैं। ऐसे में अगर कोई बीमार होता है तो अस्पताल में दाखिल होने पर 30 हजार से 1.75 लाख रुपये तक के इलाज की मुफ्त सुविधा मिलेगी। एक अनुमान के अनुसार हिमाचल में करीब 39 प्रतिशत लोग किसी भी स्वास्थ्य योजना के तहत कवर नहीं होते।

कैंसर रोगियों के लिए 2.75 लाख रुपये तक का इलाज निशुल्क

अगर कोई कैंसर का मरीज होता है तो उसका 2.25 लाख रुपये तक इलाज निःशुल्क कराने की व्यवस्था है। यही नहीं हृदय और अन्य गंभीर बीमारियों में भी यह सुविधा मिलती है। प्रदेश में वर्तमान में पांच लाख परिवारों और मुख्यमंत्री योजना के तहत दो लाख सरकारी कर्मचारियों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है।

यूं बनेगा कार्ड

योजना के तहत संबंधित कंपनी सभी मुख्य अस्पतालों में कार्ड बनाने की प्रक्रिया पर काम कर रही है। इसके लिए परिवार के सभी सदस्यों को मौके पर होना जरूरी होता है। मौके पर उनके हाथ के निशान और फोटो ली जाती है और उन्हें कार्ड जारी कर दिया जाता है। हालांकि साइबर कैफे और लोकमित्र केंद्रों में पंजीकरण करवाते हैं तो इसके लिए 450 रुपये तक चुकाने पड़ते हैं।

ये भी योजना

18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निशुल्क इंसुलिन

हिमाचल में 200 से अधिक बच्चे हैं टाइप –1 मधुमेह के शिकार

हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम लॉच करने के साथ ही हिमाचल में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निशुल्क इंसुलिन की सुविधा की भी शुरूआत की गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हिमाचल में करीब 200 बच्चे टाइप –1 मधुमेह की गंभीर बीमारी से पीड़ित है।

क्या है इंसुलिन

हमारे शरीर के अग्नाशय से इन्सुलिन हार्मोन का स्राव होता है। यह इन्सुलिन हार्मोन ही शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कण्ट्रोल करने में सहायक होता है। जब इन्सुलिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता तब "मधुमेह के रोग" का जन्म होता है। हमारे शरीर में भोजन पचाने की जिम्मेदारी "पाचनतंत्र" की होती है। अग्नाशय (पैंक्रियाज) इसी पाचनतंत्र का एक हिस्सा होता है। अग्नाशय हमारे लिवर के ओर स्थित होता है और यह छोटी आंत के आरम्भिक सिरे से जुड़ा हुआ होता।

मधुमेह के रोगियों में इन्सुलिन सही मात्रा में नहीं बन पाता तो इसे टाइप –1 कहा जाता हैं। जबकि टाइप –2 में कम इंसुलिन बनता है और अगर बनता भी है तो शरीर उसका इस्तेमाल सही से नहीं कर पाता। इन दोनों ही स्थिति को "मधुमेह" कहते हैं।

क्या होता है जब इन्सुलिन नहीं बनता

मधुमेह होने पर अग्नाशय की बीटा सेल्स की कार्यक्षमता बहुत कम हो जाती है। मधुमेह का रोगी जब भोजन करता है तो उसके शरीर में ग्लूकोज का

लेवल बढ़ जाता है लेकिन बीटा सेल्स पर्याप्त इन्सुलिन नहीं बना पातीं और ग्लूकोज पूरी तरह "ग्लाइकोजन" में परिवर्तित नहीं हो पाता और काफी सारी शुगर रोगी के रक्त में ही रह जाती है। मांसपेशियों में भी जरुरत के अनुसार एनर्जी नहीं पहुंच पाती इसीलिए मधुमेह के रोगी को ज्यादा भूख लगती है क्यूंकि पेट तो भर जाता है लेकिन मांसपेशियां भूखी रह जाती हैं उनको पर्याप्त एनर्जी नहीं मिल पाती। जब रक्त में बहुत अधिक ग्लूकोज बढ़ने लगता है तो यह रक्त के प्रवाह और अन्य अंगों पर दुष्प्रभाव डालने लगता है। इस अवस्था में हमारा शरीर ग्लूकोज को पेशाब के मार्ग से शरीर के बाहर निकालना शुरू कर देता है, बार बार पेशाब का आना या मधुमेह की पहचान भी है।

कृत्रिम इंसुलिन

मधुमेह रोगियों के लिए वैज्ञानिकों ने कृत्रिम इन्सुलिन बनाना आरम्भ किया है। जब शरीर में ग्लूकोज बहुत ही अधिक बढ़ जाता है तो इन्सुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। इन्सुलिन शरीर में पहुंचते ही अपना कार्य शुरू कर देता है और जल्दी ही ग्लूकोज का लेवल नियंत्रित हो जाता है। सबसे पहले इन्सुलिन बैल के अग्नाशय से बनाया गया था जिसे "वोभाइन इंसुलिन" का नाम दिया गया था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने सूअर के अग्नाशय से "पोरसीन इंसुलिन" बनना शुरू किया परन्तु इसमें सूअर और बैलों को मारना पड़ता था। आधुनिक समय में डी.एन.ए. रीकोम्बीनेट नामक तकनीक से शुद्धतम "मानव इंसुलिन" बनाया जाता है। इन्सुलिन का सेवन डॉक्टर के परामर्श पर ही करना चाहिए क्यूंकि जरुरत से ज्यादा इन्सुलिन लेना आपका ग्लूकोज का लेवल बहुत कम भी कर सकता है जिससे व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है।

हीमोफिलिया का भी हिमाचल में निशुल्क इलाज

इंसुलिन के साथ ही हिमाचल में हीमोफिलिया के लिए भी निशुल्क इलाज की व्यवस्था की गई है। हेमोफिलिया एक आनुवांशिक बीमारी है, जो माता–पिता से होने वाले बच्चे में भी जा सकती है। गुणसूत्र इस बीमारी की वाहक (आगे भेजने वाली) होते हैं, और यह बीमारी पुरुषों में ज्यादा देखने को मिलती है। जब कोई व्यक्ति हीमोफीलिया से पीड़ित होता है, और उन्हें थोड़ी बहुत भी चोट लग जाती है, तो उनका खून बहना रुकता नहीं है, क्योंकि हीमोफिलिया से पीड़ित लोगों में चोट लगने पर रक्त के पर्याप्त थक्के नहीं जमते हैं। ऐसे में यदि इस तरह के लोगों का एक्सीडेंट हो जाए, तो यह उनकी जिंदगी के लिए घातक भी हो सकता है, क्योंकि एक्सीडेंट में आई चोट के बाद इन लोगों में खून के बहाव को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अगर यह बीमारी परिवार के किसी भी सदस्य को है तो उसे बहुत सावधानी से रहना चाहिए।

चिकित्सा विशेषज्ञों की मानें तो इस बीमारी को सिर्फ एंटी हेमोफिलिक (एएचएफ) से नियंत्रण में रखा जा सकता हैं, जो कि बहुत महंगी होती हैं और कुछ ही जगहों पर मिलती है। यही कारण हैं कि इस बीमारी के चलते कुछ लोगों की मौत बचपन में ही हो जाती हैं। लेकिन हिमाचल में अगस्त 2017 से इसके लिए निशुल्क कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

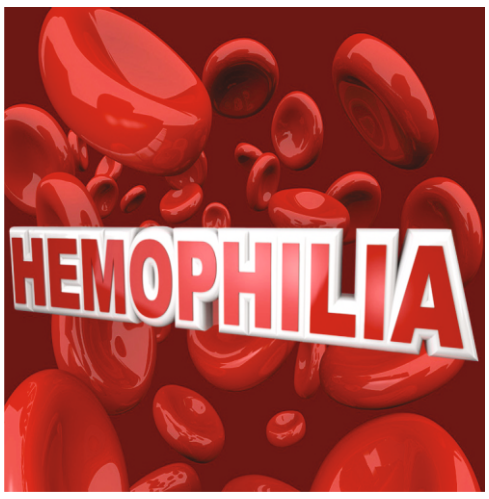

हीमोफिलिया के लक्षण

हीमोफिलिया एक आनुवांशिकी बीमारी हैं। जो माँ बाप से बच्चों में होती हैं। हीमोफिलिया की बीमारी खून में थक्के ना जम पाने की वजह से होती हैं। जो अधिकतर पुरुषों में देखने को मिलती है।

अक्वाइअर्ड हीमोफिलिया

अक्वाइअर्ड हीमोफिलिया के रोगियों में प्रतिरक्षा प्रणाली एक तरह का आठवा एंटीबॉडी बनता है जिससे खून के थक्के जमना बंद हो जाते हैं और चोट लगने पर खून बहना बंद नहीं होता है। अक्वाइअर्ड हीमोफिलिया महिलाओं और पुरुषों दोनों को प्रभावित करता है।

नाक से अधिक खून आना

हीमोफिलिया बीमारी का पहला लक्षण है नाक से अधिक खून आना। अगर किसी व्यक्ति को बेवजह नाक से बहुत खून आ रहा हो तो उसे हेमोफिलिया हो सकता है।

मसूढ़ों से खून आना

हीमोफिलिया का दूसरा लक्षण है मसूढ़ों से खून आना। अगर किसी व्यक्ति के मसूढ़ों से खून आ रहा है और रूक नहीं रहा है तो यह उसके लिए खतरनाक हो सकता है।

चोट लगने पर अधिक खून बहना

अगर किसी व्यक्ति को हल्की चोट लगने पर भी बहुत ज्यादा खून बेहता है तो उसे हीमोफिलिया की बीमारी हो सकती है।

जोड़ों में दर्द और खून आना

यदि कोई व्यक्ति हीमोफिलिया से पीड़ित है, तो उसे जोड़ों में दर्द होगा, इसका मुख्य कारण है जोड़ों में आंतरिक खून का बेहना। अगर यह स्थिति खारब हो जाती है तो जोड़ों में सूजन, दर्द और लाल पड़ने लगते हैं।

मल और मूत्र में खून आना

गुर्दे और मूत्राशय में आंतरिक खून के आने से मल और मूत्र में खून आने लगता है। जो हेमोफिलिया जैसे बीमारी का प्रमुख लक्षण है।

मस्तिष्क में खून आना

हीमोफिलिया के सबसे गंभीर मामलो में से एक है मस्तिष्क में खून आना। इसमें मस्तिष्क के अंदर खून का स्राव होने लगता है जिससे सिरदर्द, गर्दन में दर्द और उल्टी आने लगती है।

कमजोरी और डबल विज़न

कमज़ोरी महसूस करना, डबल विज़न यानी हर चीज़ दो दिखना और चलने में मुश्किल होना। यह भी हीमोफिलिया के अन्य प्रमुख लक्षण हैं।

मेक इन इंडिया अभियान.....धीमा ही सही भारत हो रहा गतिमान...

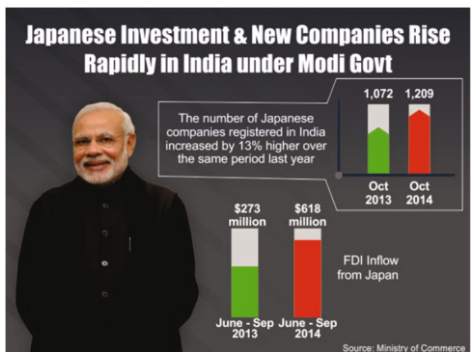

भारत सरकार ने 25 दिसम्बर 2014 को मेक इन इंडिया की एक नयी पहल की गयी एवं भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने आरंभ किया ।

▶ यह भारत सरकार का एक बहुत बड़ा और नया कदम है Make In India Campaign , Mission Bharat में नए टेक्नोलॉजी के विकास एवं भारत में बनाये जाने वाले उत्पादकों को बढ़ावा देना है ।

- Make In India Campaign का मुख्य मकसद यह है कि विदेशी कंपनी को भारत में निवेश करने के लिए प्रेरणा मिले और भारत में ही उत्पादकों को बनाने का प्रोत्साहन दिया जायेगा ।
- इस योजना में ना सिर्फ विदेशी उत्पादकों को बल्कि भारतीय कंपनी के उत्पादकों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ।

Advantages of Make In India Campaign / मेक इन इंडिया अभियान के फायदे

➡ इस अभियान की मदद से कई बेरोजगार युवाओं को रोजगार का लाभ मिल रहा है और इसी वजह से देश का विकास भी हो रहा है ।

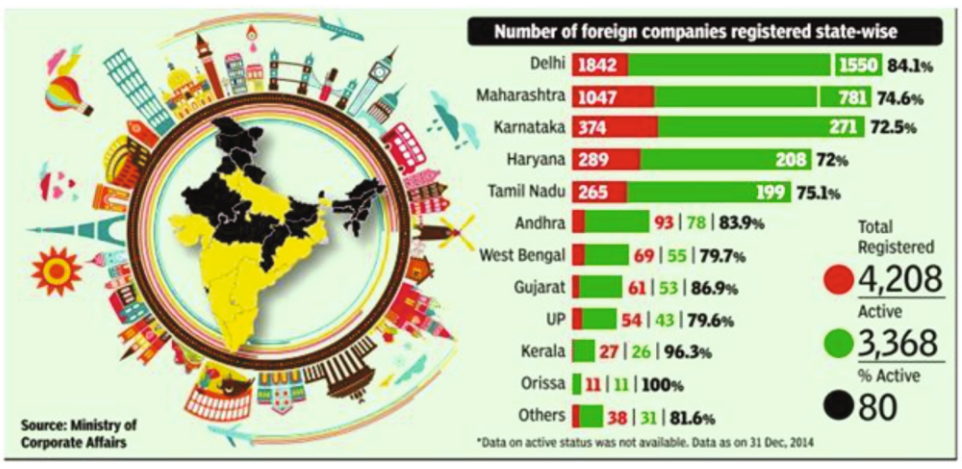

➡ Make In India Campaign की मदद से हम भारत देश को अन्य देशों की सूची में जल्द ही ला पाएंगे, क्योकि अगर विदेशी कंपनिया हमारे देश में साखे बनाएगी तो उन्हें भी फायदा होगा और भारत देश के लोगों को भी कम दाम में भी उत्पाद उपलब्ध हो सकेगा और साथ में लोगों को नौकरी एव रोजगार भी मिलेगा ।

- इस योजना के तहत देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा एवं विकास भी सुनिश्चित बनाया जा सकेगा।
- यह अभियान शुरू होने के बाद में भारत देश में तीव्रता से कई निवेशकों ने विनिर्माण, ऑटोमोबाइल, फार्मास्युटिकल, पर्यटन, रेलवे के क्षेत्र में निवेश किया है।
- इस अभियान के आरंभ के दिन बड़ी–बड़ी विदेशी कंपनिया और भारतीय कंपनी को इस अभियान का साथ देने के लिए आमंत्रित किया गया था।

मेक इन इंडिया अभियान के मुख्य उदेश्य

- इस योजना का मुख्य उदेश्य अधिक से अधिक उत्पादन भारत में हो और इससे उत्पादन की कीमत कम होगी और विदेशी निर्यात होने पर देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा।
- इस अभियान से देश में रोजगार बढ़ेगा और गरीबी कम होगी।
- इस योजना से यह महत्वपूर्ण फायदा होगा कि उच्च गुणवत्ता का सामान कम कीमत में आसानी से मिल जायेगा।
- विदेशी कंपनियां एवं उद्यमी यहाँ आकर पैसा लगाएंगे जिससे देश में बाहर से पैसा आएगा, साथ में भारत की पहचान भी एक तीव्र उभरते हुए देश के रुप में बलवती होगी।
- और इस योजना से देश युवा विदेश में जाकर रहना नहीं पसंद करेंगे यहाँ रहकर काम करना उचित मानेंगे ।

योजना का नाम Make In India
तिथि सितम्बर 25 2014
स्थान नई दिल्ली, भारत
वेबसाइट makeinindia.com

मेक इन इंडिया योजना से जुड़ीं कुछ बातें

- इस योजना ने देश–विदेश से सभी जगह के निवेशकों के लिए भारत देश में व्यापार करने के लिए सभी विकल्प रखे गए हैं और बड़ी–बड़ी कंपनिया भी इस योजना को अपना रही है।
- भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सरकार

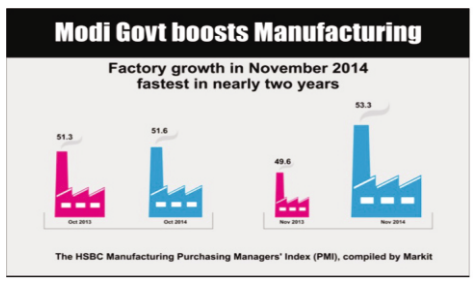

ने Make In India Campaign के लिए 25 सेक्टर का चुनाव किया है

- इसमें शामिल ऑटोमोबाइल, केमिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, आई टी क्षेत्र आदि।
- इस योजना के ज़रिये विश्व बैंक ने भारत में व्यापार के लिए देश के 17 शहरों में सर्वे किया था।
- जिसके अनुसार लुधियाना, हैदराबाद, भुवनेश्वर, गुड़गांव, अहमदाबाद टॉप 5 मुख्य शहर है जहां व्यापार बहुत आसानी से हो सकता है ।
- इस योजना का मुख्य मकसद Make In India को आगे बढ़ाना है।

भारत में मेक इन इंडिया की शुरुआत होने के बाद अगले ही साल भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। साल 2015 में भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में – 4.06 लाख करोड़ (US + 63 अरब डॉलर) प्राप्त हुए, जो

चीन से भी ज्यादा था ।

इलेक्ट्रॉनिक 2020 तक अमेरिका + 400 अरब के लिए तेजी से वृद्धि की उम्मीद हार्डवेयर के लिए मांग के साथ, भारत संभावित एक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण हब बनने की क्षमता है। सरकार ने एक स्तर के खेल मैदान बनाने और एक अनुकूल माहौल प्रदान करके 2020 तक इलेक्ट्रॉनिक्स का शुद्ध शून्य आयात को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।

क्षेत्र

'मेक इन इंडिया' अर्थव्यवस्था के पच्चीस क्षेत्रों पर

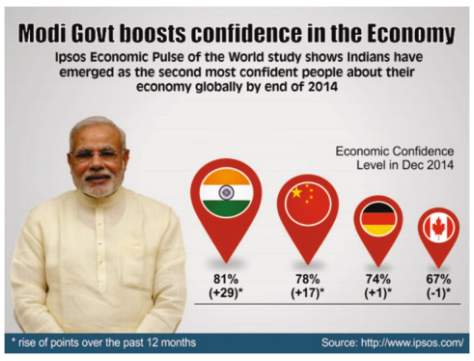

केंद्रित है:
गाडियां
ऑटोमोबाइल अवयव
विमानन
जैव प्रौद्योगिकी
रसायन
निर्माण
रक्षा विनिर्माण
इलेक्ट्रिकल मशीनरी
इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियाँ
खाद्य प्रसंस्करण
सूचना प्रौद्योगिकी और बिजनेस प्रोसेस प्रबंधन
चमड़ा
मीडिया और मनोरंजन
खनिज
तेल और गैस
फार्मास्यूटिकल्स

बंदरगाह और शिपिंग
रेलवे
नवीकरणीय ऊर्जा
सड़क और राजमार्ग
अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान
कपड़ा और परिधानों
तापीय उर्जा
पर्यटन और आतिथ्य
कल्याण

आसान नहीं है डगर

मेक इन इंडिया को मूर्त रूप देना आसान नहीं है। भारत ऐसा देश है है जहाँ बिना राजनीति के कुछ भी संभव नहीं है। अभी तक देश हित में जो भी काम हुए हैं वो देश के राजनीतिक दलों ने अपने फायदे के लिए किए हैं। भारत की राजनीति में स्वार्थीपन की पारदर्शिता है और राष्ट्रनीतियां अपारदर्शी है। आँखों के सामने कुछ और नजर आता है पर परदे के पीछे की हकीकत कुछ और ही बयान करती है। सड़कों के निर्माण से लेकर बांध के निर्माण तक, देश में हर मसले पर राजनीति का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। भूमि अधिग्रहण का विरोध और राज्य सरकारों की उदासीनता पुराने समय से ही देश के विकास की राह में बाधा रही हैं। ऐसे में मेक इन इंडिया जैसी युग परिवर्तक पहल अगर बिना वाद–विवाद के तय समय में मूर्त रूप ले सके तो इसे अजूबा ही माना जाएगा।

मजबूत होगी भारतीय अर्थव्यवस्था

मेक इन इंडिया के पूर्णयतया मूर्त रूप लेने से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। युवाओं को देश में रोजगार मिलेगा और विदेशी आयात में कमी आएगी। इससे भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा की बचत होगी और सरकारी कोष को मजबूती मिलेगी। रक्षा उत्पादों के देश में बनने के बाद रक्षा सौदों की लागत घटेगी और बिचौलियों से बचा जा सकेगा। कंपनियों से मिलने वाले करों से राज्य सरकार की आय बढ़ेगी और देश के हर भाग में रोजगार की उपलब्धता बढ़ेगी। भारतीय कंपनियों के उत्पादों की सीधी टक्कर अब विदेशी कंपनियों के उत्पादों से होगा और देश की जनता को इस प्रतिद्वंदिता का लाभ मिलेगा। रोजमर्रा के जरुरत की चीजों के दाम घटेंगे और गुणवत्ता बेहतर होगी। मेक इन इंडिया अगर अपने प्रस्तावित स्वरुप में जमीनी हकीकत में उतर पाता है तो यह भारत के लिए युग परिवर्तक पहल होगी और विश्व में भारत का दबदबा बढ़ेगा।

प्रतिक्रिया

25 सितम्बर, 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी। शुरुआत के बाद से ही यह पहल विश्वभर में चर्चा बटोरने लगी। भारत मजबूती से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और विश्वपटल पर तेजी से उभरता हुआ बाजार है। आज भारत की गिनती एशिया के अग्रणी देशों में होती है और आने वाले समय में वह विश्व की महाशक्ति बनकर उभरेगा। मोदी सरकार की इस पहल को विश्वभर से सकारात्मक प्रतिक्रिया और समर्थन मिला जिसकी बदौलत भारत ने वर्ष 2015 में अमेरिका और चीन सरीखे देशों को पछाड़ते हुए 63 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया। वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2014 के अक्टूबर महीने में भारत में 13 फीसदी अधिक जापानी कंपनियां रजिस्टर्ड हुई थी। नवंबर 2014 में भारत में फैक्ट्री विकास दर की रफ्तार अधिकतम रही थी।

भारत का पुराना सहयोगी रहा जापान अब भारत के प्रमुख सहयोगी देशों की सूची में अग्रणी स्थान पर काबिज हो चुका है। बुलेट ट्रेन परियोजना के अलावा कई जापानी कंपनियों ने भारत में निवेश करने में रूचि दिखाई और मेक इन इंडिया की सफलता में अपनी भागीदारी दी। मेक इन इंडिया की लॉन्चिंग के बाद अगले ही महीने में भारत में रजिस्टर्ड होने वाली जापानी कंपनियों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 13 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई थी। जापान तकनीकी रूप से दक्ष देश है उसकी गिनती विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में होती है। मेक इन इंडिया में जापानी निवेश निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ तकनीकी को सुधारने में भी कारगर होगा।

Sector	FDI Cap
Tobacco Products	0%
Real Estate/ Construction of Farm Houses	0%
Business-to-Consumer Ecommerce	0% *
Gambling, Lottery	0%
Nuclear Power	0%
News Publishing	26%
Insurance & Pensions	49% *
Pension Fund Management	49%
Defense	49% *
TV and Radio Terrestrial Broadcast	49%
Airlines	49% *
"Securities Infrastructure" (e.g., Stock Exchanges, Etc.)**	49%
Power Exchange	49%
Brick & Mortar Retail	51% *
Private Security Agencies	74%
Banking	74%

कहना ग़लत न होगा कि :- मेक इन इंडिया' - भारत को आर्थिक विश्वशक्ति बनाने में अहम् योजना है।

कदम दर कदम सफलता के फलक पर आईआईआरडी

करीब 14 साल पहले शिमला के संजौली से एक गैर सरकारी संस्था के तौर पर शुरुआत करने वाला , आईआईआरडी आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आईआईआरडी यानि एकीकृत ग्रामीण विकास संस्थान हिमाचल ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्य में अपनी एक विशेष पहचान बना चुका है। देश की नामी कंपनियों के साथ मिलकर आईआईआरडी देश के 21 राज्यों में विकास की गति को आगे ले जाने में अहम भूमिका निभा रहा है। आईआईआरडी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम भारत सरकार व विभिन्न प्रदेश सरकारों के साथ कई परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है। अगस्त 2018 में ही झारखंड में प्रोजेक्ट रुपांतरण के कार्यान्वयन के लिए संस्था को उत्कृष्ट संस्था के रुप में सम्मानित किया गया। आईआईआरडी राष्ट्रीय ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के साथ मिलकर विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहा है जो हिमाचल के लिए गौरव का विषय है। हाल ही में आईआईआरडी ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की ओर से पार्टनरशिप सर्टीफिकेट हासिल किया है। हिमाचल में मिशन रीव के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनके घर–द्वार पर विभिन्न सुविधाएं दी जा रही है।

आईआईआरडी और एनएसडीसी अब साथ–साथ

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की ओर से आईआईआरडी को कौशल विकास का प्रशिक्षण देने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। इसके लिए एनएसडीसी की ओर से प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया है। अब आईआईआरडी एनएसडीसी के साथ मिलकर कौशल विकास में अपना योगदान देगा।

प्रोजेक्ट रुपांतरण

आईआईआरडी ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि उस समय हासिल की जब आजीविका के क्षेत्र में उत्कृष्ट संस्था के रुप में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित एंव पुरस्कृत होने का गौरव प्राप्त हुआ। यह सम्मान सीएसआर टाइम्स के राष्ट्रीय सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह 2018 के उपलक्ष्य पर नई दिल्ली में आईआईआरडी टीम के साथ संस्था के प्रबन्ध निदेशक डॉ. एल.सी. शर्मा को केन्द्रिय पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अलफोंस के. जे. द्वारा प्रदान किया गया।

आईआईआरडी ने झारखण्ड के दूरदराज क्षेत्र में आवश्यकता आकलन करने के बाद 2017 में वहां की जनजातीय महिलाओं के लिए 12 विशेष पत्तल बनाने की मशीनों को लगाकर उनके पत्तल बनाने के कार्य को और भी आसान कर दिया। इससे न केवल उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ी बल्कि समय की बचत भी हुई। महिलाओं को पत्तल बनाने के साथ–साथ उनके भण्डारण, मार्केटिंग आदि का प्रशिक्षण भी दिया गया ।

पेयजल फिल्टर यूनिट

आईआईआरडी की ओर से कनार्टक के चिकबालापुर के आठ गांवों पेयजल से आयन को अलग करने के लिए ड्रिकिंग वाटर फिल्टर यूनिट लगाए गए और गांव के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया गया। इसके तहत हुलीकुंते गांव, नवोद्य विद्यालय और बाशीतिहली पंचायत में बोरवैल और आरओ प्लांट लगाए गए। इसके अलापा होशुदया, तिपापुर, विवेकानंद नगर, जिंकेबाचल मजराहोसहाली और चिकातुमुर गांव में भी आर ओर प्लांट लगाकर लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में आईआईआरडी ने अहम भूमिका निभाई है।

स्मार्ट क्लासरुम

शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पहल करते हुए आईआईआरडी ने कनार्टक के हुबली में 40 विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए हैं। इसमें कन्नड़ भाषा में सभी विषयों को डिजीटाइज किया गया। इसके साथ ही इंटरेक्टिव बोर्ड के माध्यम से इन विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई हो रही है। इस प्रयास से बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बच्चों के साथ अध्यापकों की अध्यापन क्षमता में भी प्रशंसनीय वृद्धि हुई है। अभी 40 और विद्यालयों को स्मार्ट क्लासेज में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जारी है।

कुल्लू में बाला कांन्सेप्ट के साथ स्कूल निमार्ण

हिमाचल के कुल्लू जिला में मनाली के ब्लॉक नग्गर की ग्राम पंचायत हालम में राजकीय प्राथमिक पाठशाला सरसई के स्कूल भवन का निर्माण किया गया। स्कूल के लिए दो मंजिला भवन का निर्माण किया गया। इस भवन में बाला कांन्सेप्ट के साथ प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए आकर्षक मॉडल बनाए गए ताकि बच्चे खेल–खेल में पढ़ना सीख सके। इसके अलावा इस स्कूल में छात्रों के मनोरंजन के लिए भी ऐसे मॉडल बनाए गए हैं जिसमे मनोरंजन के साथ बच्चों की बौद्धिक क्षमता का भी विकास हो सके।

आईआईआरडी द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाएं

प्रोजेक्ट	राज्य
रूपांतरण	झारखण्ड
पेयजल फिल्टर यूनिट	कर्नाटक
स्मार्ट क्लासरूम	कर्नाटक
प्रोजेक्ट जनऔषधि केंद्र	हिमाचल प्रदेश
कोल बांध समाजिक प्रभाव मूल्यांकन	हिमाचल प्रदेश
कुल्लू में बाला कांन्सेप्ट के साथ स्कूल निमार्ण	हिमाचल प्रदेश
आईपीडी शोली सोलर लाइट	हिमाचल प्रदेश
बहुउद्देशिय इंडोर स्टेडियम	कर्नाटक
शौचालय निर्माण	बिहार, कर्नाटक
बंगलुरू में स्टील बिन इंस्टालेशन	कर्नाटक
समुदाय सहभागिता कार्यक्रम	आसाम
कौशल विकास कार्यक्रम	उत्तर प्रदेश
डीडीयू –जीकेवाई	उत्तर प्रदेश
शिमला में कौशल विकास कार्यक्रम	हिमाचल प्रदेश
बहुउद्देशिय इंडोर स्टेडियम	उड़ीसा

बिहार और कर्नाटक में शौचालय निर्माण

आईआईआरडी कनार्टक और उड़ीसा में सार्वजनिक शौचलय निर्माण प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत बिहार के ईस्ट चंपाराण और कर्नाटक के चित्रदुर्ग और तुमकुर जिले में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर शौचालयों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

बंगलुरु में स्टील कूड़ेदान लगाने का कार्य

आईआरडी कनार्टक की राजधानी बंगलुरू में विभिन्न स्थानों पर स्टील बिन यानि स्टील से बने कूड़ेदान लगाने का कार्य कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 10 हजार स्टील बिन लगाने का कार्य आईआईआरडी कर रहा है। इसके अलावा भी आईआईआडी कनार्टक के अन्य स्थानो पर विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर कार्य कर रहा है।

डीडीयू –जीकेवाई यूपी

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत आईआईआरडी द्वारा यूपी के चंदोली और कासगंज केंद्रो पर 380 अभ्यर्थियों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन अभ्यर्थियों को जरदोजी वर्क का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें सोने और चांदी से की जाने वाली कढ़ाई का प्रशिक्षण भी शामिल है। इसके पूरा होते ही इन अभ्यर्थियों की प्लेसमेंट भी कौशल के आधार पर आईआईआरडी की ओर से की जाती है।

उत्तराखंड में पीएमकेवाई

पीएमकेवाई प्रोजेक्ट के तहत हरिद्वार और पौड़ी में आईआईआरडी कंप्यूटर और सिलाई मशीन ट्रेड्स में प्रशिक्षण दे रहा है।

शिमला में कौशल विकास कार्यक्रम

जिला शिमला में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के कौशल विकास कार्यक्रम के तहत पांच केंद्रों पर कौशल विकास का प्रशिक्षण देने के लिए आईआईआरडी को अधिकृत किया गया है। इनमें शनान, रोहड़ू, कुमारसैन, ननखड़ी (शोली) और सुन्नी शामिल है।

उड़ीसा में बहुउद्देशिय इंडोर स्टेडियम

उड़ीसा के बरूनी में पीआर हाई स्कूल फील्ड में भी आईआईआरडी की ओर से एक बहुउदेशिय इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है, यह स्टेडियम अति आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा।

कोल बांध सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन

आईआईआरडी की ओर से कोल डैम प्रोजेक्ट के प्रभाव को लेकर मूल्यांकन का कार्य किया जा रहा है। आईआईआरडी द्वारा हिमाचल के उन चार जिलों में इस प्रोजेक्ट के समाजिक प्रभाव का मूल्यांकन किया जा रहा है जो इस प्रोजेक्ट के दायरे में आ रहे हैं। इसमें शिमला, सोलन, बिलासपुर और मंडी शामिल है।

आईपीडी शोली सोलर लाइट

शिमला में रामपुर के तहत आने वाली शोली पंचायत प्रदेश की ऐसी पहली पंचायत है जहां पर सौ फीसदी सोलर लाइट्स की व्यवस्था की गई है। एकीकृत पंचायत विकास शोली प्रोजेक्ट के तहत आईआईआरडी ने शोली पंचायत में 350 सोलर लाइट्स लगाई है। इन लाइट्स की देखभाल का जिम्मा भी आईआईआरडी ही संभाल रहा है।

कर्नाटक में बहुउद्देशिय इंडोर स्टेडियम

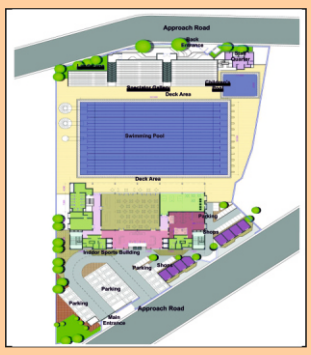

आईआईआरडी हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि प्रदेश के बाहर दूसरे राज्य मेंभी अपनी विशेष पहचान बना चुका है। यही कारण है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी आईआईआरडी के साथ मिलकर काम करने के लिए आगे आ रही है। इसका ताजा उदाहरण आईआईआरडी की ओर से बनाया जा रहा बहुउद्देशिय इंडोर स्टेडियम है। जो कर्नाटक के धारवाड़ में बनाया जा रहा है। इसके लिए सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है और निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस कांपलैक्स में युवाओं और अन्य आयुवर्ग के लिए विभिन्न खेल गतिविधियों की सुविधा होगी और साथ ही फिट रहने के लिए जिम और अन्य अत्याधुनिक तकनीक से लैस उपकरण भी होंगे। इस बहुउद्देशिय इंडोर स्टेडियम का शिलान्यास पैट्रालियम एवं प्राकृतिक गैस स्थाई संसदीय समिति के अध्यक्ष प्रह्लाद जोशी ने अक्तूबर 2018 में किया।

आसाम में समुदाय सहभागिता कार्यक्रम

आसाम में समुदाय सहभागिता कार्यक्रम के तहत आईआईआरडी प्रदेश के आठ जिलों में इस प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम में इन आठ जिलों के लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने और विभिन्न योजनाओं के सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन को लेकर कार्य किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में कौशल विकास कार्यक्रम

भारत सरकार की कौशल विकास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में विभिन्न केंद्रों पर आईआईआरडी अलग–अलग ट्रेड्स में कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर अभ्यर्थियों को रोजगार से भी जोड़ रहा है। इन केंद्रों में यूपी के चंदोली, कासगंज, गोरखपुर, महाराजगंज, दिओरिया और खुशीनगर केंद्र शामिल है।

प्रोजेक्ट जनऔषधि केंद्र

आईआईआरडी को बीपीपीआई की ओर से तीन सौ जनऔषधि केंद्र खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल के विभिन्न हिस्सों में जनऔषधि केंद्र खोले जा रहे हैं। इन केंद्रों को ऐसे स्थानों पर खोला जा रहा है जहां पर ग्रामीण लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। जनऔषधि केंद्रों पर लोगों को बेहद सस्ते दामों पर दवाईयों की उपलब्धता आईआईआरडी की ओर सुनिश्चित करवाई जा रही है। जनऔषधि केंद्र खुलने से इलाज काफी सस्ता हो गया। इससे पहले लोगों के पास सस्ती दवाईयों का कोई विकल्प नहीं था और उन्हें मजबूरन महंगी दवाईयां खरीदनी पड़ती थी। लेकिन आईआईआरडी की ओर से खोले जा रहे जनऔषधि केंद्रों पर उच्च गुणवत्ता की दवाईयां लोगों को सस्ते दामों पर उपलब्ध हो रही है। हिमाचल में अभी तक शिमला, कुल्लू , मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर में विभिन्न स्थानों पर जनऔषधि केंद्र खोले जा चुके हैं और जल्द ही अन्य जिलों में भी जनऔषधि केंद्र खोले जाएंगे।